



ENGINEERS ACADEMY®
Your GATEway to Professional Excellence
IES • GATE • PSUs • JTO • IAS • NET

NIMBUS
-Ye Hai Future Ki Taiyari-



Monthly
CURRENT AFFAIRS
BY ENGINEERS ACADEMY

Jul-2026

SSC-JE | RRB-JE | STATE-JE | STATE-AE | PSUS AND OTHER TECHNICAL EXAMS

राष्ट्रीय सुर्खियाँ

- आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ा
- जस्टिस मीनाक्षी राय बनीं पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश
- डी.के. शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री
- निशानेबाजी के दिग्गज जसपाल राणा का निधन
- PoK विरोध प्रदर्शन चर्चा में

वैश्विक सुर्खियाँ

- ब्रिक्स ने अपनाई इंदौर घोषणा
- फ्रांस में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी
- इथियोपिया बना WTO का सदस्य
- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दिया इस्तीफा
- खार्ग द्वीप चर्चा में

पुरस्कार और रैंक

- नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
- जैनेंद्र के. जैन को वुल्फ पुरस्कार
- वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए
- प्रज्ञानानंदा ने रचा शतरंज इतिहास
- RCB ने बरकरार रखा IPL खिताब

अमेरिका-ईरान

के बीच 14-सूत्रीय शांति समझौता

ऐतिहासिक उपलब्धि

एलन मस्क
बने दुनिया के पहले
ट्रिलियनेयर

मोदी बने

सबसे लंबे समय तक सेवा देने
वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री

IIP, CPI और GDP का
नया आधार वर्ष

ENGINEERS ACADEMY
All Copyright Reserved

Contact Info

Phone No: +91 8094441777

Mail: engineers.academy.india@gmail.com

Website: www.engineersacademy.org



अस्वीकरण

यह पुस्तक केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है।



लेखक/लेखकों द्वारा यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया है कि किसी भी वर्तमान कॉपीराइट या बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन न हो। यदि अनजाने में किसी स्रोत का उल्लेख छूट गया हो या कोई अनिच्छित उल्लंघन हुआ हो, तो कृपया प्रकाशक को लिखित रूप में सूचित करें, ताकि आवश्यक सुधारात्मक कदम शीघ्रता से उठाए जा सकें।



यद्यपि सामग्री की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए इसका सावधानीपूर्वक परीक्षण किया गया है, फिर भी अनजाने में कुछ त्रुटियाँ या चूक रह सकती हैं। पहचानी गई किसी भी विसंगति को आगामी संस्करणों में सुधारा जाएगा। प्रदान की गई जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से होने वाली किसी भी हानि, नुकसान या परिणाम के लिए लेखक/लेखकगण, प्रकाशक और वितरक उत्तरदायी नहीं होंगे। पाठकों को कानूनी, तथ्यात्मक या महत्वपूर्ण विवरणों की पुष्टि के लिए आधिकारिक स्रोतों से परामर्श करने की सलाह दी जाती है।



बाइंडिंग की खराबी, छपाई की त्रुटि या पृष्ठों के गायब होने जैसी समस्याओं की स्थिति में, प्रकाशक की जिम्मेदारी केवल दोषपूर्ण प्रति को उसी या समकक्ष संस्करण से बदलने तक सीमित होगी। प्रतिस्थापन के लिए अनुरोध खरीद की तिथि से सात दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तथा शिपिंग सहित सभी संबंधित खर्च खरीदार द्वारा वहन किए जाएंगे।



सर्वाधिकार सुरक्षित

इस प्रकाशन का कोई भी भाग प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में—इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोग्राफिक या अन्यथा—पुनरुत्पादित, संग्रहित या प्रसारित नहीं किया जा सकता। अनधिकृत उपयोग, पुनरुत्पादन या वितरण पर कानूनी कार्यवाई की जा सकती है।

इस कृति की मूल सामग्री पर लेखक के पूर्ण अधिकार सुरक्षित हैं, सिवाय उन स्थानों के जहाँ उचित अनुमति के साथ विशिष्ट उद्धरण दिए गए हैं। यह प्रकाशन किसी भी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गोपनीयता कानून का उल्लंघन नहीं करता और न ही इसमें कोई मानहानिकारक सामग्री शामिल है।

प्रिय अभ्यर्थियों

“

“सफलता कभी-कभी किए गए प्रयासों से नहीं, बल्कि निरंतर तैयारी, अनुशासित अध्ययन और आगे बढ़ते रहने के साहस से प्राप्त होती है।”



करंट अफेयर्स लगभग हर सामान्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का आधार हैं, चाहे वह बैंकिंग, SSC, राज्य स्तरीय परीक्षाएँ, रेलवे, रक्षा या अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाएँ हों। करंट अफेयर्स पढ़ने की नियमित आदत न केवल सामान्य जागरूकता को मजबूत करती है, बल्कि विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता और परीक्षा कक्ष में आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। प्रत्येक गंभीर अभ्यर्थी के लिए अपडेट रहना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है।

यह मासिक करंट अफेयर्स पत्रिका अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का स्पष्ट, परीक्षा-उन्मुख और संक्षिप्त रूप में पुनरावलोकन कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस अंक में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ का सेना प्रमुख बनना, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित का वाइस एयर चीफ नियुक्त होना, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालना, RBI उप-गवर्नर को सेवा विस्तार मिलना, न्यायमूर्ति मीनाक्षी राय का पटना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनना और डी.के. शिवकुमार का कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालना जैसे महत्वपूर्ण नियुक्ति एवं नेतृत्व परिवर्तन शामिल हैं।

इस अंक में प्रमुख राष्ट्रीय और वैश्विक घटनाओं को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है, जैसे मोदी का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनना, BRICS द्वारा इंदौर घोषणा-पत्र को अपनाना, फ्रांस द्वारा 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, अमेरिका-ईरान 14-सूत्रीय शांति समझौता, इथियोपिया का WTO में शामिल होना, IIP, CPI और GDP के लिए नया आधार वर्ष, यूक्रेन-स्वीडन रक्षा संबंधों की मजबूती, खार्ग द्वीप का चर्चा में आना और PoK विरोध प्रदर्शनों की व्याख्या। रक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट, जैसे SIPRI के अनुसार भारत के परमाणु शस्त्रागार का विस्तार, रुद्रम-II मिसाइल का सफल परीक्षण और पहला स्वदेशी तटरक्षक होवरक्राफ्ट भी इस अंक में शामिल किए गए हैं।

अभ्यर्थियों को इस अंक में पुरस्कार, खेल और व्यक्तित्व आधारित महत्वपूर्ण खबरें भी मिलेंगी, जिनमें नीरज और पारुल का एथलीट्स ऑफ द ईयर चुना जाना, जैनेंद्र के. जैन को वुल्फ पुरस्कार मिलना, वीरता पुरस्कारों का प्रदान किया जाना, प्रज्ञानानंदा द्वारा शतरंज इतिहास रचना, RCB द्वारा IPL 2026 का खिताब बरकरार रखना और भारतीय शूटिंग दिग्गज जसपाल राणा का निधन शामिल हैं। व्यापक सामान्य जागरूकता के लिए UK प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का इस्तीफा और एलन मस्क का पहले ट्रिलियनेयर बनना जैसी वैश्विक व्यक्तित्व एवं प्रमुख घटनाएँ भी सम्मिलित की गई हैं।

यह पत्रिका केवल खबरों का संग्रह नहीं, बल्कि भविष्य के राष्ट्र निर्माताओं के लिए एक सशक्त तैयारी साधन है। नियमित पढ़ें, समझदारी से पुनरावृत्ति करें और प्रत्येक घटना को उसकी परीक्षा-प्रासंगिकता से जोड़कर देखें। समर्पण, अनुशासन और सही अध्ययन सामग्री के साथ हर अभ्यर्थी सफलता के और करीब पहुँच सकता है।

इस संस्करण में शामिल हैं

1. पुस्तकें एवं लेखक	5
2. क्विक बाईट्स	7
3. नव नियुक्तियां	11
4. राष्ट्रीय समाचार	22
5. अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ	27
6. बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था	30
7. हस्ताक्षरित समझौते एवं एमओयू	34
8. पुरस्कार एवं सम्मान	41
9. खेल-कूद	45
10. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	49
11. निधन	54
12. विविध घटनाएँ	59
13. माह के सैन्य अभ्यास	61
14. माह के महत्वपूर्ण दिन	62
15. माह के महत्वपूर्ण घटनाक्रम	63



समाचार स्रोत

बीबीसी, रॉयटर्स, अल जज़ीरा, पीआईबी, पीटीआई, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, इंडिया टुडे, मनी कंट्रोल एवं अन्य सभी प्रमुख समाचार पत्र.....

समाचार कवरेज

बिजनेस न्यूज, फाइनेंशियल न्यूज, इकोनॉमी न्यूज, पॉलिटिक्स न्यूज, इंडिया न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज एवं कई अन्य विषयों को कवर किया गया



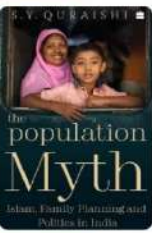
पुस्तकें एवं लेखक



पुस्तक: अपनापन: नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव

लेखक: शिवराज सिंह चौहान

बारे में: यह पुस्तक शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक जीवन, प्रशासनिक अनुभवों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके लंबे संबंधों पर आधारित संस्मरण है। इसमें नेतृत्व, जनसेवा और शासन से जुड़े अनुभवों का वर्णन किया गया है।



पुस्तक: द पॉपुलेशन मिथ: इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया

लेखक: एस. वाई. कुरैशी

बारे में: यह पुस्तक भारत में जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन और धर्म से जुड़े विभिन्न मिथकों का विश्लेषण करती है। लेखक ने तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से जनसांख्यिकीय मुद्दों पर प्रकाश डाला है।



पुस्तक: अनस्क्रिप्टेड: कन्वर्सेशन्स ऑन लाइफ एंड सिनेमा

लेखक: विधु विनोद चोपड़ा एवं अभिजात जोशी

बारे में: यह पुस्तक भारतीय सिनेमा की दुनिया, रचनात्मक प्रक्रिया, फिल्म निर्माण की चुनौतियों और लेखक-द्वय के व्यक्तिगत अनुभवों को संवादात्मक शैली में प्रस्तुत करती है।



पुस्तक: मेकिंग ऑफ ए जनरल – ए हिमालयन इको

लेखक: कोनसम हिमालय सिंह

बारे में: यह आत्मकथात्मक पुस्तक भारतीय सेना में लेखक की यात्रा, सैन्य नेतृत्व, रणनीतिक सोच और देशसेवा के दौरान प्राप्त अनुभवों का विस्तृत वर्णन करती है।

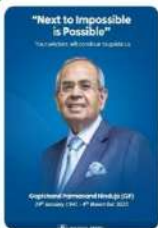


पुस्तक: गेजिंग ईस्टवर्ड्स: ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज़ इन चाइना, 1957

लेखक: रोमिला थापर

बारे में: यह पुस्तक 1957 में चीन की यात्रा के दौरान लेखक के अनुभवों, वहां की संस्कृति, इतिहास, राजनीति और बौद्ध परंपराओं के अवलोकन को प्रस्तुत करती है।

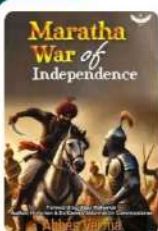
पुस्तकें एवं लेखक



पुस्तक: आई एम

लेखक: गोपीचंद पी. हिंदुजा

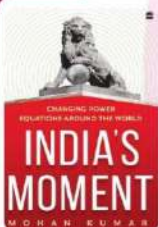
बारे में: यह पुस्तक लेखक के जीवन-दर्शन, व्यापारिक अनुभवों, आध्यात्मिक विचारों और सफलता के सिद्धांतों को साझा करती है। इसमें नेतृत्व और नैतिक मूल्यों पर भी चर्चा की गई है।



पुस्तक: मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस

लेखक: आभास वर्मा

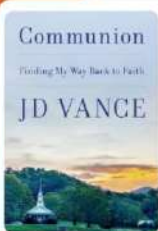
बारे में: यह पुस्तक मुगल साम्राज्य के विरुद्ध मराठाओं के संघर्ष, उनकी सैन्य रणनीतियों और स्वतंत्रता की रक्षा में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करती है।



पुस्तक: इंडियाज़ मोमेंट: चेंजिंग पावर इक्वेशन्स अराउंड द वर्ल्ड

लेखक: मोहन कुमार

बारे में: यह पुस्तक वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, विदेश नीति और बदलते शक्ति संतुलन का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।



पुस्तक: कम्युनियन: फाइंडिंग माई वे बैक टू फेथ

लेखक: जे. डी. वेंस

बारे में: यह एक व्यक्तिगत संस्मरण है जिसमें लेखक ने अपनी आध्यात्मिक खोज, धार्मिक विश्वासों और जीवन में आस्था की पुनः प्राप्ति की यात्रा का वर्णन किया है।



पुस्तक: रिजीम चेंज: इनसाइड द इंपीरियल प्रेसीडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप

लेखक: मैगी हैबरमैन एवं जोनाथन स्वान

बारे में: यह पुस्तक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल, उनकी नीतियों, निर्णय लेने की शैली, राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है।

क्विक बाइट्स

- वाइस एडमिरल संजय वत्स्यायन ने पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला
- एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारत के 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला
- जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण किया
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनल में गुजरात टाइटन्स को हराकर IPL खिताब का बचाव किया
- IPL 2026 पुरस्कार: वैभव सूर्यवंशी ने MVP और ऑरेंज कैप का सम्मान जीता
- सात्विक-चिराग सिंगापुर ओपन पुरुष युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बने
- वयोवृद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की आयु में निधन
- शिवराज सिंह चौहान ने पूरे भारत में मिट्टी संरक्षण और टिकाऊ खेती के लिए 'खेत बचाओ अभियान' शुरू किया
- भविष्य मंडावा 'फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026' में पहली भारतीय चैनल एम्बेसडर बनीं
- Meesho और BSE ने MSMEs को पूंजी बाजारों तक पहुँचने में मदद करने के लिए 'प्रोजेक्ट शिखर' लॉन्च किया
- भारतीय शिक्षिका सोमा मंडल ने 'ग्लोबल कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026' जीता
- तमिलनाडु के किसान वल्लुवन को UN FAO द्वारा 'मृदा किसान नायक' (Soil Farmer Hero) के रूप में सम्मानित किया गया
- एयर मार्शल तरुण चौधरी ने 'केंद्रीय वायु कमान' के प्रमुख का कार्यभार संभाला
- वाइस एडमिरल विनीत मैक्कार्थी ने 'अंडमान और निकोबार कमान' के प्रमुख का कार्यभार संभाला
- ICC ने शासन और अनुपालन नियमों के उल्लंघन के कारण 'क्रिकेट कनाडा' की सदस्यता निलंबित कर दी
- RBI ने Fino Payments Bank के अंतरिम CEO के तौर पर Ketan Merchant का कार्यकाल बढ़ाया
- भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी ने उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों का उपयोग करके 12.6 अरब वर्ष पुराने Loktak Galaxy Protocluster की खोज की
- पांच बार के ओलंपियन और IOC के पूर्व सदस्य Raja Randhir Singh का निधन
- P.T. Usha ने इतिहासकार K. Arumugam की किताब 'India's First Olympic Gold' लॉन्च की
- IIT Madras ने Fibrosis और Degenerative बीमारियों के इलाज के लिए कम लागत वाला Injectable Hydrogel विकसित किया
- भारतीय मूल के किशोर Shrey Parikh ने 2026 का Scripps National Spelling Bee खिताब जीता
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पहले अध्यक्ष Dhanendra Kumar का निधन
- Odisha ने Intel और 3D Glass Solutions के साथ Semiconductor निर्माण समझौता किया
- Russia, \$16.5 अरब के समझौते के तहत Kazakhstan का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएगा
- जय प्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के शामिल होने से भारत में रामसर साइट्स की संख्या 100 हुई
- J&K बैंक ने AI एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के लिए फिनाकल इनोवेशन अवार्ड्स में गोल्ड जीता
- नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया
- एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को अगला वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त किया गया
- लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी. कश्यप का 97 साल की उम्र में निधन
- अर्जुन अवार्ड बलविंदर सिंह धालीवाल का 67 साल की उम्र में निधन
- प्रसिद्ध ओडिया लेखक और पूर्व IAS अधिकारी जगन्नाथ प्रसाद दास का 90 साल की उम्र में निधन
- 'पर्सपोलिस' की क्रिएटर मरजाने सतरापी का 56 साल की उम्र में निधन
- क्लाइमेट एक्शन और प्रकृति संरक्षण पर फोकस के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2026 मनाया गया
- RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ाया गया
- तरुण कपूर को PM मोदी के सलाहकार के तौर पर एक साल का एक्सटेंशन मिला
- UIDAI प्रमुख सौरभ विजय ने IndiaAI मिशन के CEO का पद संभाला
- पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ने नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड्स 2026 में गोल्ड जीता
- प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने
- मलयालम कवि ए.सी. श्रीहरि का 56 साल की उम्र में निधन
- केरल ने भारत का पहला न्यायपालिका-एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम 'HAWK' लॉन्च किया
- पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत PM-JAY में शामिल हुआ, 36वां लागू करने वाला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बना
- SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ाकर 190 वॉरहेड किया
- भारत ने जापान को हराकर पुरुष U18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता
- भारत ने SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 जीती, रिकॉर्ड छठा खिताब अपने नाम किया

- किमी एंटोनेली ने मोनाको ग्रां प्री 2026 जीतकर चैंपियनशिप में अपनी बढ़त बढ़ाई
- ज्वेरेव और एंड्रीवा ने ऐतिहासिक फ्रेंच ओपन 2026 सिंगल्स खिताब जीते
- राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता सलीम कुमार का 56 साल की उम्र में निधन
- APEDA ने झारखंड से UK को ताज़े आम्रपाली आमों के पहले निर्यात में मदद की
- कुमार शंकर को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया
- बनवारीलाल पुरोहित भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष चुने गए
- लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज प्रशर को 'ऑपरेशन चुनतावाड़ी' में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया
- इंदौर ने खाद्य सुरक्षा और स्मार्ट खेती पर 'ब्रिक्स (BRICS) कृषि बैठक 2026' की मेज़बानी की
- PM मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बने
- APEDA ने असम से दुर्बई तक GI-टैग वाली तेजपुर लीची के पहले निर्यात में मदद की
- अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए LPMS 'विनिमय' (VINIMAY) लॉन्च किया
- उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण इलाकों में हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा बढ़ाने के लिए 'प्रोजेक्ट गंगा' लॉन्च किया
- APSEZ ने अर्जेंटीना के LNG एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 10 साल का मरीन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जीता
- सरकार ने VB-G RAM G ग्रामीण रोजगार योजना के लिए ₹95,692 करोड़ के फंड की घोषणा की
- Rapido ने 'राहवीर' (Rahveer) योजना के जरिए सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए MoRTH के साथ साझेदारी की
- सविता श्री भास्कर ने एशियन महिला शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता
- नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले डायरेक्टर भरथिराजा का 84 साल की उम्र में निधन
- 'ऑपरेशन मिलाप' से गुजरात पुलिस ने एक महीने में 1,470 लापता लोगों का पता लगाया
- राष्ट्रपति ने पावर सेक्टर की फाइनेंसिंग को मजबूत करने के लिए REC-PFC के विलय को मंजूरी दी
- भारत ने कोटे डी आइवर और साओ टोम एंड प्रिंसिपे के लिए नए राजदूत नियुक्त किए
- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी GNSS जैमर के लिए ₹449 करोड़ का समझौता किया
- AIIMS और ICMR ने सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए स्वदेशी HPV स्क्रीनिंग टेस्ट को मंजूरी दी
- ICAR ने तिलहन किसानों के लिए भारत की पहली WhatsApp AI एडवाइजरी 'ऑयलसीड्स किसान मित्र' लॉन्च की
- डोनाल्ड ट्रंप ने जे क्लेटन को अगला US इंटेलिजेंस चीफ नामित किया
- भारत और नेपाल ने UPI-NPI क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस सेवा शुरू की
- रुद्र गौरव श्रेष्ठ तुर्की में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए
- आइसलैंड ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है
- US ने लगातार अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के लिए SOLAR-1 सैटेलाइट सक्रिय किया
- IIT भुवनेश्वर ने पानी में आर्सेनिक का तेज़ी से पता लगाने के लिए 'ArsenSafe' डिवाइस विकसित किया
- जापान ने कम लागत वाला H3-30 रॉकेट लॉन्च किया ताकि कमर्शियल स्पेस मिशन को मजबूत किया जा सके
- भारतीय शूटिंग दिग्गज जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया
- SpaceX में उछाल के बाद एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बने
- संजय लोहिया RBI और SBI के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर नियुक्त
- राष्ट्रपति ने REC लिमिटेड के पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में विलय को मंजूरी दी
- मेड-इन-इंडिया C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी की
- ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026: आइसलैंड टॉप पर बरकरार, भारत 127वें स्थान पर
- भारतीय रेलवे ने RPF कर्मियों के लिए GPS-इनेबल्ड बॉडी कैमरे शुरू किए
- सुदर्शन पटनायक ने रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब जीता
- ग्लोबल डिजिटल वॉलेट डाउनलोड में भारत सबसे आगे; PhonePe दुनिया भर में सबसे आगे
- BRICS ने कृषि सहयोग और खाद्य सुरक्षा के लिए इंदौर घोषणा को अपनाया
- लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया
- डॉ. पी. एल. गौतम NBA एग्रोबायोडायवर्सिटी कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त
- इंडिया पोस्ट ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन-आधारित मेल डिलीवरी सेवा शुरू की
- जाने-माने अमेरिकी क्रिटिक जीन शालिट का 100 साल की उम्र में निधन
- झारखंड के भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क और मुंडा ज्वेलरी को GI टैग मिला
- ओडिशा ने KG से PG तक मुफ्त शिक्षा और CM अन्नपूर्णा योजना शुरू की
- CBRE ने ETNow रियल्टी अवार्ड्स में 'लीडिंग IPC ऑफ़ द ईयर' का अवार्ड जीता
- नोवार्टिस ने प्रोस्टेट कैंसर के लिए भारत की पहली रेडियोलिगेण्ड थेरेपी शुरू की
- पंकज त्रिपाठी MBG कार्ड के ब्रांड एंबेसडर बने

- केरल ने महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की
- UP ने ₹5 लाख की मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की
- भारतीय सेना ने नई यूनिफॉर्म कोड के तहत 'बंदी जैकेट' पेश की
- भारतीय सेना ने नेगेव लाइट मशीन गन के लिए MEPRO X6 साइट्स चुनीं
- स्विस् वोटर्स ने आबादी को 1 करोड़ (10 मिलियन) तक सीमित करने का प्रस्ताव ठुकराया
- पीएम मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस' मिला
- भारत और जापान ने पेरिस समझौते के तहत 'जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म' के नियमों को अपनाया
- स्मृति मंधाना TIME के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बनीं
- सरप्रीत सिंह FIFA वर्ल्ड कप मैच में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी बने
- स्कॉटलैंड में पहली बार अफ्रीकी मूल के 'उसुटु वायरस' का पता चला
- भारतीय नौसेना ने 'सी किंग 42B' हेलीकॉप्टर स्काइन INAS 330 को सेवामुक्त किया
- अरुणव दास को InCred कैपिटल नॉर्थ अमेरिका का CEO नियुक्त किया गया
- ASI और डेनमार्क ने ओरेसुंड जहाज़ के मलबे के अंडरवाटर सर्वे के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए
- भारतीय सेना को SMPP से 106 पीसकीपर अग्निवेद कामिकेज़ ड्रोन मिले
- दीप्ति शर्मा ने झूलन गोस्वामी के 355 इंटरनेशनल विकेट के रिकॉर्ड की बराबरी की
- QS रैंकिंग 2027 में IIT दिल्ली भारत की सबसे ऊंची रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी बनी
- INST मोहाली ने एडवांस्ड ज़िंक-आयन बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव विकसित किया
- सैबल चट्टोपाध्याय नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरपर्सन नियुक्त किए गए
- ब्रिक्स कृषि मंत्रियों ने इंदौर में 16वीं बैठक में 'इंदौर घोषणापत्र' को अपनाया
- WEF एनर्जी ट्रांज़िशन इंडेक्स 2026 में भारत 70वें स्थान पर रहा
- RBI ने HDFC बैंक के अंतरिम चेयरमैन के तौर पर केकी मिस्त्री का कार्यकाल बढ़ाया
- RBI ने श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस रद्द किया
- भारतीय न्यायविद बिमल एन. पटेल 2026-2035 के कार्यकाल के लिए ITLOS जज चुने गए
- वैज्ञानिकों ने मेघालय में लिंक्स स्पाइडर की नई प्रजाति 'हमातालियावा मावलिंगोट' (Hamataliwa mawlyngot) की खोज की
- देव कुमार मीणा ने रांची में 5.45 मीटर का राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड बनाया, जो पिछले 5.41 मीटर के रिकॉर्ड से ज़्यादा है।
- चीन ने शेनझोउ-23 मिशन लॉन्च किया; अंतरिक्ष यात्री 365 दिन कक्षा में बिताएगा, जो चीन का अब तक का सबसे लंबा मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रयास है।
- मेजर अभिलाषा बराक ने लेबनान मिशन में शांति स्थापना सेवाओं के लिए 2025 का UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड जीता।
- ओडिशा ने गंजाम में 'बोमकाई बुनाई पुनरुद्धार परियोजना' शुरू की, जिसका उद्देश्य GI-टैग वाली पारंपरिक सूती हथकरघा विरासत को संरक्षित करना है।
- Fintech ऐप jUMPP को स्वास्थ्य, जीवन, मोटर और गृह बीमा उत्पादों को बेचने के लिए IRDAI से लाइसेंस मिल गया है।
- NCB प्रमुख अनुराग गर्ग का कार्यकाल जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे वे नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व जारी रखेंगे।
- उपराष्ट्रपति ने केरल में पुस्तकालय आंदोलन के प्रणेता पी.एन. पैनिकर पर लिखी पुस्तक "The Library Man of India" का विमोचन किया।
- RBI ने ICICI बैंक के CEO संदीप बख्शी की दो साल के लिए, यानी अक्टूबर 2028 तक, पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
- भारत और कनाडा ने CEPA वार्ता को तेज़ किया, जिसका लक्ष्य 2030 तक \$50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार और मज़बूत आर्थिक सहयोग हासिल करना है।
- भारतीय वैज्ञानिकों ने 'CLEAR' तकनीक विकसित की है, जो सटीक चिकित्सा और रोग अनुसंधान के लिए उन्नत मल्टी-प्रोटीन इमेजिंग को संभव बनाती है।
- शिवराज सिंह चौहान ने 'अपनापन' पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत अनुभवों और राजनीतिक यात्रा को उजागर किया गया है।
- भारतीय सेना ने AI-आधारित निर्णय लेने और सैन्य लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए 'कौटिल्य' और 'Q-FORCE' प्लेटफॉर्म लॉन्च किए।
- भारत ने दा नांग में आयोजित एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप के पुरुषों के फ्रीस्टाइल मुकाबलों में दो स्वर्ण पदक जीते।
- भारत ने पहले BRICS पर्यटन कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें AI, स्थिरता और निर्बाध यात्रा सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया।
- सामाजिक न्याय मंत्रालय ने कल्याणकारी योजनाओं की डिजिटल निगरानी के लिए 'PM-AJAY' पोर्टल और ऐप लॉन्च किया।
- CSIR-NIScPR और NIAS ने विज्ञान संचार, अनुसंधान सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- ONGC ने लद्दाख की पुगा घाटी में भारत की पहली वाणिज्यिक भू-तापीय (Geothermal) ऊर्जा परियोजना का विकास कार्य शुरू किया।
- डाक विभाग ने 'इंडिया पोस्ट' नेटवर्क के माध्यम से 'लास्ट-माइल डिलीवरी' सेवाओं का विस्तार करने के लिए Flipkart के साथ साझेदारी की है।
- RBI ने नए शासन (Governance) संबंधी नियम लागू किए हैं, जिनके तहत शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों का लगातार कार्यकाल दस वर्षों तक सीमित कर दिया गया है।
- गुजरात ने 'लिटिल रन ऑफ़ कच्छ' में वन्यजीवों को पानी उपलब्ध कराने के लिए 'जल-परब' अभियान की शुरुआत की है।
- पी. जवाहर ने 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' (MPEDA) के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया।
- दक्षिण कोरिया ने 2030 के दशक के अंत तक अपनी पहली स्वदेशी परमाणु-संचालित पनडुब्बी विकसित करने के उद्देश्य से 'Jangbogo-N' परियोजना की शुरुआत की है।
- केरल ने 'प्रोजेक्ट ज़ीरो' लॉन्च किया, जो भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो-टॉलरेंस वाली एक पहल है, जिसका मकसद रिश्वत-मुक्त सार्वजनिक सेवाएँ सुनिश्चित करना है।
- स्वरा लक्ष्मी नायर शतरंज में 'वुमन इंटरनेशनल मास्टर' (WIM) का खिताब हासिल करने वाली बेंगलुरु की पहली महिला बन गईं।
- भारतीय ओलंपिक संघ ने ग्लासगो में होने वाले 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए रोहित राजपाल को भारत का 'शेफ डी मिशन' नियुक्त किया।
- Mercedes के ड्राइवर किमी एंतेनेली ने 2026 कैनेडियन ग्रां प्री जीत ली, जो Formula One में उनकी लगातार चौथी जीत है।
- RBI की मंजूरी के बाद, Elias George को Federal Bank का तीन साल के कार्यकाल के लिए पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया।
- जस्टिस प्रकाश नवलेकर एक उच्च-स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेंगे, जो जनसांख्यिकीय बदलावों और अवैध प्रवासन से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करेगी।
- IAS अधिकारी Piyush Singla को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' का निदेशक नियुक्त किया गया।
- ULLAS पहल के तहत Sikkim भारत का पाँचवाँ पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, जिससे वयस्क शिक्षा और आजीवन सीखने को बढ़ावा मिला है।
- केंद्रीय मंत्री Jyotiraditya Scindia ने Tripura में निर्यात, प्रसंस्करण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ₹236 करोड़ की लागत वाली 'Mission Queen Pineapple' योजना शुरू की।
- वैभव सूर्यवंशी ने एक ही सीज़न में 65 छक्के लगाकर एक नया IPL रिकॉर्ड बनाया, और क्रिस गेल की लंबे समय से चली आ रही उपलब्धि को पीछे छोड़ दिया।
- वयोवृद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया; वे अपने पीछे सहज और लोकप्रिय गज़लों की एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं।
- सिक्किम पुलिस सम्मान: राष्ट्रपति मुर्मू ने 125 वर्षों की सेवा, सुधार और नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग के लिए प्रतिष्ठित 'पुलिस कलर' से सम्मानित किया।
- स्लोवेनिया की राजनीति: जानेज़ जान्सा चौथी बार प्रधानमंत्री चुने गए; गठबंधन में बहुमत हासिल किया, जिससे यूरोप में राष्ट्रवादी राजनीति मजबूत हुई।
- CDSL लीडरशिप: SEBI ने अमित महाजन और नयना ओवलेकर को ऑपरेशन्स, कंप्लायंस और निवेशकों की शिकायतों को देखने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर मंजूरी दी।
- GAIL में विस्तार: दीपक गुप्ता का डायरेक्टर (प्रोजेक्ट्स) के तौर पर अतिरिक्त कार्यभार छह महीने के लिए बढ़ाया गया; साथ ही वे CMD की ज़िम्मेदारियाँ भी निभाते रहेंगे।
- Bellatrix-TelePIX सहयोग: भारत-कोरिया की साझेदारी ने एक एडवांस्ड VLEO सैटेलाइट मिशन विकसित किया है, जिसमें बेहतर अर्थ ऑब्ज़र्वेशन के लिए ऑप्टिकल पेलोड और प्रोपल्शन को जोड़ा गया है।
- ईशा सिंह की जीत: भारतीय शूटर ने म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में वर्ल्ड-रिकॉर्ड 43 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता।
- UN पीसकीपर्स का सम्मान: हरभजन सिंह और सुजीत प्रधान को मरणोपरांत डैग हैमरस्कजॉल्ड मेडल दिया गया; अभिलाषा बराक को जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला।
- श्याम लाल मीणा: अनुभवी ओलंपियन तीरंदाज का 61 साल की उम्र में निधन; उन्हें 1988 के सियोल ओलंपिक्स और तीरंदाजी में उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए याद किया जाता है।
- दिल्ली हवाई अड्डे ने उन्नत मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत का पहला 'स्काईकास्ट' सिस्टम लॉन्च किया।
- ओडिशा, इंटेल और 3DGS ने \$3.3 बिलियन के सेमीकंडक्टर निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- RBI और वियतनाम के केंद्रीय बैंक ने डिजिटल भुगतान सहयोग पर MoU पर हस्ताक्षर किए।
- वाइस एडमिरल अजय कोचर ने नौसेना स्टाफ के 48वें वाइस चीफ के रूप में कार्यभार संभाला।
- राजेश कुमार सिंह ने DRDO के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला।

नव-नियुक्तियां

कुणाल शाह WhatsApp की कमान संभालेंगे



मेटा प्लेटफॉर्म ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए भारतीय फिनटेक कंपनी CRED में निवेश किया है और इसके फ़ाउंडर कुणाल शाह को WhatsApp का नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया है।

मुख्य बिन्दु:

- चर्चा में कंपनी: CRED
- निवेशक: मेटा प्लेटफॉर्म
- निवेश की राशि: \$900 मिलियन (~₹8,550 करोड़)
- हिस्सेदारी: ~20%
- वैल्यूएशन: \$4.5 बिलियन
- सेक्टर: फिनटेक / डिजिटल पेमेंट

लीडरशिप में बदलाव:

- कुणाल शाह WhatsApp के हेड नियुक्त
- विल कैथकार्ट की जगह लेंगे
- CRED के अंतरिम CEO: मितेन संपत

पृष्ठभूमि:

- CRED की स्थापना 2018 में कुणाल शाह ने की
- फ़ोकस: क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट और रिवाइड इकोसिस्टम
- लेंडिंग, रेंट पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज़ में विस्तार किया
- WhatsApp भारत में मेटा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है (500 मिलियन से ज्यादा यूज़र्स)
- भारत मेटा की पेमेंट और कॉमर्स रणनीति के लिए एक अहम बाज़ार है

अन्य मुख्य तथ्य:

- मेटा WhatsApp, Facebook, Instagram और Threads की मालिक है
- मकसद: WhatsApp का पेमेंट + बिज़नेस कॉमर्स इकोसिस्टम में विस्तार करना
- भारत में फिनटेक की ग्रोथ UPI, JAM ट्रिनिटी और डिजिटल लेंडिंग से बढ़ी है
- CRED को प्रीमियम क्रेडिट-फ़ोकस्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म माना जाता है
- कुणाल शाह: FreeCharge के फ़ाउंडर (पहले की फिनटेक सफलता)

- चिंताएं: डेटा प्राइवेसी, बड़ी टेक कंपनियों का दबदबा, रेगुलेटरी निगरानी
- अवसर: ग्लोबल निवेश, फिनटेक इनोवेशन, डिजिटल इकोसिस्टम की ग्रोथ

तुषार मेहता को तीन और साल के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल फिर से नियुक्त किया गया



कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने तुषार मेहता को 1 जुलाई 2026 से तीन साल के और कार्यकाल के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने जारी किया।

मुख्य बिन्दु:

- व्यक्ति: तुषार मेहता
- पद: भारत का सॉलिसिटर जनरल
- पुनर्नियुक्ति: 3 साल के लिए (1 जुलाई 2026 से)
- मंजूरी: कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा
- जारीकर्ता: DoPT
- पद: भारत का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी
- पद की प्रकृति: संवैधानिक नहीं (कार्यकारी नियुक्ति)

पृष्ठभूमि:

- अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए
- पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (2014) के तौर पर काम किया
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं
- कानूनी मामलों में अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं
- SGI 'लॉ ऑफिसर्स (सेवा की शर्तें) नियम, 1987' के तहत काम करते हैं

अन्य मुख्य तथ्य:

- भारत के अटॉर्नी जनरल: आर. वेंकटरमणी
- अनुच्छेद 76: अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है
- SGI, अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है
- ACC का गठन: प्रधानमंत्री + केंद्रीय गृह मंत्री

SGI के काम:

- भारत सरकार को कानूनी सलाह देना
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रतिनिधित्व करना
- संवैधानिक मामलों और अनुच्छेद 143 के संदर्भों में सहायता करना

राजेंद्र कुमार साबू को UCO बैंक के MD और CEO का अतिरिक्त प्रभार मिला



वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने राजेंद्र कुमार साबू को UCO बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (MD और CEO) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

मुख्य बिन्दु:

- नियुक्ति: MD और CEO का अतिरिक्त प्रभार
- बैंक: UCO बैंक
- नियुक्त व्यक्ति: राजेंद्र कुमार साबू
- वर्तमान पद: एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, UCO बैंक
- नियुक्ति करने वाला विभाग: वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
- कारण: अश्विनी कुमार का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली पद
- कार्यकाल: 31 अगस्त 2026 तक या नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो)

पृष्ठभूमि:

- साबू नवंबर 2022 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर UCO बैंक से जुड़े
- बैंकिंग करियर की शुरुआत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (1994) में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर की
- बैंकिंग सेक्टर में कई लीडरशिप भूमिकाओं में काम किया
- इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक में चीफ जनरल मैनेजर के तौर पर काम किया

RBI ने HDFC बैंक के अंतरिम चेयरमैन के तौर पर केकी मिस्त्री का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी



रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने HDFC बैंक के अंतरिम पार्ट-टाइम चेयरमैन के तौर पर केकी मिस्त्री का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह कार्यकाल 18 सितंबर 2026 तक या किसी रेगुलर चेयरमैन की नियुक्ति होने तक रहेगा।

मुख्य बिन्दु:

- व्यक्ति: केकी मिस्त्री
- पद: अंतरिम पार्ट-टाइम चेयरमैन, HDFC बैंक
- कार्यकाल में बढ़ोतरी: 18 सितंबर 2026 तक
- अथॉरिटी: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI)
- कारण: बदलाव के समय लीडरशिप में निरंतरता बनाए रखना
- पिछले चेयरमैन: अतनु चक्रवर्ती
- बैंक का प्रकार: सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक (भारत)

पृष्ठभूमि:

- केकी मिस्त्री ने मार्च 2026 में पद संभाला
- RBI बैंकों में टॉप मैनेजमेंट की नियुक्तियों को मंजूरी देता है
- HDFC-HDFC लिमिटेड मर्जर (2023) के बाद HDFC बैंक की लीडरशिप में बदलाव
- सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण बैंक के गवर्नेंस में स्थिरता सुनिश्चित करता है
- HDFC बैंक भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में अहम भूमिका निभाता है

अन्य मुख्य तथ्य:

- HDFC बैंक की स्थापना: 1994
- हेडक्वार्टर: मुंबई
- MD और CEO: शशिधर जगदीशन
- RBI की स्थापना: 1935 (1949 में राष्ट्रीयकरण)
- RBI एक्ट: RBI एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949
- D-SIB बैंक: SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक
- HDFC मर्जर लागू: 1 जुलाई 2023
- कॉन्सेप्ट: RBI की निगरानी में "Too Big to Fail" (इतने बड़े कि फेल नहीं हो सकते) बैंक

विवेक अग्रवाल FATF के उपाध्यक्ष नियुक्त



वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल को 2026-27 के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत ने पहली बार यह पद हासिल किया है।

मुख्य बिन्दु:

- व्यक्ति: विवेक अग्रवाल
- नियुक्ति: उपाध्यक्ष, FATF

- कार्यकाल: 2026-27 (जुलाई 2026-जून 2027)
- संगठन: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)
- भारत के लिए पहली बार: हाँ (उपाध्यक्ष पद)
- वर्तमान पद: सचिव, संस्कृति मंत्रालय
- पिछली भूमिका: निदेशक, FIU-IND
- उत्तराधिकारी: जाइल्स थॉमसन (UK)
- निर्णय: FATF प्लेनरी (17-19 जून 2026)

पृष्ठभूमि:

- FATF, AML, CFT और PF के लिए वैश्विक मानक तय करता है
- भारत 2010 में FATF का सदस्य बना
- विवेक अग्रवाल ने FATF की बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व किया
- वैश्विक वित्तीय प्रशासन में भारत की भूमिका को मजबूत करता है

अन्य मुख्य तथ्य:

- FATF की स्थापना: 1989 (G7 पहल)
- मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
- सदस्य: 40 देश + क्षेत्रीय निकाय
- ग्रे लिस्ट: निगरानी वाले देश
- ब्लैक लिस्ट: उच्च जोखिम वाले क्षेत्र
- FIU-IND: 2004, वित्त मंत्रालय के तहत
- PMLA एक्ट: 2002 (2005 से प्रभावी)
- एगमोंट ग्रुप: 1995 (वैश्विक FIU नेटवर्क)

डॉ. सैबल चट्टोपाध्याय NSC के चेयरपर्सन नियुक्त



भारत सरकार ने IIM कलकत्ता के पूर्व डायरेक्टर डॉ. सैबल चट्टोपाध्याय को नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन (NSC) का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दी। वे प्रो. राजीव लक्ष्मण करंदीकर की जगह लेंगे।

मुख्य बिन्दु:

- नियुक्त व्यक्ति: डॉ. सैबल चट्टोपाध्याय
- पद: चेयरपर्सन, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन (NSC)
- नियुक्ति करने वाली संस्था: ACC (जिसके प्रमुख PM होते हैं)
- पिछले चेयरपर्सन: प्रो. आर. एल. करंदीकर
- नियुक्त सदस्य: शुभ्रत दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह, माधवन मुकुंद
- क्षेत्र: आधिकारिक आँकड़े / गवर्नेंस

पृष्ठभूमि:

- NSC का गठन 2005 में हुआ, 2006 से काम करना शुरू किया
- रंगराजन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर स्थापित
- आधिकारिक आँकड़ों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और अखंडता सुनिश्चित करता है
- MoSPI और अन्य सरकारी निकायों के साथ काम करता है
- चेयरपर्सन और 4 सदस्य पार्ट-टाइम होते हैं

अन्य मुख्य तथ्य:

- NSC के काम: नीति, मानक, समन्वय, सांख्यिकीय ऑडिट
- पदेन सदस्य: CEO, नीति आयोग
- मंत्रालय: MoSPI (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)
- NSO का गठन 2019 में CSO + NSSO को मिलाकर किया गया
- NSC भारत की सांख्यिकीय प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत करता है
- ACC उच्च-स्तरीय सरकारी नियुक्तियाँ संभालती है

हितेश जोशी GIC Re के CMD नियुक्त



भारत सरकार ने हितेश रमेशचंद्र जोशी को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (GIC Re) का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) नियुक्त किया है।

मुख्य बिन्दु:

- नियुक्त व्यक्ति: हितेश रमेशचंद्र जोशी
- पद: चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD)
- संस्था: GIC Re (जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया)
- पिछली भूमिका: एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक्टिंग CMD
- मंजूरी देने वाली संस्था: ACC (जिसके प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होते हैं)
- सेक्टर: इंश्योरेंस / री-इंश्योरेंस
- पूर्ववर्ती: एन. रामास्वामी

पृष्ठभूमि:

- GIC Re की स्थापना 1972 में हुई
- हेडक्वार्टर: मुंबई
- भारत की नेशनल री-इंश्योरर (वित्त मंत्रालय के तहत PSU)
- इंश्योरेंस कंपनियों को री-इंश्योरेंस सपोर्ट देती है
- इंश्योरेंस कंपनियों के रिस्क और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनेज करने में मदद करती है

- जोशी के पास री-इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंस में 30 से ज्यादा सालों का अनुभव है

अन्य मुख्य तथ्य:

- री-इंश्योरेंस = इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इंश्योरेंस
- रेगुलेटर: IRDAI (स्थापना 1999, हेडक्वार्टर हैदराबाद)
- नियुक्ति सिस्टम: FSIB PSU में फाइनेंशियल नियुक्तियों की सिफारिश करता है
- FSIB ने 2022 में बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) की जगह ली
- GIC Re भारत की सबसे बड़ी री-इंश्योरर है
- घरेलू इंश्योरेंस सेक्टर की स्टेबिलिटी और ग्लोबल री-इंश्योरेंस ऑपरेशन्स को सपोर्ट करती है

बाटा इंडिया ने संजय राव को MD और CEO नियुक्त किया



बाटा इंडिया ने संजय राव को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और CEO नियुक्त किया है। वे गुंजन शाह की जगह लेंगे, जिनका पांच साल का कार्यकाल पूरा हो गया है।

मुख्य बिन्दु:

- कंपनी: बाटा इंडिया
- नए MD और CEO: संजय राव
- निवर्तमान CEO: गुंजन शाह
- सेक्टर: फुटवियर और रिटेल
- फोकस: प्रीमियम प्रोडक्ट्स, डिजिटल कॉमर्स, रिटेल का विस्तार
- अनुभव: नाइकी (Nike), ज़ारा (Inditex), गेस यूरोप (Guess Europe)

पृष्ठभूमि:

- बाटा इंडिया की स्थापना 1931 में हुई
- पैरेंट कंपनी: बाटा ग्रुप (स्थापना 1894)
- मुख्य ब्रांड: बाटा, हश पपीज़ (Hush Puppies), पावर, नॉर्थ स्टार
- भारत का रिटेल सेक्टर ई-कॉमर्स और ओमनीचैनल मॉडल के ज़रिए बढ़ रहा है
- FDI भारत में ऑर्गनाइज़्ड रिटेल के विस्तार में मदद करता है

अन्य मुख्य तथ्य:

- हेडक्वार्टर (भारत): गुरुग्राम
- ग्लोबल हेडक्वार्टर: लॉज़ेन, स्विट्ज़रलैंड
- संस्थापक (बाटा ग्रुप): टोमास बाटा (Tomáš Bat'a)
- भारत की GDP में रिटेल का योगदान ~10% है

- भारत में डिजिटल और प्रीमियम फुटवियर सेगमेंट की ओर झुकाव

सिप्ला ने शिवम पुरी को 'वन इंडिया बिज़नेस' का CEO नियुक्त किया



सिप्ला ने शिवम पुरी को 1 जुलाई 2026 से अपने 'वन इंडिया बिज़नेस' का CEO नियुक्त किया है। वे सीनियर लीडरशिप टीम के हिस्से के तौर पर कंपनी की मैनेजमेंट काउंसिल में भी शामिल होंगे।

मुख्य बिन्दु:

- कंपनी: सिप्ला लिमिटेड
- नए CEO: शिवम पुरी
- पद: CEO, वन इंडिया बिज़नेस
- प्रभावी तारीख: 1 जुलाई 2026
- पिछली भूमिका: MD और CEO, सिप्ला हेल्थ
- सेक्टर: फार्मास्यूटिकल्स
- उद्देश्य: भारत में बिज़नेस ऑपरेशन्स को मज़बूत करना

पृष्ठभूमि:

- सिप्ला की स्थापना 1935 में डॉ. ख्वाजा अब्दुल हमीद ने की थी
- मुख्यालय मुंबई में है
- रेस्पिरेटरी (सांस संबंधी) और HIV/AIDS की दवाओं में मज़बूत मौजूदगी
- शिवम पुरी के पास FMCG और हेल्थकेयर में 23 से ज्यादा सालों का अनुभव है
- HUL, ITC, जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ काम किया है

अन्य मुख्य तथ्य:

- भारत फार्मा इंडस्ट्री के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है (वॉल्यूम के हिसाब से)
- भारत दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाओं का लगभग 20% सप्लाई करता है
- सिप्ला सस्ती दवाएं एक्सपोर्ट करने वाली एक बड़ी कंपनी है
- फार्मा सेक्टर "दुनिया की फार्मसी" (Pharmacy of the World) वाली छवि को मज़बूत करता है
- संबंधित योजना: PM भारतीय जनऔषधि परियोजना

BigBasket के CEO हरि मेनन ने पद छोड़ा; Amazon के अनुभवी अमित नंदा ने संभाली कमान



BigBasket के को-फ़ाउंडर और CEO हरि मेनन ने लगभग 15 साल तक नेतृत्व करने के बाद अपना पद छोड़ दिया है। Tata Digital समर्थित इस कंपनी के नए CEO के तौर पर Amazon के पूर्व एग्जीक्यूटिव अमित नंदा को नियुक्त किया गया है।

मुख्य बिन्दु:

- कंपनी: BigBasket
- पद छोड़ने वाले CEO: हरि मेनन
- नए CEO: अमित नंदा
- पैरेंट कंपनी: Tata Digital (Tata Group)
- सेक्टर: ऑनलाइन ग्रांसरी और क्लिक कॉमर्स
- मकसद: भारत के ई-ग्रांसरी मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करना
- बदलाव: नेतृत्व में बदलाव, लेकिन हरि मेनन बोर्ड में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे

पृष्ठभूमि:

- BigBasket की स्थापना 2011 में हुई
- को-फ़ाउंडर्स में हरि मेनन और अन्य शामिल हैं
- तेजी से बढ़ते क्लिक कॉमर्स सेक्टर में काम करती है
- डार्क स्टोर्स के जरिए बहुत तेज डिलीवरी (10-30 मिनट) पर फोकस
- Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart के साथ मुकाबला
- यह बदलाव स्टार्टअप्स में प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ओर बढ़ते रुझान को दिखाता है

अन्य मुख्य तथ्य:

- Tata Digital, Tata Group के डिजिटल इकोसिस्टम (Tata Neu ऐप) को चलाती है
- क्लिक कॉमर्स का मतलब है लोकल वेयरहाउस का इस्तेमाल करके बहुत तेज डिलीवरी करना
- Amazon (अमित नंदा की पिछली कंपनी) ग्लोबल ई-कॉमर्स लीडर है
- भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है
- भारत में 100 से ज्यादा यूनिคอร์न स्टार्टअप्स हैं
- इस सेक्टर में ई-कॉमर्स, फिनटेक, SaaS और लॉजिस्टिक्स इनोवेशन शामिल हैं

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख (COAS) नियुक्त किया गया

भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला सेना प्रमुख (COAS) नियुक्त किया है। वे अभी सेना के उप-प्रमुख

(Vice Chief of the Army Staff) के तौर पर काम कर रहे हैं और जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे।



मुख्य बिन्दु:

- पद: सेना प्रमुख (COAS)
- अधिकारी: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ
- वर्तमान पद: सेना के उप-प्रमुख (VCOAS)
- किनकी जगह लेंगे: जनरल उपेंद्र द्विवेदी
- नियुक्ति करने वाली संस्था: कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC)
- रैंक: फोर-स्टार जनरल (पद संभालने पर)

पृष्ठभूमि:

- दिसंबर 1986 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया
- NDA के पूर्व छात्र (खड़कवासला)
- 38 साल से ज़्यादा का सैन्य अनुभव
- ऑपरेशनल, कमांड और रणनीतिक भूमिकाओं में काम किया
- उग्रवाद-विरोधी अभियानों और आर्म्ड वॉरफेयर (बख्तरबंद युद्ध) में व्यापक अनुभव

सरकार ने दिनेश पंत और गिरिजा सुब्रमण्यन को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया



केंद्र सरकार ने भारत के बीमा क्षेत्र में रेगुलेटरी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए दिनेश पंत और गिरिजा सुब्रमण्यन को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य (WTM) नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल पांच साल या 62 साल की उम्र तक (जो भी पहले हो) होगा।

मुख्य बिन्दु:

- संस्था: IRDAI (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया)
- नियुक्तियां: दिनेश पंत, गिरिजा सुब्रमण्यन
- पद: पूर्णकालिक सदस्य (WTMs)
- कार्यकाल: 5 साल या 62 साल की उम्र तक (जो भी पहले हो)

- उद्देश्य: बीमा क्षेत्र के रेगुलेशन और सुधारों को मजबूत करना
- विज़न: "2047 तक सभी के लिए बीमा"

पृष्ठभूमि:

- नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा की गईं
- IRDAI भारत में बीमा क्षेत्र को रेगुलेट और विकसित करता है
- बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं
- पॉलिसी फ्रेमवर्क और उपभोक्ता सुरक्षा को बेहतर बनाने पर फोकस

अन्य मुख्य तथ्य:

- IRDAI की स्थापना: 1999 (IRDA एक्ट, 1999 के तहत)
- मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना
- संरचना: 1 चेयरपर्सन, 5 तक पूर्णकालिक सदस्य (WTMs), 4 तक अंशकालिक सदस्य
- दिनेश पंत: MD, LIC ऑफ़ इंडिया (एक्चुरियल एक्सपर्ट)
- गिरिजा सुब्रमण्यन: पूर्व CMD, न्यू इंडिया एश्योरेंस
- बीमा के प्रकार: जीवन बीमा और सामान्य बीमा क्षेत्र

कुमार शंकर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त



कुमार शंकर को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कमल किशोर चतिवाल की जगह ली है, जो GAIL (इंडिया) लिमिटेड वापस लौट गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- नए MD: कुमार शंकर
- किनकी जगह ली: कमल किशोर चतिवाल
- पिछली भूमिका: MD, महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड (MNGL)
- अनुभव: तेल और गैस सेक्टर में 32 साल से ज्यादा का अनुभव
- योग्यता: BITS पिलानी से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट

IGL के बारे में:

- 1998 में स्थापना।
- भारत की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनी।
- CNG और PNG की सप्लाई करती है।
- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में काम करती है।
- GAIL और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जॉइंट वेंचर।

UIDAI के CEO सौरभ विजय ने IndiaAI मिशन के CEO का पद संभाला



UIDAI के CEO सौरभ विजय ने IndiaAI मिशन के CEO के तौर पर अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली है। यह नियुक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा की गई है।

मुख्य बिंदु:

- चर्चा में व्यक्ति: सौरभ विजय
- वर्तमान पद: CEO, UIDAI
- अतिरिक्त जिम्मेदारी: CEO, IndiaAI मिशन
- नोडल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
- IndiaAI मिशन का बजट: ₹10,372 करोड़

पृष्ठभूमि:

- सौरभ विजय एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में UIDAI के CEO के रूप में कार्यरत हैं।
- पिछले CEO के पद बदलने के बाद उन्हें IndiaAI मिशन के CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
- IndiaAI मिशन देश के AI इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

IndiaAI मिशन के बारे में:

- मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित।
- नोडल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।
- कुल बजट: ₹10,372 करोड़।
- इसका उद्देश्य AI अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप, कौशल विकास और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
- यह स्वदेशी, नैतिक और जिम्मेदार AI क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है।

UIDAI के बारे में:

- स्थापना: जनवरी 2009।
- वैधानिक दर्जा: आधार अधिनियम, 2016 के तहत।
- मंत्रालय: MeitY।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।
- आधार नंबर जारी करने और उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार।

RBI के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ाया गया



केंद्र सरकार ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के डिप्टी गवर्नर के तौर पर स्वामीनाथन जानकीरमन का कार्यकाल दो साल और बढ़ा दिया है। यह विस्तार 26 जून 2026 से लागू होगा।

मुख्य बिन्दु:

- व्यक्ति: स्वामीनाथन जानकीरमन
- पद: RBI डिप्टी गवर्नर
- कार्यकाल विस्तार: 2 साल
- कब से लागू: 26 जून 2026

पृष्ठभूमि:

- दो साल के लिए RBI डिप्टी गवर्नर के तौर पर फिर से नियुक्त।
- मूल रूप से जून 2023 में नियुक्त हुए थे।
- इस पद पर एम के जैन की जगह ली थी।
- पहले IDBI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं।
- RBI डिप्टी गवर्नरों में कमर्शियल बैंकिंग कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

RBI के बारे में:

- स्थापना: 1 अप्रैल 1935
- मुख्यालय: मुंबई
- गवर्नर: संजय मल्होत्रा
- किसके तहत रेगुलेटेड: RBI एक्ट, 1934
- कुल डिप्टी गवर्नर: 4

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को अगला 'वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ' नियुक्त किया गया



एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायु सेना का अगला 'वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ' (VCAS) नियुक्त किया गया है। वे 1 जुलाई 2026 को अपना पद संभालेंगे।

मुख्य बिन्दु:

- नियुक्ति: वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (VCAS)
- वर्तमान पद: चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (CISC)

- पदभार ग्रहण: 1 जुलाई 2026
- सेवा: भारतीय वायु सेना

पृष्ठभूमि:

- फ्लाइट टेस्टिंग और आधुनिकीकरण में माहिर अनुभवी फाइटर पायलट।
- स्वदेशी विमान विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई।
- जगुआर और मिग-27 के एवियोनिक्स अपग्रेड में शामिल रहे।
- 'डायरेक्टर एयर स्टाफ रिक्रायरमेंट्स' के तौर पर MMRC ट्रायल में हिस्सा लिया।
- 6 दिसंबर 1986 को IAF फाइटर स्टीम में कमीशन हुए।

VCAS के बारे में:

- भारतीय वायु सेना में दूसरा सबसे बड़ा पद
- चीफ ऑफ एयर स्टाफ की मदद करते हैं
- ऑपरेशन, प्लानिंग और आधुनिकीकरण के लिए ज़िम्मेदार

ACC ने विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के तौर पर नीलकंठ मिश्रा की नियुक्ति को मंजूरी दी



कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने विश्व बैंक (वाशिंगटन D.C.) में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नीलकंठ मिश्रा की नियुक्ति को 3 साल के लिए मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिन्दु:

- ACC द्वारा मंजूरी
- पद: कार्यकारी निदेशक, विश्व बैंक (भारत)
- कार्यकाल: 3 साल
- स्थान: वाशिंगटन D.C., USA

पृष्ठभूमि:

- वर्तमान भूमिका: मुख्य अर्थशास्त्री, एक्सिस बैंक
- सदस्य: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)
- विशेषज्ञता: मैक्रोइकॉनॉमिक्स और वित्तीय शोध
- वैश्विक विकास संबंधी फैसलों में भारत का प्रतिनिधित्व

विश्व बैंक के बारे में:

- मुख्यालय: वाशिंगटन D.C.
- स्थापना: 1944 (ब्रेटन वुड्स सम्मेलन)
- अध्यक्ष: अजय बंगा
- उद्देश्य: गरीबी कम करना और विकास के लिए वित्तपोषण
- कार्य: ऋण, अनुदान, बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग

विश्व बैंक समूह:

- IBRD – मध्यम आय वाले देशों के लिए ऋण

- IDA – सबसे गरीब देशों के लिए आसान शर्तों पर ऋण (सॉफ्ट लोन)
- IFC – निजी क्षेत्र में निवेश करने वाली शाखा
- MIGA – निवेश गारंटी
- ICSID – विवाद निपटान संस्था

ACC ने PM के सलाहकार के तौर पर तरुण कपूर का कार्यकाल बढ़ाया



कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में तरुण कपूर के कार्यकाल को एक साल और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिन्दु:

- नियुक्त व्यक्ति: तरुण कपूर (1987-बैच के IAS अधिकारी, HP कैडर)
- भूमिका: प्रधानमंत्री कार्यालय में PM के सलाहकार
- कार्यकाल विस्तार: 10 जून 2026 तक एक साल के लिए
- मंजूरी देने वाली संस्था: कैबिनेट की नियुक्ति समिति

पृष्ठभूमि:

- भारत के पूर्व पेट्रोलियम सचिव।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) के पूर्व चेयरमैन।
- PMO में सचिव स्तर के पद पर कार्यरत।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

- PMO नीति बनाने और मंत्रालयों के बीच कामकाज में तालमेल बिठाता है।
- ACC की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।
- PNGRB पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र को रेगुलेट करता है (स्थापना 2006 में हुई)।

विपुल सऊदी अरब में भारत के राजदूत नियुक्त



विपुल को सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है: वे डॉ. सुहेल एजाज़ खान की जगह लेंगे।

मुख्य बिन्दु:

- नियुक्त व्यक्ति: विपुल (IFS 1998 बैच)
- वर्तमान पोस्टिंग: कतर में राजदूत
- नई पोस्टिंग: सऊदी अरब
- किनकी जगह लेंगे: डॉ. सुहेल एजाज़ खान

पृष्ठभूमि:

- इससे पहले काहिरा, कोलंबो, जिनेवा और दुबई में काम कर चुके हैं।
- सऊदी अरब ऊर्जा, व्यापार, रक्षा और निवेश के क्षेत्र में एक अहम साझेदार है।
- इससे भारत-सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद (SPC) का सहयोग मजबूत होगा।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

- राजधानी: रियाद
- मुद्रा: सऊदी रियाल (SAR)
- SPC की स्थापना 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान हुई थी।
- मुख्य क्षेत्र: ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, रक्षा, निवेश और तकनीक।

अंशुल गुप्ता बैंक ऑफ़ अमेरिका के भारत में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिज़नेस की कमान संभालेंगे



अंशुल गुप्ता को बैंक ऑफ़ अमेरिका के भारत में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिज़नेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

मुख्य बिन्दु:

- चर्चा में व्यक्ति: अंशुल गुप्ता
- नई भूमिका: हेड ऑफ़ इंडिया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बैंक ऑफ़ अमेरिका
- पिछली कंपनी: अवेंडस कैपिटल

पृष्ठभूमि:

उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का लगभग दो दशकों का अनुभव है।

बैंक ऑफ़ अमेरिका:

- मुख्यालय: शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना, USA
- CEO: ब्रायन मोयनिहान

अवेंडस कैपिटल:

- स्थापना: 1999
- मुख्यालय: मुंबई

अजय राजन प्रोटियन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज के MD और CEO नियुक्त



प्रोटियन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने सुरेश सेठी की जगह अजय राजन को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) नियुक्त किया है।

मुख्य बिन्दु:

- नए MD और CEO: अजय राजन
- कंपनी: प्रोटियन ई-गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
- पुराना नाम: NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पृष्ठभूमि:

- अजय राजन के पास बैंकिंग, फिनटेक और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में 30 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है।
- प्रोटियन भारत में प्रमुख डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है।

इनसे जुड़े हैं:

- PAN सेवाएं
- टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क (TIN)
- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
- अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क
- ONDC

जस्टिस मीनाक्षी एम. राय पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नियुक्त



सिक्किम हाई कोर्ट की मौजूदा जज, जस्टिस मीनाक्षी एम. राय को पटना हाई कोर्ट का 48वां चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।

मुख्य बिन्दु:

- नियुक्त व्यक्ति: जस्टिस मीनाक्षी एम. राय
- कोर्ट: पटना हाई कोर्ट
- किनकी जगह ली: जस्टिस संगम कुमार साहू
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 217

पृष्ठभूमि:

- अभी सिक्किम हाई कोर्ट की जज के तौर पर काम कर रही हैं।
- सिक्किम की पहली महिला जो हाई कोर्ट जज बनीं।
- 2015 में सिक्किम हाई कोर्ट की जज बनीं।
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनकी नियुक्ति की सिफारिश की।

डी.के. शिवकुमार ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली



कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी.के. शिवकुमार ने सिद्धारमैया की जगह कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।

मुख्य बिन्दु:

- नए CM: डी.के. शिवकुमार
- राज्य: कर्नाटक
- किनकी जगह ली: सिद्धारमैया
- पार्टी: इंडियन नेशनल कांग्रेस
- शपथ किसने दिलाई: थावरचंद गहलोट

पृष्ठभूमि:

- कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता चुने गए।
- कर्नाटक के पूर्व उपमुख्यमंत्री।
- कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष।
- कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- आठ बार के विधायक।

कर्नाटक:

- राजधानी: बेंगलुरु
- राज्यपाल: थावरचंद गहलोट
- हाई कोर्ट: कर्नाटक हाई कोर्ट

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 163: मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है।
- अनुच्छेद 164: राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं।

लोखंडे प्रशांत सीताराम CBSE के चेयरपर्सन नियुक्त

केंद्र सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत राहुल सिंह की जगह लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है।

मुख्य बिन्दु:

- नियुक्त व्यक्ति: लोखंडे प्रशांत सीताराम
- सेवा: 2001-बैच के IAS (AGMUT कैडर)

- पिछला पद: अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय
- किसकी जगह ली: राहुल सिंह
- मंजूरी: कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC)



पृष्ठभूमि:

- वरुण भारद्वाज को नया CBSE सचिव नियुक्त किया गया।
- राहुल सिंह को कृषि और किसान कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE):

- मुख्यालय: नई दिल्ली
- किसके अंतर्गत: शिक्षा मंत्रालय
- कक्षा 10, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएँ और CTET आयोजित करता है

एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने 27वें नौसेना प्रमुख (CNS) के तौर पर कार्यभार संभाला



एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख (CNS) का पदभार संभाला है।

मुख्य बिंदु:

- पद: 27वें नौसेना प्रमुख (CNS)
- किनकी जगह ली: एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी
- कमीशन: 1 जुलाई 1987
- विशेषज्ञता: कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर
- पिछला पद: फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (FOC-in-C), वेस्टर्न नेवल कमांड

पृष्ठभूमि:

INS विक्रमादित्य और INS मैसूर जैसे प्रमुख नौसैनिक प्लेटफॉर्म की कमान संभाली।

अन्य मुख्य तथ्य:

- CNS भारतीय नौसेना के प्रोफेशनल प्रमुख होते हैं।

- नौसैनिक ऑपरेशन, आधुनिकीकरण, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक योजना के लिए ज़िम्मेदार।

भारतीय नौसेना कमांड:

- वेस्टर्न नेवल कमांड – मुंबई
- ईस्टर्न नेवल कमांड – विशाखापत्तनम
- सदर्न नेवल कमांड – कोच्चि

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में पाँच जजों की नियुक्ति की



राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की। ये नियुक्तियाँ न्यायपालिका को मज़बूत करने और लंबित मामलों के निपटारे में सुधार करने में मदद करती हैं।

मुख्य बिन्दु:

- कुल नियुक्तियाँ: 5 जज
- नियुक्ति करने वाले: भारत के राष्ट्रपति
- सिफ़ारिश: CJI जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
- SC में काम कर रहे जजों की संख्या: 37 जज
- स्वीकृत संख्या: 38 जज

पृष्ठभूमि:

नए नियुक्त जज:

- जस्टिस शील नागू
- जस्टिस श्री चंद्रशेखर
- जस्टिस संजीव सचदेवा
- जस्टिस अरुण पल्ली
- वी. मोहना
- नियुक्त किए गए चार लोग हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि वी. मोहना को सीधे बार (वकीलों) से पदोन्नत किया गया है।
- वकीलों का सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति पाना एक दुर्लभ घटना है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के माध्यम से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई थी।

वाइस एडमिरल अजय कोचर ने नौसेना स्टाफ के 48वें वाइस चीफ का पदभार संभाला



वाइस एडमिरल अजय कोचर ने नौसेना स्टाफ के 48वें वाइस चीफ (VCNS) के रूप में पदभार ग्रहण किया, और वे भारतीय नौसेना में दूसरे सबसे ऊँचे रैंक वाले अधिकारी बन गए। उनके पास 37 वर्षों से अधिक की विशिष्ट नौसेना सेवा का अनुभव है।

मुख्य बिन्दु:

- अधिकारी: वाइस एडमिरल अजय कोचर
- नियुक्ति: नौसेना स्टाफ के 48वें वाइस चीफ (VCNS)
- सेवा: 37+ वर्ष
- कमीशन: 1 जुलाई 1988 (NDA, पुणे)
- पूर्ववर्ती: वाइस एडमिरल संजय वत्सयान

पृष्ठभूमि:

- वे गनरी और मिसाइल युद्ध (Missile Warfare) के विशेषज्ञ हैं।
- उन्होंने भारतीय नौसेना में कई ऑपरेशनल, कमांड और स्टाफ भूमिकाओं में सेवा दी है।
- एक लंबे और विशिष्ट नौसेना करियर के बाद उन्होंने यह पदभार संभाला है।

VCNS के बारे में:

- CNS के बाद भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे ऊँचा रैंक।

इन कार्यों में सहायता करते हैं:

- ऑपरेशंस (संचालन)
- आधुनिकीकरण
- बल नियोजन (Force planning)
- लॉजिस्टिक्स (रसद)
- प्रशासन और नीति

भारतीय नौसेना के बारे में:

भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा

- मुख्यालय: नई दिल्ली
- नौसेना स्टाफ के प्रमुख (CNS): दिनेश के. त्रिपाठी
- आदर्श वाक्य: "शं नो वरुणः"
- आधुनिक स्थापना: 26 जनवरी 1950

अंडमान और निकोबार कमांड (ANC) के बारे में:

- 2001 में स्थापित
- भारत की एकमात्र एकीकृत त्रि-सेवा कमांड (थल, जल और वायु सेना की संयुक्त कमांड)
- पोर्ट ब्लेयर में स्थित
- हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है

स्लोवेनिया की संसद ने जेनेज़ जान्शा को प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी



स्लोवेनिया की संसद ने जेनेज़ जान्शा को प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है, जो रॉबर्ट गोलोब के नेतृत्व वाली पिछली सरकार से एक बदलाव का संकेत है।

मुख्य बिन्दु:

- देश: स्लोवेनिया
- प्रधानमंत्री: जेनेज़ जान्शा
- संसदीय वोट: 51-36
- कार्यकाल: प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल
- संसद: नेशनल असेंबली (90 सदस्य)

पृष्ठभूमि:

- जेनेज़ जान्शा एक अनुभवी राजनेता और स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं।
- उनकी पार्टी ने संसद में बहुमत हासिल करने के लिए चार मध्य-दक्षिणपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन किया।

पिछले कार्यकाल:

- 2004-2008
- 2012-2013
- 2020-2022
- 2026-वर्तमान

स्लोवेनिया के बारे में:

- राजधानी: ल्युब्लजाना
- मुद्रा: यूरो (€)
- राष्ट्रपति: नताशा पर्क मुसर
- स्वतंत्रता: 1991 (यूगोस्लाविया से)

**हर कठिनाई में
एक सबक छिपा होता है,
बस देखने की
नज़र चाहिए.**

राष्ट्रीय समाचार

हरियाणा ने 'जल संरक्षित हरियाणा' प्रोजेक्ट्स शुरू किए

वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा के "जल संरक्षित हरियाणा" प्रोजेक्ट के लिए ₹4,000 करोड़ के लोन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, राज्य ने सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस और पर्यावरण से जुड़े नतीजों को बेहतर बनाने के मकसद से स्वच्छ हवा और AI डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किए हैं।

मुख्य बिन्दु:

- प्रोजेक्ट: जल संरक्षित हरियाणा
- राज्य: हरियाणा
- कुल प्रोजेक्ट लागत: ₹5,714 करोड़
- विश्व बैंक का लोन: ₹4,000 करोड़
- लागू करने की अवधि: 2026-2032
- कवरेज: 15 क्लस्टर (48.94 लाख एकड़)

उद्देश्य:

- हरियाणा में पानी के मामले में आत्मनिर्भरता
- पानी का कुशल और समान वितरण
- भूजल संरक्षण और पानी का टिकाऊ इस्तेमाल

पृष्ठभूमि:

- हरियाणा को भूजल की कमी और सिंचाई से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
- टिकाऊ खेती और जल प्रबंधन पर ध्यान
- विश्व बैंक का सहयोग लंबे समय के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को मजबूत करता है
- सिंचाई, खेती और जल संरक्षण को मिलाकर एक एकीकृत दृष्टिकोण

सरकार ने SC और OBC स्कॉलरशिप के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत खत्म की

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) ने SC और OBC प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने वाले छात्रों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवास प्रमाण पत्र) की ज़रूरत को खत्म कर दिया है।

मुख्य बिन्दु:

- सुधार: डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत को खत्म करना
- मंत्रालय/विभाग: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE)
- स्कीम: प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप (SC और OBC)
- लाभार्थी: हर साल लगभग 1.2 करोड़ छात्र
- मकसद: आसानी से सुविधा मिलना, कम कागज़ी कार्रवाई, तेज़ी से मंजूरी
- तरीका: डिजिटल गवर्नेंस और 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' (आसान जीवन) पहल

➤ दायरा: अपने राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्र भी पात्र हैं

पृष्ठभूमि:

- पहले, आवेदन करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी था
- प्री-मैट्रिक: कक्षा IX-X (स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करना)
- पोस्ट-मैट्रिक: कक्षा X से ऊपर (उच्च शिक्षा में मदद)
- SC और OBC छात्रों के लिए शिक्षा में समानता को बढ़ावा देना
- नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के ज़रिए लागू

अन्य मुख्य तथ्य:

- DoSJE सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है
- NSP: स्कॉलरशिप के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म
- संवैधानिक समर्थन: अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46
- डिजिटल इंडिया पहल पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देती है
- फ़ोकस: सबको शामिल करना, आगे बढ़ने के मौके और प्रशासनिक बोझ कम करना

सरकार ने 100% इथेनॉल फ्यूल (E100) के कानूनी इस्तेमाल को मंजूरी दी

भारत सरकार ने गाड़ियों में 100% इथेनॉल फ्यूल (E100) के कानूनी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद आयातित फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना और साफ़-सुथरे, रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिन्दु:

- घोषणा: 100% इथेनॉल फ्यूल (E100) के लिए कानूनी मंजूरी
- मंत्री: नितिन गडकरी
- मकसद: फॉसिल फ्यूल का आयात कम करना और एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाना
- फ्यूल का प्रकार: E100 (100% इथेनॉल, पेट्रोल की कोई मिलावट नहीं)
- समर्थन: इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) और फ्लेक्स-फ्यूल इकोसिस्टम
- महत्व: ग्रीन मोबिलिटी और घरेलू फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है

पृष्ठभूमि:

- भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है
- इथेनॉल गन्ना, मक्का और अनाज से बनाया जाता है
- इथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन उत्सर्जन और तेल पर निर्भरता कम होती है
- भारत ने तय समय से पहले ही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है

- बायोप्यूल को बढ़ावा देना भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन का हिस्सा है

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- E10 = 10% इथेनॉल + पेट्रोल
- E20 = 20% इथेनॉल + पेट्रोल
- E85 = 85% इथेनॉल + पेट्रोल
- E100 = 100% इथेनॉल
- इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 में शुरू किया गया
- बायोप्यूल पर राष्ट्रीय नीति: 2018
- G20 प्रेसीडेंसी (2023) के दौरान ग्लोबल बायोप्यूल्स अलायंस लॉन्च किया गया
- फ्लेक्स-प्यूल गाड़ियां कई तरह के इथेनॉल ब्लेंड पर चल सकती हैं
- लक्ष्य: पूरे भारत में इथेनॉल डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

ज़ोजि ला टनल का काम एक अहम पड़ाव पर पहुँचा, कश्मीर-लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी का रास्ता साफ हुआ

भारत ने ज़ोजि ला टनल के निर्माण में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। हिमालय के नीचे टनल के दोनों सिरों को जोड़ने वाला आखिरी 'ब्रेकथ्रू' (सुरंग का मिलन) पूरा हो गया है, जिससे कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर कनेक्टिविटी का रास्ता खुल गया है।

मुख्य बिंदु:

- प्रोजेक्ट: ज़ोजि ला टनल
- जगह: सोनमर्ग और द्रास के बीच
- किन जगहों को जोड़ती है: कश्मीर और लद्दाख
- ब्रेकथ्रू कब हुआ: जून 2026
- काम करने वाली एजेंसी: नेशनल हाईवेज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL)

पृष्ठभूमि:

- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आखिरी ब्रेकथ्रू ब्लास्ट किया।
- ज़ोजि ला दर्रे के नीचे लगभग 13.15 किलोमीटर लंबी टनल।
- कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी देगी।
- इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सिंगल-ट्यूब, दोनों तरफ से चलने वाली (बाई-डायरेक्शनल) सड़क टनल मानी जाती है।
- इससे यात्रा का समय कम होने और इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।
- लद्दाख में डिफेंस लॉजिस्टिक्स और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करेगी।
- पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

ज़ोजि ला टनल के बारे में:

- नेशनल हाईवे-1 (NH-1) पर स्थित है।
- निर्माण 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ।
- सिंगल-ट्यूब, दोनों तरफ से चलने वाली सड़क टनल।
- लगभग 11,500–12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

UP ने ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 'प्रोजेक्ट गंगा' शुरू किया

योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण घरों तक हाई-स्पीड फाइबर-बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुँचाने और डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने के लिए 'प्रोजेक्ट गंगा' (Government Assisted Network for Growth and Advancement) लॉन्च किया।

मुख्य बिंदु:

- किसने लॉन्च किया: योगी आदित्यनाथ
- राज्य: उत्तर प्रदेश
- उद्देश्य: ग्रामीण इलाकों में अंतिम छोर तक (लास्ट-माइल) ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुँचाना
- लक्षित लाभार्थी: 20 लाख ग्रामीण परिवार
- पहले चरण का कवरेज: 21 जिले

प्रोजेक्ट गंगा के बारे में:

- इसका पूरा नाम 'Government Assisted Network for Growth and Advancement' है।
- इसका मकसद ग्रामीण डिजिटल अंतर (digital divide) को कम करना है।
- यह डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, कौशल विकास और स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देगा।
- इसे OneOTT Entertainment Limited के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
- इससे 1 लाख से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

डिजिटल इंडिया के बारे में:

- 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया।
- नोडल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
- उद्देश्य: भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना।

निष्कर्ष:

प्रोजेक्ट गंगा का मकसद 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है, जिससे उत्तर प्रदेश में डिजिटल समावेश और ग्रामीण विकास को मज़बूती मिलेगी।

पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर, बिना किसी रुकावट के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- उपलब्धि: बिना किसी रुकावट के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री
- पिछला रिकॉर्ड धारक: जवाहरलाल नेहरू
- नेहरू का रिकॉर्ड: लगातार 4,077 दिन
- प्रधानमंत्री के तौर पर पहली शपथ: 26 मई 2014

- वर्तमान स्थिति: लगातार तीसरा कार्यकाल
- पृष्ठभूमि:**
- नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं।
- वे लगातार तीन कार्यकाल पूरे करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं।
- वे गैर-कांग्रेसी पार्टी से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी हैं।
- दुनिया के कई नेताओं ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।
- प्रधानमंत्री बनने से पहले, उन्होंने 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया।

अमित शाह ने 'विनिमय' (VINIMAY) लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (LPMS) 'विनिमय' का उद्घाटन किया। इसका मकसद बॉर्डर मैनेजमेंट को आधुनिक बनाना और भारत के लैंड पोर्ट्स (ज़मीनी बंदरगाहों) के ज़रिए कार्गो और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाना है।

मुख्य बिंदु:

- प्लेटफॉर्म: विनिमय (LPMS)
- किसके द्वारा लॉन्च किया गया: अमित शाह
- नोडल एजेंसी: लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (LPAI)
- उद्देश्य: डिजिटल बॉर्डर मैनेजमेंट
- मंत्रालय: गृह मंत्रालय

विशेषताएं:

- कार्गो और यात्रियों की एंड-टू-एंड डिजिटल प्रोसेसिंग को संभव बनाता है।
- स्लॉट बुकिंग, पेमेंट, ट्रेकिंग और सिंगल-विंडो क्लियरेंस की सुविधा देता है।
- कस्टम्स, इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसियों को एक साथ जोड़ता है।
- ICEGATE और ULIP प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है।

विनिमय के बारे में:

- डिजिटल लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (LPMS)।
- पेपरलेस और इंटीग्रेटेड बॉर्डर ऑपरेशन्स को सपोर्ट करता है।
- लैंड पोर्ट्स को एयरपोर्ट और सीपोर्ट के डिजिटल सिस्टम के बराबर लाता है।
- पारदर्शिता, सुरक्षा और सीमा-पार व्यापार को आसान बनाता है।

प्रोजेक्ट शिखर

प्रोजेक्ट शिखर को मीशो (Meesho) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के बीच एक MoU के ज़रिए शुरू किया गया है। इसका

मकसद MSME और डिजिटल सेलर को IPO के लिए तैयार होने और कैपिटल मार्केट तक पहुँचने में मदद करना है।

मुख्य बिन्दु:

- पार्टनर: मीशो और BSE
- टारगेट ग्रुप: MSME और डिजिटल-फर्स्ट बिज़नेस
- मकसद: इक्विटी फाइनेंसिंग और IPO की तैयारी में सुधार करना

पृष्ठभूमि:

इन विषयों पर गाइडेंस देता है:

- कॉर्पोरेट गवर्नेंस
- फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
- रेगुलेटरी कंप्लायंस
- बिज़नेस रीस्ट्रक्चरिंग
- IPO की तैयारी
- स्टॉक मार्केट के ज़रिए फंड जुटाने में बिज़नेस की मदद करता है।
- पारदर्शिता, फॉर्मलाइज़ेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देता है।
- BSE SME प्लेटफॉर्म, SME को आसान लिस्टिंग नियमों के साथ कैपिटल जुटाने में मदद करता है।

BSE:

- स्थापना: 1875
- मुख्यालय: मुंबई
- बेंचमार्क इंडेक्स: SENSEX
- भारत में कैपिटल मार्केट को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) रेगुलेट करता है।

निष्कर्ष:

प्रोजेक्ट शिखर का मकसद MSME को कैपिटल मार्केट के मौकों से जोड़ना है, ताकि वे पब्लिक फंडिंग और बेहतर गवर्नेंस प्रैक्टिस के ज़रिए अपना विस्तार कर सकें।

प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (PMRC) योजना 2026

शिक्षा मंत्रालय ने विदेशों में काम कर रहे भारतीय मूल के रिसर्चर्स को आकर्षित करने और भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए PMRC योजना 2026 शुरू की है।

मुख्य बिन्दु:

- योजना: प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (PMRC) योजना 2026
- मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय
- उद्देश्य: 'ब्रेन गेन' (प्रतिभाओं की वापसी) को बढ़ावा देना और भारत के R&D इकोसिस्टम को मजबूत करना
- टारगेट ग्रुप: विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के रिसर्चर्स, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल्स

PMRC फेलो को ये सुविधाएं मिलेंगी:

- फेलोशिप सपोर्ट
- रिसर्च ग्रांट
- एडवांस्ड लैबोरेटरी तक पहुंच
- एकेडमिक लीडरशिप के अवसर

श्रेणियां:

1. यंग रिसर्च फेलो (YRF): PhD के बाद < 5 साल
2. सीनियर फेलो (SF): PhD के बाद 5-10 साल
3. रिसर्च चेयर (RC): PhD के बाद ≥ 10 साल

प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

- AI और क्वांटम कंप्यूटिंग
- सेमीकंडक्टर
- साइबर सुरक्षा
- बायोटेक्नोलॉजी
- हेल्थकेयर और मेडटेक
- अंतरिक्ष और रक्षा
- ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन
- ब्लू इकोनॉमी

केंद्र ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के मसौदा संशोधनों को वापस ले लिया

केंद्र सरकार ने किसानों, छोटे पैमाने की गुड़ और खांडसारी इकाइयों, और अन्य हितधारकों के कड़े विरोध के बाद, बढ़े हुए विनियमन और अनुपालन के बोझ की चिंताओं को देखते हुए, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 के मसौदे को वापस ले लिया है।

मुख्य बिन्दु:

- नीति: गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 का मसौदा (वापस ले लिया गया)
- शासी अधिनियम: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- क्षेत्र: गन्ना और चीनी उद्योग

मुख्य मुद्दे:

- गुड़ और खांडसारी इकाइयों के लिए लाइसेंसिंग
- FRP का अनुपालन
- चीनी मिलों के लिए दूरी के मानक

पृष्ठभूमि:

- गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 गन्ने की कीमत निर्धारण, खरीद और आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
- इस मसौदे का उद्देश्य चीनी क्षेत्र में सुधार और उसका आधुनिकीकरण करना था।
- छोटे उत्पादकों और प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंताओं के कारण इसे वापस ले लिया गया।

विशेषताएं:

- गुड़ और खांडसारी इकाइयों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रस्ताव किया गया था।
- उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) का भुगतान करने की आवश्यकता शुरू की गई थी।
- चीनी मिलों के बीच न्यूनतम दूरी को 15 किमी से बढ़ाकर 25 किमी करने का प्रस्ताव था।
- किसानों और उद्योग के हितधारकों के कड़े विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया।

FRP के बारे में:

- उचित और लाभकारी मूल्य (FRP): गन्ना किसानों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम कीमत।
- CACP की सिफारिश और CCEA की मंजूरी पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- 2009 में इसने सांविधिक न्यूनतम मूल्य (SMP) का स्थान ले लिया।
- 2026-27 के लिए FRP: ₹365 प्रति क्विंटल (10.25% रिकवरी पर)।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के बारे में:

- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी किया गया।
- गन्ने की कीमत निर्धारण, खरीद, आपूर्ति और मिलों की स्थापना को नियंत्रित करता है।

सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित

सिक्किम को आधिकारिक तौर पर ULLAS – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत एक पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, और इसके साथ ही यह इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत का 5वां राज्य बन गया है।

मुख्य बिन्दु:

- राज्य: सिक्किम
- साक्षरता दर: 99.82%
- कार्यक्रम: ULLAS – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम
- मान्यता का पैमाना: 95% साक्षरता
- उपलब्धि का वर्ष: 2026

पृष्ठभूमि:

- ULLAS का उद्देश्य वयस्क शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, अंक ज्ञान और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है।
- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

ULLAS के बारे में:

- पूरा नाम: समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ (ULLAS)
- किसके द्वारा शुरू किया गया: शिक्षा मंत्रालय
- लॉन्च का वर्ष: 2022
- अवधि: 2022-2027
- लक्षित समूह: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षर व्यक्ति

ULLAS के पाँच घटक:

1. बुनियादी साक्षरता और अंकज्ञान
2. महत्वपूर्ण जीवन कौशल
3. बुनियादी शिक्षा
4. व्यावसायिक कौशल विकास
5. सतत शिक्षा

ULLAS के तहत पूरी तरह साक्षर राज्य:

- मिजोरम (2025) – पहला राज्य
- गोवा (2025)

- त्रिपुरा (2025)
- हिमाचल प्रदेश (2025)
- सिक्किम (2026)

सिक्किम के बारे में:

- राजधानी: गंगटोक
- मुख्यमंत्री: प्रेम सिंह तमांग
- राज्यपाल: ओम प्रकाश माथुर
- राज्य स्थापना दिवस: 16 मई 1975
- सबसे ऊँची चोटी: कंचनजंगा

कैबिनेट ने SARTHAK-PDS योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक बनाने और खाद्यान्न वितरण में सुधार के लिए 2026-27 से 2030-31 तक के लिए ₹25,530 करोड़ के परिव्यय के साथ SARTHAK-PDS को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिन्दु:

- योजना: SARTHAK-PDS
- पूरा नाम: राशन परिवहन और प्रबंधन में सहायता योजना - PDS में स्वचालन के साथ आय (Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in PDS)
- परिव्यय: ₹25,530 करोड़
- अवधि: 2026-27 से 2030-31
- उद्देश्य: PDS का आधुनिकीकरण

पृष्ठभूमि:

- PDS भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, जिसके तहत रियायती खाद्यान्न वितरित किया जाता है।
- यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत संचालित होती है।
- NFSA के तहत लगभग 81 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- यह परिवहन, प्रबंधन सहायता, FPS मार्जिन और SMART-PDS सुधारों को एक ही व्यापक योजना के तहत एकीकृत करती है।
- यह प्रौद्योगिकी-आधारित खाद्यान्न वितरण को बढ़ावा देती है।
- इसका मुख्य जोर पारदर्शिता, दक्षता और लीकेज (चोरी/बर्बादी) को कम करने पर है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC):

- यह लाभार्थियों को भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से राशन प्राप्त करने की सुविधा देता है।
- इसमें आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है।
- यह प्रवासी श्रमिकों और गतिशील आबादी के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।

निष्कर्ष:

SARTHAK-PDS का लक्ष्य AI-आधारित शासन, बेहतर लॉजिस्टिक्स और बढ़ी हुई पारदर्शिता के माध्यम से भारत की

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदलाव लाना है, ताकि लाखों लाभार्थियों तक खाद्य सुरक्षा की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके।

GI टैग भारत की सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करते हैं

नए GI टैग दिए गए: खुरासानी इमली (मध्य प्रदेश), त्रिपुरा सरिंडा, और असम के चार पारंपरिक प्रोडक्ट्स को GI पहचान मिली, जिससे भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत मज़बूत हुई।

मिशन क्वीन पाइनएप्पल: केंद्र ने त्रिपुरा के GI-टैग वाले क्वीन पाइनएप्पल को वैल्यू एडिशन और एग्रो-प्रोसेसिंग के ज़रिए ग्लोबल एक्सपोर्ट ब्रांड में बदलने के लिए ₹236 करोड़ का मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया।

खुरासानी इमली (मध्य प्रदेश): धार ज़िले के मांडू के बाओबाब फल को उसकी खास पहचान, दवा वाली वैल्यू और आदिवासी समुदायों के साथ जुड़ाव के लिए GI टैग मिला।

असम के चार नए GI प्रोडक्ट्स: कार्बी आंगलोंग हैंडलूम, बिहू पेपा, बैम्बू क्राफ्ट, और देउरी हैंडलूम को GI टैग मिले, जिससे देसी क्राफ्ट, आदिवासी रोज़ी-रोटी और सांस्कृतिक बचाव को बढ़ावा मिला।

त्रिपुरा सरिंडा: त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों के पारंपरिक झुके हुए तार वाले इंटर्मेंट को GI टैग मिला, जिससे राज्य के कुल GI प्रोडक्ट्स की संख्या चार हो गई।

GI टैग क्यों ज़रूरी हैं: GI टैग किसी खास इलाके से जुड़े प्रोडक्ट्स की सुरक्षा करते हैं, पारंपरिक ज्ञान को बचाते हैं, नकल रोकते हैं, कारीगरों और किसानों को सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट और गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।



अंतराष्ट्रीय समाचार

US-Iran के बीच शुरुआती शांति समझौते के तहत IAEA ईरान में फिर से जांच शुरू करेगा

इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) से उम्मीद है कि वह US-Iran के बीच शुरुआती शांति समझौते के तहत ईरान की परमाणु सुविधाओं की जांच फिर से शुरू करेगी। इस कदम का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण स्वरूप की पुष्टि करना है।

मुख्य बिन्दु:

- चर्चा में संगठन: इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA)
- मुद्दा: ईरान की परमाणु सुविधाओं की IAEA जांच को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव
- IAEA के महानिदेशक: राफेल मारियानो ग्रेसी
- कारण: US-Iran के बीच शुरुआती शांति समझौता और अंतरिम मेमोरेंडम
- बातचीत का समय: व्यापक शांति और परमाणु समझौते के लिए 60 दिन
- मौजूदा स्थिति: ईरान ने अभी तक संवेदनशील परमाणु साइटों तक अंतिम पहुंच नहीं दी है; मंजूरी प्रतिबंधों में ढील और अंतिम समझौते से जुड़ी है।
- जांच का फोकस: ईरान की यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों की पुष्टि करना और परमाणु सुरक्षा नियमों के पालन को सुनिश्चित करना।
- मुख्य परमाणु साइटें: नतांज़, फोर्दो और इस्फ़हान।

पृष्ठभूमि:

- IAEA दुनिया की परमाणु निगरानी संस्था है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि परमाणु सामग्री का इस्तेमाल हथियारों के लिए न किया जाए।
- स्थापना: 1957
- मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया

अन्य मुख्य तथ्य:

- JCPOA (जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन) पर 2015 में ईरान और P5+1 (US, UK, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी) के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
- JCPOA के तहत, ईरान प्रतिबंधों में ढील के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमत हुआ, जबकि IAEA ने नियमों के पालन की निगरानी की।
- 2018 में US के हटने के बाद यह समझौता कमजोर हो गया, जिससे फिर से तनाव बढ़ गया।
- ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसके तीन स्तंभ हैं: अप्रसार, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग और निरस्त्रीकरण।

- कम संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल नागरिक परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है, जबकि अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम से संभावित हथियार विकास को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।

अमेरिका ने भारत के M777A2 अल्ट्रा-लाइट होवित्ज़र के लिए \$230 मिलियन के सस्टेनमेंट पैकेज की घोषणा की

अमेरिका ने भारतीय सेना के आर्टिलरी सिस्टम के लंबे समय तक रखरखाव और ऑपरेशनल तैयारी को बेहतर बनाने के लिए भारत के M777A2 अल्ट्रा-लाइट होवित्ज़र को सपोर्ट करने के मकसद से \$230 मिलियन के सस्टेनमेंट पैकेज का प्रस्ताव दिया है।

मुख्य बिन्दु:

- देश: अमेरिका
- लाभार्थी: भारतीय सेना
- उपकरण: M777A2 अल्ट्रा-लाइट होवित्ज़र
- पैकेज की कीमत: \$230 मिलियन
- प्रोग्राम: फॉरेन मिलिट्री सेल्स (FMS)
- मकसद: रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट
- कॉन्ट्रैक्टर: BAE सिस्टम्स

पृष्ठभूमि:

- 2016 में भारत और अमेरिका के बीच M777 डील हुई
- भारत ने कुल 145 होवित्ज़र खरीदे
- ऊंचे इलाकों (लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश) में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया
- भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग का हिस्सा

भारत-थाईलैंड रक्षा वार्ता से रणनीतिक सहयोग मजबूत हुआ

बैंकॉक में हुई 10वीं रक्षा वार्ता के दौरान भारत और थाईलैंड रक्षा सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने रक्षा निर्माण, R&D (अनुसंधान और विकास), क्षमता विकास और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।

मुख्य बिन्दु:

- कार्यक्रम: 10वीं थाईलैंड-भारत रक्षा वार्ता
- स्थान: बैंकॉक, थाईलैंड
- मुख्य क्षेत्र: रक्षा निर्माण, R&D, इनोवेशन, क्षमता विकास
- रणनीतिक फोकस: इंडो-पैसिफिक सुरक्षा और स्थिरता

सह-अध्यक्षता:

- भारत: सत्यजीत मोहंती (रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव)
- थाईलैंड: एडमिरल नट्टापोल डियूवानिच
- उद्देश्य: रक्षा उद्योग और सैन्य सहयोग को मजबूत करना

पृष्ठभूमि:

- भारत-थाईलैंड संबंध 2025 में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचे
- 2012 में रक्षा सहयोग MoU पर हस्ताक्षर किए गए
- थाईलैंड भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत एक प्रमुख ASEAN भागीदार है
- रक्षा वार्ता, अभ्यास और प्रशिक्षण आदान-प्रदान के माध्यम से नियमित जुड़ाव
- सहयोग समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता तक फैला हुआ है

BRICS ने कृषि सहयोग पर इंदौर घोषणा को अपनाया

भारत की BRICS अध्यक्षता (2026) के तहत इंदौर में हुई बैठक में BRICS कृषि मंत्रियों ने 'इंदौर घोषणा' को अपनाया। यह घोषणा किसानों के कल्याण, खाद्य सुरक्षा, जलवायु के प्रति लचीलेपन और डिजिटल कृषि सहयोग पर केंद्रित है।

मुख्य बिन्दु:

- घोषणा: BRICS इंदौर घोषणा
- स्थान: इंदौर, मध्य प्रदेश
- किसने अपनाया: BRICS कृषि मंत्रियों ने
- मुख्य विषय: किसान, खाद्य सुरक्षा, जलवायु के प्रति लचीलापन, तकनीक
- भारत की भूमिका: BRICS अध्यक्षता 2026 का समन्वयक
- मुख्य फोकस: किसान-केंद्रित वैश्विक कृषि प्रणाली
- डिजिटल कृषि और इनोवेशन पर जोर

पृष्ठभूमि:

- BRICS प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है
- विस्तारित BRICS (2026) में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, UAE, ईरान, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं
- ये सामूहिक रूप से दुनिया की लगभग 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं
- वैश्विक अनाज उत्पादन में लगभग 42% का योगदान करते हैं
- BRICS ढांचे के तहत कृषि सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है
- भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान 'ग्लोबल साउथ' की प्राथमिकताओं को बढ़ावा देता है

अन्य मुख्य तथ्य:

- नई पहल: किसानों के बीज अधिकारों पर वैश्विक मंच (Global Forum on Farmers' Seed Rights)
- भारत की BRICS अध्यक्षता का विषय: "सहयोग और स्थिरता के लिए लचीलापन और इनोवेशन का निर्माण"

UK ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन की घोषणा की

यूनाइटेड किंगडम ने ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने और नाबालिगों को हानिकारक डिजिटल चीजों से बचाने के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर देशव्यापी बैन की घोषणा

की है। उम्मीद है कि यह कानून 2027 के वसंत (spring) से लागू होगा।

मुख्य बिन्दु:

- देश: यूनाइटेड किंगडम
- घोषणा: 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन
- प्रधानमंत्री: कीर स्टारमर
- उद्देश्य: बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा
- लागू होने की उम्मीद: वसंत 2027
- रेगुलेटर: Ofcom
- किससे प्रेरित: ऑस्ट्रेलिया की ऐसी ही पॉलिसी से

अन्य मुख्य तथ्य:

- शामिल प्रमुख प्लेटफॉर्म: Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, X, YouTube, Reddit
- WhatsApp और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स को छूट मिलने की उम्मीद है
- अतिरिक्त नियम: नाबालिगों के लिए लाइव-स्ट्रीमिंग पर पाबंदियां और AI चैटबॉट की सीमाएं
- UK की राजधानी: लंदन
- मुद्रा: पाउंड स्टर्लिंग (£)

EU ने यूक्रेन और मोल्दोवा के लिए सदस्यता प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई

यूरोपीय संघ (EU) ने यूक्रेन और मोल्दोवा के साथ बातचीत के पहले क्लस्टर को शुरू करने की मंजूरी दे दी है, जो EU की सदस्यता की दिशा में एक अहम कदम है।

मुख्य बिन्दु:

- संगठन: यूरोपीय संघ (EU)
- देश: यूक्रेन और मोल्दोवा
- घटनाक्रम: सदस्यता के लिए बातचीत के पहले क्लस्टर की शुरुआत
- क्लस्टर का नाम: "फंडामेंटल्स" (बुनियादी सिद्धांत)
- इसमें शामिल हैं: कानून का शासन, लोकतंत्र, न्यायपालिका में सुधार, मौलिक अधिकार, लोक प्रशासन
- उद्देश्य: EU सदस्यता की दिशा में प्रगति

पृष्ठभूमि:

- यूक्रेन ने फरवरी 2022 में EU सदस्यता के लिए आवेदन किया था
- मोल्दोवा ने मार्च 2022 में आवेदन किया था
- दोनों को जून 2022 में उम्मीदवार का दर्जा दिया गया
- EU में शामिल होने की प्रक्रिया कोपेनहेगन मानदंडों (1993) पर आधारित है
- उम्मीदवार देशों को राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी मानकों को पूरा करना होता है

अन्य मुख्य तथ्य:

- EU की स्थापना मास्ट्रिच संधि (1993) के तहत हुई थी

- EU में 27 सदस्य देश हैं
- मुद्रा: यूरो (20 सदस्य इसका इस्तेमाल करते हैं)
- मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम
- यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष: उर्सुला वॉन डेर लेयेन
- यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष: एंटोनियो कोस्टा
- सदस्यता की बातचीत में पहला क्लस्टर ("फंडामेंटल्स") आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण होता है

UN सुरक्षा परिषद के लिए पांच देशों को गैर-स्थायी सदस्य चुना गया

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2027-2028 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, DR कांगो, लातविया और लाइबेरिया को UNSC का गैर-स्थायी सदस्य चुना है। यह कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा।

मुख्य बिन्दु:

- संस्था: UN महासभा (UNGA)
- परिषद: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)
- कार्यकाल: 2027-2028
- नए सदस्य: बहरीन, कोलंबिया, DR कांगो, लातविया, लाइबेरिया

पृष्ठभूमि:

- न्यूयॉर्क में UNGA में चुनाव हुआ।
- लातविया पहली बार UNSC के लिए चुना गया।
- अन्य चार देश पहले भी सदस्य रह चुके हैं।
- UNSC अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखता है।

नए सदस्य: बहरीन: कोलंबिया, DR कांगो, लातविया, लाइबेरिया
UNSC:

- 15 सदस्य (5 स्थायी + 10 गैर-स्थायी)
- मुख्यालय: न्यूयॉर्क
- स्थापना: 1945
- P5: चीन, फ्रांस, रूस, UK, USA

इथियोपिया WTO में शामिल: WTO सदस्यता प्रक्रिया को समझना

लगभग 22 साल की बातचीत के बाद इथियोपिया WTO का सदस्य बनने जा रहा है, जिससे WTO में शामिल होने की प्रक्रिया पर ध्यान गया है।

मुख्य बिन्दु:

- देश: इथियोपिया
- संगठन: विश्व व्यापार संगठन (WTO)
- आवेदन का वर्ष: 2003
- सदस्यता प्रक्रिया: शामिल होना (एक्सेशन)
- मौजूदा WTO सदस्य: 166 (इथियोपिया के शामिल होने से पहले)

पृष्ठभूमि:

- WTO में शामिल होने के लिए देशों को अपने व्यापार कानूनों को WTO के नियमों के अनुरूप बनाना होता है।
- सदस्य देश बाजार तक पहुंच और टैरिफ में कटौती के लिए बातचीत करते हैं।
- आर्थिक सुधारों, व्यापार वार्ता और राजनीतिक अस्थिरता के कारण इथियोपिया के शामिल होने में देरी हुई।
- सदस्यता से बाजार तक पहुंच, निवेश के अवसर और वैश्विक व्यापार प्रशासन में भागीदारी बेहतर होती है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना: 1995
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- महानिदेशक: नोजी ओकोन्जो-इवेला
- WTO ने GATT (1947) की जगह ली।
- भारत WTO का संस्थापक सदस्य है।

जापान ने विदेशी खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना की

जापान ने खुफिया समन्वय को मजबूत करने और जासूसी, आतंकवाद, साइबर हमले और क्षेत्रीय तनाव जैसे बढ़ते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद (NIC) की स्थापना की है।

मुख्य बिन्दु:

- देश: जापान
- संस्था: राष्ट्रीय खुफिया परिषद (NIC)
- उद्देश्य: केंद्रीकृत खुफिया समन्वय
- प्रधानमंत्री: सनाए ताकाइची
- फोकस: राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रति-खुफिया (Counter-Intelligence)

पृष्ठभूमि:

- पहले खुफिया कार्य कई अलग-अलग एजेंसियों में बंटे हुए थे।
- समन्वय में आने वाली चुनौतियों के कारण व्यापक खुफिया सुधारों की ज़रूरत महसूस हुई।
- यह कदम जापान की व्यापक सुरक्षा आधुनिकीकरण रणनीति का एक हिस्सा है।

मुख्य विशेषताएं:

- NIC की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे।
- एक नया 'राष्ट्रीय खुफिया ब्यूरो' इसके सचिवालय के रूप में काम करेगा।
- 'कैबिनेट खुफिया और अनुसंधान कार्यालय' (CIRO) को अपग्रेड करके एक 'राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी' बनाया जाएगा।

बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था

भारत जुलाई 2026 से 'इंडेक्स ऑफ़ सर्विसेज़ प्रोडक्शन' (ISP) शुरू करेगा

MoSPI 14 जुलाई 2026 को भारत का पहला मासिक 'इंडेक्स ऑफ़ सर्विसेज़ प्रोडक्शन' (ISP) लॉन्च करेगा। यह सर्विस सेक्टर के शॉर्ट-टर्म आउटपुट को मापेगा और 'इंडेक्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन' (IIP) की तरह ही सर्विस सेक्टर के लिए एक इंडेक्स का काम करेगा।

मुख्य बिन्दु:

- लॉन्च करने वाला: MoSPI / NSO
- पहली बार जारी: 14 जुलाई 2026
- बेस ईयर: 2024-25
- जारी होने का समय: मासिक (हर महीने की 29 तारीख को, 60 दिन के अंतर के साथ)
- मकसद: सर्विस सेक्टर के मासिक आउटपुट पर नज़र रखना
- किसका समकक्ष: IIP का
- तरीका: फिक्स्ड-वेट लैस्पेयर वॉल्यूम इंडेक्स
- डेटा का मुख्य स्रोत: GST डेटा
- सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी: भारत के GVA का 50% से ज्यादा
- बैकग्राउंड:
- ISP सर्विस सेक्टर के लिए भारत का पहला आधिकारिक मासिक इंडेक्स है।
- इससे GDP का अनुमान लगाने, आर्थिक पूर्वानुमान और पॉलिसी बनाने में सुधार होगा।
- शुरुआत में इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज़ जैसे सेक्टर शामिल होंगे।

अन्य मुख्य तथ्य:

- NSO GDP, CPI, IIP और ISP तैयार करता है।
- IIP का बेस ईयर: 2022-23 | ISP का बेस ईयर: 2024-25।
- टेक्निकल एडवाइज़री कमेटी की चेयरपर्सन: देबजानी घोष (मई 2025 में गठित)।

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL) को नवरत्न का दर्जा मिला

भारत सरकार ने चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL) को नवरत्न का दर्जा दिया है, जिससे यह 28वीं नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ (CPSE) बन गई है।

मुख्य बिन्दु:

- कंपनी: चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL)
- मिला दर्जा: नवरत्न CPSE
- कुल नवरत्न CPSE: भारत में 28वीं
- मंजूरी देने वाली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

- नोटिफाई करने वाला विभाग: डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक एंटरप्राइजेज़ (DPE)
- पैरेंट कंपनी: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)
- मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
- मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु

नवरत्न दर्जे के फ़ायदे:

- निवेश के फ़ैसलों में ज्यादा आज़ादी
- जॉइंट वेंचर और विस्तार की आज़ादी
- बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तेज़ी से मंजूरी

IOCL:

- भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी
- महाराष्ट्र CPSE
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- वित्त मंत्रालय के तहत DPE, CPSE के वर्गीकरण का प्रबंधन करता है

सरकार ने MFIs के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम बढ़ाई; इंडस्ट्री को ज्यादा इस्तेमाल की उम्मीद

सरकार ने छोटे उधारकर्ताओं तक क्रेडिट का बहाव बेहतर करने और लिक्विडिटी (नकदी की उपलब्धता) बढ़ाने के लिए माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स 2.0 (CGSMFI-2.0) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को आगे बढ़ाया है।

मुख्य बिन्दु:

- स्कीम: माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स 2.0 के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGSMFI-2.0)
- लागू करने वाली एजेंसी: नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
- इंडस्ट्री बॉडी: माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क
- वैलिडिटी बढ़ाई गई: 31 अगस्त 2026 तक
- गारंटी कॉर्पस: ₹20,000 करोड़
- मंजूर किए गए लोन: ~₹770 करोड़

CGSMFI-2.0 के बारे में:

- 20 मार्च 2026 को लॉन्च की गई
- भारत सरकार के तहत NCGTC के ज़रिए चलाई जाती है
- MFIs को दिए गए लोन के लिए गारंटी कवरेज देती है
- कवरेज लेवल: 80% (छोटे MFIs), 75% (मध्यम), 70% (बड़े)
- बड़े MFIs के लिए अधिकतम लोन लिमिट बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ की गई (20% AUM कैप के अधीन)

माइक्रोफाइनेंस सेक्टर फ्रेमवर्क के बारे में:

- MFIs कम आय वाले और ज़रूरतमंद उधारकर्ताओं को छोटे लोन देते हैं

- RBI की गाइडलाइंस के तहत रेगुलेट और सुपरवाइज़ किए जाते हैं
- MFIN, NBFC-MFIs के लिए सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गनाइज़ेशन के तौर पर काम करता है
- ज़िम्मेदार लेंडिंग और फाइनेंशियल इन्क्लूजन पर फ़ोकस

निष्कर्ष:

CGSMFI-2.0 की अवधि बढ़ाने से लिक्विडिटी बेहतर होती है, क्रेडिट का बहाव बढ़ता है और देश भर में छोटे उधारकर्ताओं के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूजन को बढ़ावा मिलता है, जिससे भारत का माइक्रोफाइनेंस इकोसिस्टम मज़बूत होता है।

भारत और नेपाल ने आसानी से रियल-टाइम पैसे ट्रांसफर करने के लिए UPI और NPI को जोड़ा

भारत और नेपाल ने UPI और नेपाल के NPI के बीच इंटरऑपरेबिलिटी (आपसी तालमेल) शुरू की है, ताकि रियल-टाइम में सीमा-पार पैसे ट्रांसफर करना आसान हो सके। यह सिस्टम बैंक की जानकारी शेयर किए बिना मोबाइल नंबर, UPI ID और VPA का इस्तेमाल करके तुरंत P2P पेमेंट करने की सुविधा देता है।

मुख्य बिंदु:

- देश: भारत और नेपाल
- जुड़े हुए सिस्टम: UPI और नेपाल का NPI
- किसके द्वारा लागू: NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड
- मकसद: रियल-टाइम सीमा-पार P2P रेमिटेंस (पैसे भेजना)
- तरीका: मोबाइल नंबर, UPI ID, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस

पृष्ठभूमि:

- भारत और नेपाल के बीच आसानी से फंड ट्रांसफर के लिए UPI-NPI लिंकेज शुरू किया गया है
- बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है
- शुरुआत में कुछ चुनिंदा बैंकों के ज़रिए लॉन्च किया गया, आगे विस्तार की योजना है
- तेज़, सस्ते और ज़्यादा आसान सीमा-पार पेमेंट के G20 लक्ष्य को सपोर्ट करता है
- पड़ोसी देशों के बीच डिजिटल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को मज़बूत करता है

UPI और NPI के बारे में:

- UPI को 2016 में NPCI ने लॉन्च किया था और RBI इसे रेगुलेट करता है
- भारत में 24x7 तुरंत डिजिटल पेमेंट की सुविधा देता है
- नेपाल का NPI राष्ट्रीय डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे NCHL मैनेज करता है

- दोनों सिस्टम इंटरऑपरेबल और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा देते हैं

Viyona Fintech को BOU के तौर पर NPCI Bharat BillPay सर्टिफिकेशन मिला

Viyona Fintech को NPCI से Bharat BillPay इकोसिस्टम के तहत Bharat BillPay ऑपरेटिंग यूनिट (BOU) के तौर पर काम करने का सर्टिफिकेशन मिला है।

इससे कंपनी पूरे भारत में सीधे डिजिटल बिल पेमेंट सर्विस दे सकती है और उन्हें मैनेज कर सकती है।

मुख्य बिंदु:

- सर्टिफिकेशन देने वाली संस्था: National Payments Corporation of India (NPCI)
- संस्था: Viyona Fintech
- स्टेटस: Bharat BillPay ऑपरेटिंग यूनिट (BOU)
- सिस्टम: Bharat BillPay
- मकसद: डिजिटल बिल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

Bharat BillPay और BOU के बारे में:

- Bharat BillPay भारत में बार-बार होने वाले बिल पेमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है
- सुरक्षित और स्टैंडर्ड ट्रांज़ैक्शन के लिए NPCI के तहत चलाया जाता है
- BOU (Bharat BillPay ऑपरेटिंग यूनिट) को इस सिस्टम के तहत काम करने की मंजूरी होती है
- BOU बिलर को जोड़ने, ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस करने और सर्विस का विस्तार करने का काम करते हैं
- बैंकों, ऐप्स और पेमेंट प्लेटफॉर्म के बीच इंटरऑपरेबिलिटी पक्की करता है

निष्कर्ष:

BOU के तौर पर Viyona Fintech का सर्टिफिकेशन Bharat BillPay की पहुँच बढ़ाकर और सुरक्षित, यूनिफ़ाइड और आसान बिल पेमेंट सर्विस तक पहुँच में सुधार करके भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मज़बूत करता है।

FCNR(B) डिपॉज़िट और RBI की स्वेप स्कीम चर्चा में

FCNR(B) डिपॉज़िट पर चर्चा हो रही है कि क्या रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) NRI विदेशी मुद्रा डिपॉज़िट को आकर्षित करने और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) को मज़बूत करने के लिए कोई विशेष स्वेप स्कीम फिर से शुरू कर सकता है।

मुख्य बिंदु:

- FCNR(B) का पूरा नाम: फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट (बैंक) डिपॉज़िट
- पात्र जमाकर्ता: NRI और OCI

- उद्देश्य: विदेशी मुद्रा का प्रवाह (inflow) बढ़ाना
- RBI की विशेष स्वैप स्कीम: 2013 में शुरू की गई
- मकसद: रुपये की स्थिरता और विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा देना

FCNR(B) डिपॉजिट के बारे में:

- विदेशी मुद्राओं में रखे गए फिक्स्ड डिपॉजिट।
- मूलधन और ब्याज को पूरी तरह से वापस ले जाया जा सकता है (repatriable)।
- जमाकर्ताओं को एक्सचेंज रेट में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है।
- अवधि 1 से 5 साल तक होती है।
- स्वीकृत मुद्राएं: USD, GBP, EUR, JPY, AUD और CAD।

RBI स्वैप स्कीम के बारे में:

- 2013 में रुपये की कीमत गिरने और बाहरी सेक्टर के दबाव के समय शुरू की गई थी।
- बैंकों ने FCNR(B) डिपॉजिट स्वीकार किए और रियायती दरों पर RBI के साथ विदेशी मुद्रा की अदला-बदली (स्वैप) की।
- इससे विदेशी मुद्रा का काफी प्रवाह हुआ और रुपये को स्थिर करने में मदद मिली।
- अभी तक किसी नई FCNR(B) स्वैप स्कीम की घोषणा नहीं की गई है।

IIP, CPI और GDP के लिए नया बेस ईयर मंजूर

भारत सरकार ने IIP, CPI और GDP जैसे अहम मैक्रो-इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेस ईयर में बदलाव को मंजूरी दी है, ताकि अर्थव्यवस्था के मौजूदा ढांचे को बेहतर ढंग से दिखाया जा सके और आंकड़ों की सटीकता बढ़ाई जा सके।

मुख्य बिंदु:

- IIP का नया बेस ईयर: 2022-23
- शामिल इंडिकेटर्स: IIP, CPI और GDP
- डेटा तैयार करने वाली एजेंसी: नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO)
- मंत्रालय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- मकसद: आर्थिक इंडिकेटर्स की प्रासंगिकता और सटीकता को बेहतर बनाना

विशेषताएं:

- बदली हुई IIP सीरीज़ में उभरते उद्योगों और नए प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाएगा।
- बेस ईयर में बदलाव से खपत के बदलते तरीकों और आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है।
- इससे आर्थिक योजना बनाने, पॉलिसी बनाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने में मदद मिलती है।
- यह वैश्विक स्तर पर माने जाने वाले सांख्यिकीय तरीकों का पालन करता है।

IIP के बारे में:

- यह औद्योगिक उत्पादन में अल्पकालिक बदलावों को मापता है।
- इसे NSO हर महीने जारी करता है।
- इसमें मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और बिजली क्षेत्र शामिल हैं।
- आठ कोर उद्योगों का IIP वेटेज में 40.27% हिस्सा है।

CPI और GDP के बारे में:

- CPI खुदरा महंगाई को मापता है और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया इसका इस्तेमाल मॉनेटरी पॉलिसी के लिए करता है।
- GDP किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दिखाता है।
- दोनों इंडिकेटर्स NSO द्वारा तैयार किए जाते हैं।

निष्कर्ष:

IIP, CPI और GDP के बेस ईयर में बदलाव का मकसद अहम इंडिकेटर्स को मौजूदा उत्पादन और खपत के तरीकों के अनुरूप बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था की ज्यादा सटीक तस्वीर पेश करना है। IIP, CPI और GDP के लिए नया बेस ईयर मंजूर

भारत ने कंबोडिया में UPI पेमेंट शुरू किया

भारत ने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और ACLEDA बैंक के बीच साझेदारी के ज़रिए कंबोडिया में UPI-आधारित QR पेमेंट की सुविधा शुरू की है। इससे भारतीय यात्री कंबोडिया के KHQR सिस्टम के ज़रिए पेमेंट कर सकेंगे।

मुख्य बिन्दु:

- देश: भारत और कंबोडिया
- पार्टनर: NIPL और ACLEDA बैंक Plc.
- पेमेंट सिस्टम: KHQR से जुड़ा UPI
- महत्व: क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल पेमेंट

पृष्ठभूमि:

- भारतीय यूज़र कंबोडिया में UPI ऐप्स का इस्तेमाल करके QR-आधारित पेमेंट कर सकते हैं।
- KHQR (खमेर QR) कंबोडिया का नेशनल इंटरऑपरेबल QR पेमेंट सिस्टम है।
- इससे दोनों देशों के बीच डिजिटल इकोनॉमिक और टूरिज़्म संबंध मज़बूत होते हैं।
- यह भारत-कंबोडिया QR पेमेंट लिंकेज पहल का पहला चरण है।

UPI:

- लॉन्च: 2016
- किसने बनाया: नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI)
- किसके द्वारा रेगुलेटेड: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया

कंबोडिया:

- राजधानी: नोम पेन्ह
- करेंसी: कंबोडियन रियल
- प्रधानमंत्री: हुन मानेट

UPI लिंकेज वाले अन्य देश:

1. सिंगापुर
2. UAE
3. फ्रांस
4. श्रीलंका
5. मॉरिशस
6. नेपाल
7. भूटान
8. कंबोडिया (सबसे नया)

निष्कर्ष:

कंबोडिया में इसकी शुरुआत से UPI की ग्लोबल पहुंच और बढ़ती है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में भारत की लीडरशिप मज़बूत होती है।

सरकार WPI की जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) लाएगी

भारत महंगाई को मापने के तरीके को बेहतर बनाने और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ तालमेल बिठाने के लिए धीरे-धीरे होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) की जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) प्रेमवर्क अपनाएगा।

मुख्य बिन्दु:

- मौजूदा WPI बेस ईयर: 2011-12
- नया WPI बेस ईयर: 2022-23
- बदलाव का समय (ट्रांजिशन पीरियड): 5 साल
- नए इंडेक्स: OPPI, IPPI, SPPI

पृष्ठभूमि:

- PPI में सामान और सर्विस दोनों शामिल होंगे, जबकि WPI में सिर्फ सामान शामिल होता है।
- यह प्रोडक्शन के कई चरणों में कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है।

शुरुआती SPPI कवरेज:

- बैंकिंग
- इंश्योरेंस
- रेलवे
- टेलीकम्युनिकेशन
- हवाई यात्री परिवहन
- सिक्योरिटीज ट्रांज़ेक्शन
- पेंशन फंड मैनेजमेंट
- WPI बास्केट में आइटम की संख्या 697 से बढ़ाकर 957 कर दी गई है।

WPI बनाम PPI:

- WPI: सिर्फ सामान, थोक कीमतें।
- PPI: सामान + सर्विस, प्रोड्यूसर/फैक्टरी-गेट कीमतें।
- PPI प्रोड्यूसर महंगाई का ज्यादा व्यापक पैमाना है।

अन्य मुख्य तथ्य:

- WPI को ऑफिस ऑफ़ इकोनॉमिक एडवाइज़र (DPIIT) जारी करता है।
- CPI को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) तैयार करता है।

- RBI मॉनेटरी पॉलिसी के लिए CPI महंगाई का इस्तेमाल करता है।

निष्कर्ष:

WPI से PPI में बदलाव से सामान और सर्विस दोनों को शामिल करके प्रोड्यूसर-लेवल की महंगाई का ज्यादा व्यापक और सटीक पैमाना मिलेगा।

RBI ने रेगुलेटरी और गवर्नेंस सुधारों के साथ को-ऑपरेटिव बैंकिंग की निगरानी को मज़बूत किया

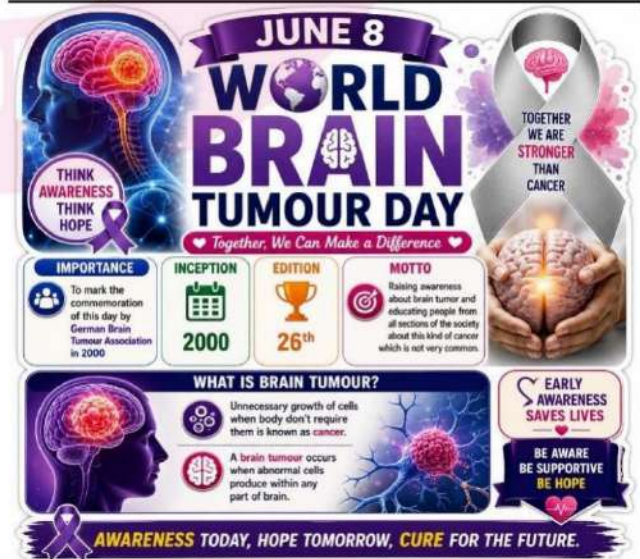
सख्त रेगुलेटरी कार्रवाई: RBI ने श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक (कर्नाटक) का लाइसेंस कैसिल कर दिया और मोगावीरा को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) पर छह महीने की रोक लगा दी, क्योंकि बैंक की फाइनेंशियल हालत खराब थी, कैपिटल काफी नहीं था और कमाई की उम्मीदें भी कम थीं।

डिपॉज़िटर की सुरक्षा: रेगुलेटरी कार्रवाई के बावजूद, योग्य डिपॉज़िटर DICGC इंश्योरेंस के तहत सुरक्षित हैं, जो हर बैंक के हर डिपॉज़िटर को ₹5 लाख तक का कवरेज देता है।

बड़ा गवर्नेंस सुधार: RBI ने अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों (UCB) के लिए गवर्नेंस के नियम कड़े कर दिए हैं, जिसमें डायरेक्टरों का लगातार कार्यकाल 10 साल तक सीमित कर दिया गया है और उन्हें तीन साल के ज़रूरी कूलिंग-ऑफ़ पीरियड के बाद ही दोबारा नियुक्ति के लिए योग्य बनाया गया है।

यह सुधार क्यों? नए नियमों का मकसद डायरेक्टरों को बार-बार इस्तीफ़ा देने और दोबारा नियुक्ति के ज़रिए अपना कार्यकाल बढ़ाने से रोकना है, जिससे गवर्नेंस, ट्रांसपैरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और बोर्ड की आज़ादी में सुधार होगा।

कानूनी आधार: ये कदम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और RBI (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स – गवर्नेंस) अमेंडमेंट डायरेक्शन्स, 2026 के तहत उठाए गए हैं, ताकि डिपॉज़िटर्स के हितों की रक्षा की जा सके और भारत के को-ऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता को मज़बूत किया जा सके।



हस्ताक्षरित एमओयूज

RBI और स्टेट बैंक ऑफ़ वियतनाम ने सीमा-पार डिजिटल भुगतान और Fintech सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और स्टेट बैंक ऑफ़ वियतनाम (SBV) ने डिजिटल भुगतान, Fintech विकास और सीमा-पार भुगतान कनेक्टिविटी—जिसमें QR कोड-आधारित लेनदेन भी शामिल हैं—में सहयोग को मज़बूत करने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिन्दु:

- देश: भारत, वियतनाम
- संस्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), स्टेट बैंक ऑफ़ वियतनाम (SBV)
- समझौता: डिजिटल भुगतान और Fintech सहयोग पर MoU

फोकस क्षेत्र:

- सीमा-पार डिजिटल भुगतान
- Fintech नवाचार
- QR कोड-आधारित मर्चेट भुगतान
- नियामक समन्वय

पृष्ठभूमि:

- भारत और वियतनाम के बीच वित्तीय और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए गए।
- भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित।
- इसका उद्देश्य निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का समर्थन करना और डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना है।

महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

- सीमा-पार QR कोड-आधारित मर्चेट भुगतान को बढ़ावा देता है।
- डिजिटल भुगतान प्रणालियों और Fintech नवाचार में सहयोग को बढ़ाता है।
- तेज़, सस्ता और पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन संभव बनाता है।
- द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन और निवेश को मज़बूत करता है।
- भारत की व्यापक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विस्तार रणनीति का समर्थन करता है।

RBI के बारे में:

- स्थापना: 1 अप्रैल 1935
- राष्ट्रीयकरण: 1 जनवरी 1949
- मुख्यालय: मुंबई
- गवर्नर: संजय मल्होत्रा
- भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण

स्टेट बैंक ऑफ़ वियतनाम (SBV) के बारे में:

- वियतनाम का केंद्रीय बैंक
- मुख्यालय: हनोई

भारत-वियतनाम संबंध:

2016 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई।

सहयोग के क्षेत्र:

- रक्षा और सुरक्षा
- व्यापार और निवेश
- ऊर्जा और समुद्री सहयोग
- डिजिटल तकनीक
- वियतनाम, भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'इंडो-पैसिफिक विज़न' में एक अहम साझेदार है।

रक्षा मंत्रालय ने भारत फोर्ज के साथ ₹425 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 1.25 MW के 12 मरीन गैस टर्बाइन जेनरेटर (GTG) खरीदने के लिए पुणे की भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ ₹425 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है।

मुख्य बिन्दु:

- कॉन्ट्रैक्ट की कीमत: ₹425 करोड़
- मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय
- कंपनी: भारत फोर्ज लिमिटेड, पुणे
- उपकरण: 1.25 MW के 12 मरीन गैस टर्बाइन जेनरेटर
- इस्तेमाल करने वाला: भारतीय नौसेना
- प्लेटफॉर्म: कोलकाता-क्लास डिस्ट्रॉयर
- खरीद श्रेणी: DAP 2020 के तहत 'बाय (इंडियन)' यानी भारतीय खरीद
- स्वदेशी सामग्री: कम से कम 60%
- उद्देश्य: नौसेना की बिजली उत्पादन क्षमता को मज़बूत करना और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना

पृष्ठभूमि:

- GTG नौसेना प्रणालियों के लिए जहाज पर बिजली की आपूर्ति करते हैं
- इनका इस्तेमाल रडार, हथियारों, नेविगेशन और जहाज के संचालन के लिए किया जाता है
- गैस टर्बाइन ज्यादा क्षमता, छोटे आकार और तेज़ी से शुरू होने की सुविधा देते हैं
- कोलकाता-क्लास डिस्ट्रॉयर (प्रोजेक्ट 15A) में INS कोलकाता, कोच्चि और चेन्नई शामिल हैं
- रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में भारत के प्रयासों का हिस्सा

पश्चिम एशिया में संघर्ष खत्म करने के लिए US-ईरान के बीच 14-सूत्रीय शांति समझौता

US और ईरान ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के मकसद से 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता तुरंत लड़ाई रोकने, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे रणनीतिक समुद्री रास्तों को फिर से

खोलने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक व्यवस्थित राजनयिक प्रक्रिया शुरू करने पर केंद्रित है।

मुख्य बिन्दु:

- घटना: US-ईरान 14-सूत्रीय शांति समझौता (MoU)
- नेता: डोनाल्ड ट्रंप (US राष्ट्रपति) और मसूद पेजेशकियन (ईरान के राष्ट्रपति)
- उद्देश्य: पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करना और क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करना
- मुख्य प्रावधान: होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना
- परमाणु प्रतिबद्धता: ईरान परमाणु हथियार बनाने से दूर रहेगा (रूपरेखा के आधार पर)
- बातचीत की समय-सीमा: 60-दिन की शांति वार्ता प्रक्रिया
- प्रतिबंधों का मुद्दा: चरणों में प्रतिबंधों में ढील और आर्थिक सामान्यीकरण
- मध्यस्थ: पाकिस्तान ने US और ईरान के बीच बातचीत में मदद की
- फोकस: ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता

पृष्ठभूमि:

- पश्चिम एशिया संघर्ष-प्रवण क्षेत्र है जो वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करता है
- होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल शिपिंग का एक महत्वपूर्ण 'चोकपॉइंट' है (लगभग 20% तेल व्यापार)
- US-ईरान के बीच तनाव मुख्य रूप से परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों के कारण है
- प्रतिबंधों ने वैश्विक ऊर्जा कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है
- IAEA अंतरराष्ट्रीय ढांचे के तहत परमाणु नियमों के पालन की निगरानी करता है

अन्य मुख्य तथ्य:

- होर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है
- IAEA: इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मुख्यालय वियना में (1957)
- ईरान की राजधानी: तेहरान | मुद्रा: ईरानी रियाल
- US राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रंप
- ईरान के राष्ट्रपति: मसूद पेजेशकियन
- मध्यस्थ देश: पाकिस्तान
- भारत पर प्रभाव: कच्चे तेल की कम कीमतें, बेहतर CAD (चालू खाता घाटा), महंगाई पर नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा
- महत्व: वैश्विक ऊर्जा स्थिरता, व्यापार सुरक्षा, परमाणु अप्रसार

भारत और जापान ने जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (JCM) के लिए लागू करने के नियम अपनाए

भारत और जापान ने पेरिस समझौते के आर्टिकल 6.2 के तहत जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (JCM) के लिए लागू करने के नियम (RoI) अपनाए हैं, जिससे कार्बन मार्केट और जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों में दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा।

मुख्य बिन्दु:

- देश: भारत और जापान
- मैकेनिज्म: जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म (JCM)
- फ्रेमवर्क: पेरिस समझौते का आर्टिकल 6.2
- अपनाने की तारीख: 8 जून 2026
- उद्देश्य: कार्बन क्रेडिट बनाना और उत्सर्जन कम करना
- फोकस: जलवायु परिवर्तन को कम करना, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट

पृष्ठभूमि:

- 2025 में भारत और जापान के बीच साइन किए गए MoC पर आधारित
- JCM उत्सर्जन कम करने वाले प्रोजेक्ट्स से कार्बन क्रेडिट शेयर करने में मदद करता है
- नेशनली डिटरमिन्ड कंटीरिब्यूशन्स (NDCs) को लागू करने में मदद करता है
- कम कार्बन वाली टेक्नोलॉजी और ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है
- गवर्नेंस के लिए एक जॉइंट कमिटी के माध्यम से काम करता है

अन्य मुख्य तथ्य:

- आर्टिकल 6.2 उत्सर्जन में कमी (ITMOs) के इंटरनेशनल ट्रांसफर की अनुमति देता है
- आर्टिकल 6.4 UN की देखरेख में ग्लोबल कार्बन मार्केट बनाता है
- JCM को जापान ने 2011 में शुरू किया था, अब इसमें 30 से ज्यादा पार्टनर देश हैं
- क्लाइमेट फाइनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन टेक्नोलॉजी पर फोकस
- भारत का लक्ष्य पेरिस समझौते के तहत 2070 तक नेट जीरो हासिल करना है
- पेरिस समझौता 2015 में UNFCCC फ्रेमवर्क के तहत अपनाया गया था

किशाऊ मल्टी-पर्पस डैम प्रोजेक्ट के लिए छह राज्य MoU पर साइन करने को तैयार

छह उत्तरी राज्य, यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी 'टोंस' पर बनने वाले किशाऊ मल्टी-पर्पस डैम प्रोजेक्ट के लिए MoU पर साइन करने को तैयार हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद पानी का मैनेजमेंट, सिंचाई और पनबिजली (हाइड्रोपावर) उत्पादन को बेहतर बनाना है।

मुख्य बिन्दु:

- प्रोजेक्ट: किशाऊ मल्टी-पर्पस डैम प्रोजेक्ट
- नदी: टोंस नदी (यमुना की सहायक नदी)
- राज्य: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
- मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय
- मकसद: पानी का बंटवारा, पनबिजली, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण

- इंस्टॉलड कैपेसिटी: 660 MW

पृष्ठभूमि:

- टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है
- राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दों के कारण यह प्रोजेक्ट लंबे समय से रुका हुआ था
- इसका मकसद यमुना नदी बेसिन मैनेजमेंट को मजबूत करना है
- यह उत्तरी राज्यों के बीच सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को बढ़ावा देता है
- यह पीने के पानी की सप्लाई और खेती की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है

भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को 'व्यापक साझेदारी' (Comprehensive Partnership) के स्तर पर पहुँचाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रातिस्लावा यात्रा के दौरान, भारत और स्लोवाकिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाया है। साथ ही, कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और आतंकवाद-रोधी (counter-terrorism) मामलों पर एक 'संयुक्त कार्य समूह' (Joint Working Group) का गठन किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- देश: भारत और स्लोवाकिया
- विकास: व्यापक साझेदारी (Comprehensive Partnership) का दर्जा मिला
- यात्रा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ब्रातिस्लावा)
- नई व्यवस्था: आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह (JWG)
- उद्देश्य: सुरक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना
- फोकस: आतंकवाद-रोधी उपाय, डिजिटल तकनीक, शिक्षा, AI और बुनियादी ढांचा (infrastructure)

पृष्ठभूमि:

- संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा घोषित आतंकवादी संगठनों (UNSC 1267) के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता
- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को गहरा करने का लक्ष्य
- लोगों के बीच और संस्थागत संबंधों को मजबूत करना
- रणनीतिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर जोर

अन्य मुख्य तथ्य:

- MoU के क्षेत्र: डिजिटल तकनीक, श्रम प्रवास (labour migration), उच्च शिक्षा, क्रांति संचार, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा
- AI पहल: टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोसिसे (Technical University of Kosice) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए पहली ICCR चेयर
- शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग: IIT दिल्ली और स्लोवाक टेक्निकल यूनिवर्सिटी
- विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग: इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी (INSA) और स्लोवाक एकेडमी ऑफ़ साइंसेज (SAS)

- स्लोवाकिया की राजधानी: ब्रातिस्लावा

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी GNSS जैमर का ₹449 करोड़ का सौदा किया

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए एडवांस्ड GNSS जैमर खरीदने के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ ₹449 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।

ये सिस्टम दुश्मन के नेविगेशन सिग्नल में रुकावट डालकर और उन्हें गलत जानकारी (spoofing) देकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

मुख्य बिंदु:

- कॉन्ट्रैक्ट की कीमत: ₹449 करोड़
- खरीदार: रक्षा मंत्रालय
- इस्तेमाल करने वाला: भारतीय नौसेना
- सप्लायर: एकोर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
- उपकरण: 20 ECGNSS (एनहैस्ड कैपेबिलिटी GNSS) जैमर
- कैटेगरी: खरीद (भारतीय-IDDM)
- स्वदेशी कंटेंट: कम से कम 75%

GNSS और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में:

- GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) सैटेलाइट-आधारित पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विस देता है
- प्रमुख सिस्टम में GPS, GLONASS, गैलीलियो और बेईडौ (BeiDou) शामिल हैं
- ECGNSS जैमर दुश्मन के नेविगेशन सिग्नल में रुकावट डाल सकते हैं, उन्हें कमजोर कर सकते हैं और गलत जानकारी (spoofing) दे सकते हैं
- इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) दुश्मन के सिस्टम का पता लगाने, उनसे बचाव करने या उन पर हमला करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करता है
- जैमिंग आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक हमले की एक प्रमुख तकनीक है

भारतीय नौसेना के बारे में:

- मुख्यालय: नई दिल्ली
- चीफ ऑफ नेवल स्टाफ: दिनेश के. त्रिपाठी
- आदर्श वाक्य: "शं नो वरुणः" (Sham No Varunah)
- समुद्री सुरक्षा और नौसेना ऑपरेशन्स के लिए जिम्मेदार

निष्कर्ष:

₹449 करोड़ का GNSS जैमर सौदा भारत की स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता को मजबूत करता है और आधुनिक नौसेना युद्ध के लिए आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के अनुरूप है।

अडानी पोर्ट्स को अर्जेंटीना के पहले LNG एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ) को अर्जेंटीना के पहले LNG एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 10 साल का मरीन सर्विसेज़ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट APSEZ की दक्षिण अमेरिकी बाज़ार में एंटी और ग्लोबल मरीन सर्विसेज़ में उसकी मौजूदगी को बढ़ाता है।

मुख्य बिंदु:

- चर्चा में कंपनी: अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ)
- कॉन्ट्रैक्ट की अवधि: 10 साल
- प्रोजेक्ट: अर्जेंटीना का पहला LNG एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट
- विस्तार का क्षेत्र: दक्षिण अमेरिका
- निवेश की प्रतिबद्धता: 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर

पृष्ठभूमि:

- यह कॉन्ट्रैक्ट अर्जेंटीना स्थित मेरिडियन ग्रुप के साथ साझेदारी में APSEZ की सब्सिडियरी कंपनी को दिया गया था।
- यह सदर्न एनर्जी FLNG (फ्लोटिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस) प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा।
- यह प्रोजेक्ट APSEZ की दक्षिण अमेरिकी बाज़ार में एंटी का प्रतीक है।
- अर्जेंटीना के पहले ऑपरेशनल LNG एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट से अपने पहले चरण में सालाना लगभग 2.45 मिलियन टन LNG के उत्पादन की उम्मीद है।

APSEZ के बारे में:

- स्थापना: 1998।
- मुख्यालय: अहमदाबाद, गुजरात।
- पैरेंट ग्रुप: अडानी ग्रुप।
- चेयरमैन: गौतम अडानी।
- भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी और प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर।

भारत-ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) लागू हुआ

भारत-ओमान CEPA लागू हो गया है, जिससे दोनों देशों के बीच बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा, आपसी व्यापार और निवेश बढ़ेगा और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।

मुख्य बिंदु:

- समझौता: भारत-ओमान CEPA
- हस्ताक्षर: 18 दिसंबर 2025, मस्कट
- लागू होने की तारीख: 1 जून 2026
- आपसी व्यापार (वित्त वर्ष 2024-25): US\$ 10.6 बिलियन
- UAE के बाद ओमान भारत के साथ CEPA पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा GCC देश बन गया है।

पृष्ठभूमि:

- भारत को ओमान की 98.08% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिला, जिसमें भारतीय निर्यात का 99% से अधिक हिस्सा शामिल है।

- इसमें सामान, सेवाओं, निवेश, कस्टम सहयोग और रेगुलेटरी सुविधा का व्यापार शामिल है।
- लाभान्वित क्षेत्र: टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, कृषि और खेल का सामान।
- CEPA के तहत पहली खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से निर्यात की गई।

ओमान:

- राजधानी: मस्कट
- मुद्रा: ओमानी रियाल
- सुल्तान: हैथम बिन तारिक

GCC सदस्य:

बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE

महत्व:

- खाड़ी क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ाता है।
- MSME, मैनुफैक्चरर्स, किसानों और सर्विस प्रोवाइडर्स को लाभ पहुंचाता है।
- व्यापार में विविधता लाने और रोजगार पैदा करने में मदद करता है।

निष्कर्ष:

भारत-ओमान CEPA एक बड़ा व्यापार समझौता है जो निर्यात, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा और साथ ही खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करेगा।

भारत और दक्षिण अफ्रीका AI और भविष्य की तकनीकों में सहयोग बढ़ा रहे हैं

भारत और दक्षिण अफ्रीका ने टिकाऊ विकास और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल तकनीकों, इनोवेशन और एडवांस्ड वैज्ञानिक रिसर्च में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है।

मुख्य बिंदु:

- देश: भारत और दक्षिण अफ्रीका
- फोकस क्षेत्र: AI, डिजिटल तकनीकें, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट
- उद्देश्य: तकनीकी सहयोग, कौशल विकास और इनोवेशन

पृष्ठभूमि:

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

राजनयिक संबंध: 1993 में स्थापित।

दोनों देश इनके सदस्य हैं:

- BRICS
- G20
- IBSA

IBSA (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच):

- स्थापना: 2003
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है

दक्षिण अफ्रीका:

- राजधानियां: प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लोमफ़ोन्टेन

- मुद्रा: दक्षिण अफ्रीकी रैंड (ZAR)
- सबसे बड़ा शहर: जोहान्सबर्ग

निष्कर्ष:

भारत-दक्षिण अफ्रीका तकनीकी साझेदारी उभरती हुई तकनीकों में इनोवेशन, रिसर्च सहयोग और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देगी।

भारत-जर्मनी वैज्ञानिक सहयोग: द्विपक्षीय संबंधों का सबसे मज़बूत आधार

भारत और जर्मनी संयुक्त शोध, एकेडमिक आदान-प्रदान और उभरती हुई तकनीकों में साझेदारी के ज़रिए विज्ञान, तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को लगातार मज़बूत कर रहे हैं।

मुख्य बिन्दु:

- देश: भारत और जर्मनी
- मुख्य क्षेत्र: AI, स्वच्छ ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास)
- रणनीतिक साझेदारी: 2000 से
- राजनयिक संबंध: 1951 में स्थापित

जर्मनी:

- राजधानी: बर्लिन
- मुद्रा: यूरो (€)
- चांसलर: फ्रेडरिक मर्ज़
- EU, NATO और G7 का सदस्य

इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (IGSTC):

- मुख्यालय: नई दिल्ली
- औद्योगिक शोध और तकनीक के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देता है

भारत-म्यांमार ने व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सीमा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाईंग ने नई दिल्ली में व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास में सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत की।

मुख्य बिन्दु:

- देश: भारत और म्यांमार
- मुख्य क्षेत्र: व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, सीमा प्रबंधन
- म्यांमार के राष्ट्रपति: मिन आंग ह्लाईंग
- भारत की नीति: नेबरहुड फर्स्ट (पड़ोसी पहले) और एकट ईस्ट पॉलिसी

पृष्ठभूमि:

- म्यांमार ने भरोसा दिलाया कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं किया जाएगा।
- दोनों देश व्यापार, निवेश, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, AI और अहम टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

- दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेज़ी लाने का वादा किया।

भारत के लिए महत्व:

- म्यांमार दक्षिण-पूर्व एशिया और ASEAN के लिए भारत का प्रवेश द्वार है।
- बेहतर सीमा प्रबंधन से उग्रवाद, अवैध प्रवास, तस्करी और मानव तस्करी से निपटने में मदद मिलती है।
- म्यांमार एकमात्र ASEAN देश है जिसकी ज़मीनी सीमा भारत से लगती है।

अन्य मुख्य तथ्य:

- भारत-म्यांमार सीमा: 1,643 किमी
- सीमावर्ती राज्य: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम
- म्यांमार की राजधानी: नेपीटा (Naypyidaw)
- मुद्रा: क्यात (Kyat)

मुख्य प्रोजेक्ट्स:

- कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट
- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे
- निष्कर्ष
- म्यांमार भारत की एकट ईस्ट पॉलिसी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सीमा सुरक्षा के लक्ष्यों के लिए एक अहम रणनीतिक साझेदार बना हुआ है।

यूक्रेन और स्वीडन ने रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए घोषणा पर हस्ताक्षर किए

यूक्रेन और स्वीडन ने चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच सैन्य संबंधों को मज़बूत करने, रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और समर्थन का विस्तार करने के लिए 'बढ़ी हुई सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा' पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुख्य बिन्दु:

- देश: यूक्रेन, स्वीडन
- समझौता: रक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा

फोकस क्षेत्र:

- रक्षा-औद्योगिक सहयोग
- वायु रक्षा प्रणालियाँ
- ड्रोन युद्ध सहयोग
- सैन्य सहायता
- स्वीडन की सैन्य सहायता: ~\$2.7 बिलियन का पैकेज

महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

- रक्षा-औद्योगिक सहयोग और हथियारों की आपूर्ति का विस्तार।
- UAV (ड्रोन) विकास के लिए "ड्रोन डील" ढाँचे के तहत सहयोग।
- बहु-स्तरीय वायु-रक्षा प्रणालियों को मज़बूत करना।
- बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का मुकाबला करने पर फोकस।
- स्वीडन ने \$2.7 बिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की।

इसमें शामिल हैं:

- ड्रोन उत्पादन में सहायता
- वायु-रक्षा प्रणालियाँ
- लड़ाकू विमानों में सहयोग

ग्रीपेन लड़ाकू विमान सहयोग:

- स्वीडन यूक्रेन को 16 Saab JAS 39 Gripen C/D जेट दान करेगा।
- यूक्रेन भविष्य में 20 तक Gripen E मॉडल खरीदने की योजना बना रहा है।
- यूक्रेनी पायलट और तकनीशियन प्रशिक्षण ले रहे हैं।
- इससे यूक्रेन की हवाई युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

"ड्रोन डील" क्या है?

- ड्रोन प्रौद्योगिकी और उत्पादन में सहयोग के लिए एक ढाँचा।

फोकस के क्षेत्र:

- रक्षा नवाचार
- ड्रोन निर्माण
- आधुनिक युद्धक्षेत्र प्रणालियाँ
- निगरानी और युद्धक क्षमता में वृद्धि

भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य को फिर से दोहराया

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की यात्रा के दौरान, भारत और कनाडा ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के अपने लक्ष्य को फिर से दोहराया है।

मुख्य बिन्दु:

- देश: भारत और कनाडा
- व्यापार लक्ष्य: 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर
- मुख्य बिंदु: CEPA वार्ता
- वर्तमान व्यापार: लगभग 17 अरब अमेरिकी डॉलर
- CEPA का लक्ष्य: 2026 के अंत तक

पृष्ठभूमि:

- भारत और कनाडा व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) पर बातचीत कर रहे हैं।
- CEPA एक पारंपरिक FTA (मुक्त व्यापार समझौता) से अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें निवेश और आर्थिक सहयोग भी शामिल है।

CEPA के बारे में:

शामिल विषय:

- वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार
- निवेश संवर्धन
- बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
- सीमा शुल्क सहयोग
- डिजिटल व्यापार
- आर्थिक सहयोग

महत्व:

- आर्थिक और निवेश संबंधों को मजबूत करता है।
- व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करता है।
- आपूर्ति-श्रृंखला की मजबूती (resilience) को बढ़ाता है।
- प्रौद्योगिकी साझेदारी और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है।
- भारत-कनाडा आर्थिक संबंधों में गति वापस लाने में मदद करता है।

भारत-कनाडा व्यापार:

भारत के प्रमुख निर्यात:

- फार्मास्यूटिकल्स (दवाएं)
- वस्त्र
- इंजीनियरिंग उत्पाद
- रसायन

कनाडा से प्रमुख आयात:

- दालें
- उर्वरक
- लकड़ी के उत्पाद
- खनिज

महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों पर भारत-अमेरिका सहयोग

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भविष्य की तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा के लिए सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने हेतु महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के क्षेत्र में अपना सहयोग और मजबूत किया है।

मुख्य बिंदु:

- देश: भारत और अमेरिका
- क्षेत्र: महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ मृदा तत्व
- मुख्य ध्यान: खनन, प्रसंस्करण, शोधन और आपूर्ति श्रृंखलाएं
- चर्चा करने वाले: एस. जयशंकर और मार्को रूबियो
- अवसर: क्राड विदेश मंत्रियों की बैठक

पृष्ठभूमि:

- महत्वपूर्ण खनिज स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
- वर्तमान में, दुर्लभ मृदा तत्वों के वैश्विक प्रसंस्करण और शोधन पर चीन का वर्चस्व है।

दुर्लभ मृदा तत्वों (REEs) के बारे में:

17 धात्विक तत्वों का एक समूह।

इनमें उपयोग होता है:

- पवन टर्बाइन
- इलेक्ट्रिक मोटर
- स्मार्टफोन
- मिसाइलें
- लड़ाकू विमान

अन्य मुख्य तथ्य:

- भारत ने वर्ष 2023 में महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की।

- भारत 'खनिज सुरक्षा भागीदारी' (Minerals Security Partnership) का सदस्य है।
- दुर्लभ मृदा तत्वों के वैश्विक शोधन पर चीन का वर्चस्व है।

निष्कर्ष:

भारत-अमेरिका की यह साझेदारी महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को सुरक्षित करने, रणनीतिक उद्योगों को मजबूत बनाने और वैश्विक स्तर पर मौजूद कमजोर आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करने में सहायक सिद्ध होगी।

भारत और जापान एक मज़बूत और समृद्ध इंडो-पैसिफिक के लिए सहयोग जारी रखे हुए हैं

जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी की नई दिल्ली यात्रा के दौरान, भारत और जापान ने एक स्वतंत्र, खुला और समृद्ध इंडो-पैसिफिक क्षेत्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

मुख्य बिन्दु:

- देश: भारत और जापान
- ढांचा: स्वतंत्र और खुला इंडो-पैसिफिक (FOIP)
- स्थान: नई दिल्ली
- मुख्य विषय: समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन
- अवसर: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक

पृष्ठभूमि:

- भारत और जापान के बीच 2014 से 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' है।
- दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1952 में स्थापित हुए थे।
- दोनों देश एक स्थिर, नियमों पर आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और मज़बूत वैश्विक सप्लाई चेन का समर्थन करते हैं।

उभरते क्षेत्रों में सहयोग:

- महत्वपूर्ण खनिज
- स्वच्छ ऊर्जा
- उन्नत टेक्नोलॉजी
- सेमीकंडक्टर
- आर्थिक सुरक्षा

FOIP के बारे में:

- FOIP का पूरा नाम 'स्वतंत्र और खुला इंडो-पैसिफिक' (Free and Open Indo-Pacific) है।

जापान का रणनीतिक दृष्टिकोण:

- नौवहन की स्वतंत्रता
- खुला व्यापार
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी
- सतत विकास
- नियमों पर आधारित अंतराष्ट्रीय व्यवस्था
- यह भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का पूरक है।

क्वाड (Quad) के बारे में:

- इन देशों का रणनीतिक समूह:

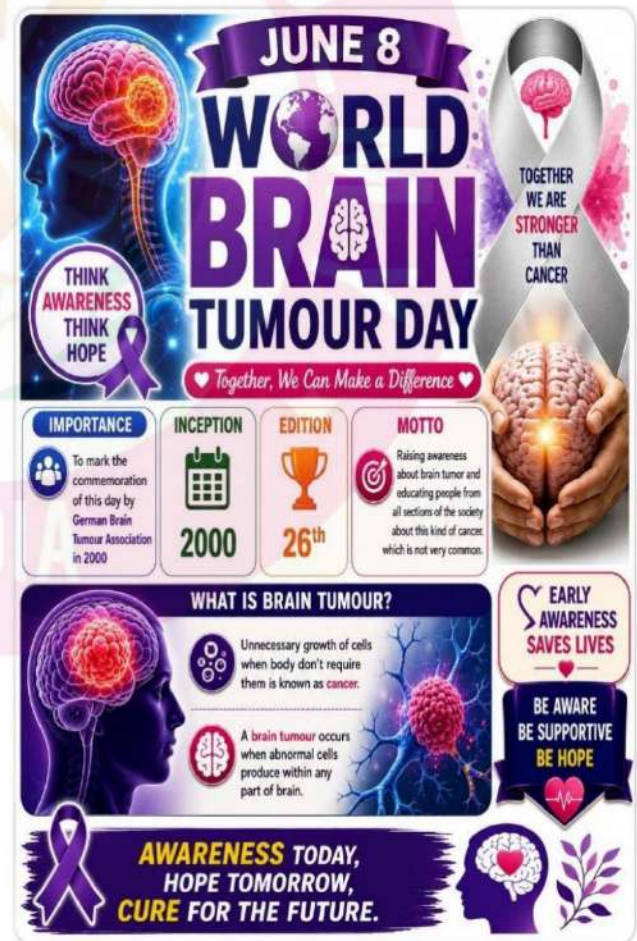
- भारत
- जापान
- संयुक्त राज्य अमेरिका
- ऑस्ट्रेलिया

मुख्य विषय:

- समुद्री सुरक्षा
- आपदा राहत कार्य
- महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी
- सप्लाई चेन की मज़बूती
- क्षेत्रीय स्थिरता

महत्व:

- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को मज़बूत करता है।
- आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देता है।
- मज़बूत सप्लाई चेन को प्रोत्साहित करता है।
- नौवहन की स्वतंत्रता और अंतराष्ट्रीय कानून का समर्थन करता है।
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भागीदारी को और गहरा करता है।



पुरस्कार एवं सम्मान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, खेल, सिनेमा, साहित्य और सार्वजनिक जीवन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए।

मुख्य बिन्दु:

- कार्यक्रम: पद्म पुरस्कार 2026 (दूसरा नागरिक सम्मान समारोह)
- स्थान: राष्ट्रपति भवन
- राष्ट्रपति: द्रौपदी मुर्मू
- कुल पुरस्कार प्राप्तकर्ता (दूसरा समारोह): 65
- श्रेणियाँ: 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण, 56 पद्म श्री
- कुल पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता (2026): 131
- घोषणा की तारीख: गणतंत्र दिवस 2026

प्रमुख पुरस्कार प्राप्तकर्ता:

- अलका यात्रिक – पद्म भूषण
- विजय अमृतराज – पद्म भूषण
- रोहित शर्मा – पद्म श्री
- ममूटी – पद्म भूषण
- आर. माधवन – पद्म श्री
- सविता पूनिया – पद्म श्री

पृष्ठभूमि:

- पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं
- हर साल तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री
- कला, खेल, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक मामलों आदि में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं
- सिफारिशों की समीक्षा पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जाती है

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी
- नोडल मंत्रालय: गृह मंत्रालय
- हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषणा की जाती है
- भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसके बाद पद्म पुरस्कार आते हैं
- चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा जांच शामिल होती है

19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (MIFF) 2026 संपन्न

MIFF 2026 मुंबई में संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन कैटेगरी में दुनिया भर से लोगों ने हिस्सा लिया। पोलिश डॉक्यूमेंट्री 'सिल्वर' (Silver) ने बेस्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए 'गोल्डन कॉच' (Golden Conch) अवॉर्ड जीता।

मुख्य बिन्दु:

- इवेंट: 19वां MIFF 2026
- जगह: मुंबई, महाराष्ट्र
- आयोजक: NFDC | सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of I&B)
- मुख्य अवॉर्ड: गोल्डन कॉच
- विजेता: सिल्वर (पोलैंड), डायरेक्टर: नतालिया कोनियार्ज़ (Natalia Koniarz)
- इनाम: ₹10 लाख

अन्य विजेता:

- इंटरनेशनल शॉर्ट फिक्शन: अंडर द स्नो (ईरान)
- इंटरनेशनल एनिमेशन: मायाज़ सॉन (जर्मनी)
- इंडियन डॉक्यूमेंट्री: वाई (Waii)
- इंडियन शॉर्ट फिक्शन: स्मॉल क्लाउड्स
- इंडियन एनिमेशन: आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगालम्पन टेम्पल स्ट्रीट

पृष्ठभूमि:

- स्थापना: 1990
- फोकस: डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन
- दक्षिण एशिया के सबसे पुराने नॉन-फिक्शन फिल्म फेस्टिवल्स में से एक

अन्य मुख्य तथ्य:

- कई कैटेगरी में 'सिल्वर कॉच' अवॉर्ड दिया गया
- NFDC (1975) भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देता है और उसे फाइनेंस करता है
- CBFC भारत में फिल्मों के सर्टिफिकेशन का काम देखता है
- FIAPF (पेरिस) इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स को मान्यता देता है
- डॉक्यूमेंट्री फिल्में असल ज़िंदगी के मुद्दों और जागरूकता पर फोकस करती हैं

नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी को 'बेस्ट एथलीट ऑफ़ द ईयर' चुना गया

पहले 'इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स' में ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और स्टीपलचेज़र रनर पारुल चौधरी को क्रमशः 'बेस्ट मेल एथलीट' और 'बेस्ट फीमेल एथलीट' चुना गया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित इन अवार्ड्स में 2025 एथलेटिक्स सीज़न में शानदार प्रदर्शन को सम्मानित किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- इवेंट: इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स (पहला संस्करण)
- आयोजक: एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (AFI)
- बेस्ट मेल एथलीट: नीरज चोपड़ा
- बेस्ट फीमेल एथलीट: पारुल चौधरी
- कुल कैटेगरी: 10
- सम्मानित सीज़न: 2025 एथलेटिक्स सीज़न



पृष्ठभूमि:

- AFI द्वारा इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स शुरू किए गए
- मकसद: एथलीटों, कोचों, अधिकारियों, मेंटर्स और राज्य संघों को सम्मानित करना
- भारतीय एथलेटिक्स में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर फोकस
- पहला संस्करण भारत में एथलेटिक्स उपलब्धियों के लिए औपचारिक सम्मान का मंच है

अन्य मुख्य तथ्य:

- लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड: पी. टी. उषा
- पी. टी. उषा इंडियन ओलंपिक कमेटी (IOA) की प्रेसिडेंट हैं

जैनेंद्र के. जैन ने भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार जीता

प्रोफेसर जैनेंद्र के. जैन भौतिकी में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिक विज्ञानी बन गए हैं। उन्हें 'कम्पोजिट फर्मियन्स' (Composite Fermions) की अवधारणा पर उनके अभूतपूर्व काम के लिए सम्मानित किया गया, जिसने क्वांटम पदार्थ (quantum matter) की समझ को बदल दिया।

मुख्य बिन्दु:

- पुरस्कार: भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार

- किसे मिला: जैनेंद्र के. जैन
- किसके द्वारा दिया गया: वुल्फ फाउंडेशन, इज़राइल
- किसने प्रदान किया: इज़राइली राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग
- उपलब्धि: यह पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिक विज्ञानी
- मुख्य योगदान: कम्पोजिट फर्मियन्स की खोज
- खोज का वर्ष: 1989 (येल यूनिवर्सिटी, पोस्टडॉक्टरल रिसर्च)

पृष्ठभूमि:

- वुल्फ पुरस्कार की स्थापना 1978 में हुई
- विज्ञान और कला में उत्कृष्टता को मान्यता देता है
- दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कारों में से एक माना जाता है
- कई प्राप्तकर्ता बाद में नोबेल पुरस्कार भी जीतते हैं
- यह पुरस्कार भौतिकी और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में बड़े योगदान को उजागर करता है
- सह-लेखक: 'कम्पोजिट फर्मियन्स' पुस्तक
- ओलिवर ई. बकले पुरस्कार प्राप्तकर्ता
- कम्पोजिट फर्मियन थ्योरी 'फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट' की व्याख्या करती है

सुदर्शन पटनायक रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बने

मशहूर भारतीय सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक रूस के कलनिनग्राद में आयोजित एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में क्लाइमेट (जलवायु) पर आधारित अपनी सैंड स्कल्पचर (रेत की कलाकृति) के लिए रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

मुख्य बिन्दु:

- अवॉर्ड: रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026
- विजेता: सुदर्शन पटनायक
- उपलब्धि: यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय
- जगह: कलनिनग्राद क्षेत्र, रूस
- थीम: ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण
- स्कल्पचर: जलवायु में अंतर को दिखाने वाली 3-मीटर की रेत की कलाकृति

अन्य मुख्य तथ्य:

- सुदर्शन पटनायक का जन्म: 15 अप्रैल 1977, ओडिशा
- बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के पुरी बीच पर सैंड आर्ट की शुरुआत की
- सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की (1994)
- 2014 में पद्म श्री से सम्मानित
- 2017 में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया
- कई इंटरनेशनल अवॉर्ड और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर

राष्ट्रपति मुर्मू ने सशस्त्र बलों, CAPF और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'फेज-I डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2026' के दौरान सशस्त्र बलों, CAPF और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। कुल 51 वीरता पुरस्कार दिए गए।

मुख्य बिंदु:

- कार्यक्रम: फेज-I डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2026
- स्थान: राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
- पुरस्कार प्रदान करने वाली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
- कुल वीरता पुरस्कार: 51
- पुरस्कार पाने वाले: सशस्त्र बल, CAPF और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मी

पृष्ठभूमि:

- 7 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए, जिनमें 2 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं।
- 15 वीर चक्र प्रदान किए गए, जिनमें 3 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं।
- 29 शौर्य चक्र प्रदान किए गए, जिनमें 1 मरणोपरांत पुरस्कार शामिल है।
- कीर्ति चक्र पाने वालों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, मेजर अर्शदीप सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी और डिप्टी कमांडेंट पवन कुमार शामिल थे।

वीरता पुरस्कारों का क्रम:

शांति-काल के पुरस्कार

1. अशोक चक्र – शांति-काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार।
2. कीर्ति चक्र – शांति-काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार।
3. शौर्य चक्र – शांति-काल का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार।

युद्ध-काल के पुरस्कार

1. परम वीर चक्र – युद्ध-काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार।
2. महावीर चक्र – युद्ध-काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार।
3. वीर चक्र – युद्ध-काल का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार।

निष्कर्ष:

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2026 में सशस्त्र बलों, CAPF और पुलिस बलों के कर्मियों के असाधारण साहस और सेवा को मान्यता देते हुए 51 वीरता पुरस्कार प्रदान किए।

51 कलाकारों को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिले

संगीत, नृत्य, थिएटर और लोक कलाओं में योगदान के लिए लगभग 51 कलाकारों को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार 2021-2024 की अवधि के लिए दिए गए।

मुख्य बिन्दु:

- पुरस्कार: उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
- पुरस्कार पाने वाले: 51 कलाकार
- शामिल वर्ष: 2021-2024
- स्थान: लोक भवन, लखनऊ

पृष्ठभूमि:

- पुरस्कार ब्रजेश पाठक ने प्रदान किए।
- संगीत, नृत्य, थिएटर और लोक कलाओं में बेहतरीन काम को मान्यता दी गई।
- सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कला रूपों के संरक्षण को बढ़ावा देता है।

प्रमुख पुरस्कार विजेता (2024):

- सफदर हाशमी पुरस्कार: शुभदीप राहा (लखनऊ)
- बीएम शाह पुरस्कार: संजय मेहता (भोपाल)

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के बारे में:

- मुख्यालय: लखनऊ
- क्षेत्र: संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाएं
- उद्देश्य: प्रदर्शन कलाओं को बढ़ावा देना और उनका संरक्षण करना

भारतीय किशोरों ने इमली के बीज से बने माइक्रोप्लास्टिक फ़िल्टर के लिए 'द अर्थ प्राइज़ 2026' जीता

तीन भारतीय किशोरों ने "प्लास-स्टिक" (Plas-Stick) विकसित करने के लिए 'द अर्थ प्राइज़ 2026' जीता। यह एक सस्ता और नया समाधान है जो इमली के बीज के कचरे का इस्तेमाल करके दूषित पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाता है। वे यह ग्लोबल अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय टीम बन गए हैं।

मुख्य बिन्दु:

- विजेता: विवान छावछरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता
- अवॉर्ड: द अर्थ प्राइज़ 2026
- इनोवेशन: प्लास-स्टिक
- उपलब्धि: ग्लोबल अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय टीम

पृष्ठभूमि:

- प्लास-स्टिक, बेकार इमली के बीजों से बना एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर है।
- यह माइक्रोप्लास्टिक कणों को अपनी ओर खींचता है और उन्हें जोड़कर बड़े गुच्छे बनाता है, जिन्हें चुंबक की मदद से हटाया जा सकता है।
- इस तकनीक के लिए बिजली, महंगे फ़िल्टर या हानिकारक केमिकल की ज़रूरत नहीं होती है।
- यह आइडिया ग्रामीण इलाकों में पानी साफ़ करने की चुनौतियों से प्रेरित था।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने इस तकनीक को टेस्ट करने और बेहतर बनाने में मदद की।

अन्य मुख्य तथ्य:

- 'द अर्थ प्राइज़' का आयोजन 'अर्थ फ़ाउंडेशन' करता है।
- हेडक्वार्टर: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड।
- योग्यता: 13-19 साल की उम्र के स्टूडेंट्स।
- 2026 में प्रतिभागी: 169 देश और क्षेत्र।

निष्कर्ष:

प्लास-स्टिक इनोवेशन दिखाता है कि युवा इनोवेटर्स द्वारा विकसित सस्ते और टिकाऊ समाधान कैसे माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की ग्लोबल चुनौती से निपटने और साफ़ पानी तक पहुँच में मदद कर सकते हैं।

मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित UN पुरस्कार मिलेगा

संयुक्त राष्ट्र दो भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत 'डैग हैमरशोल्ड मेडल' से सम्मानित करेगा, जबकि मेजर अभिलाषा बराक को '2025 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर' पुरस्कार मिलेगा।

मुख्य बिन्दु:

- संगठन: संयुक्त राष्ट्र (United Nations)
- मरणोपरांत सम्मान: डैग हैमरशोल्ड मेडल
- पुरस्कार विजेता: मेजर अभिलाषा बराक
- UN मिशन: UNIFIL, लेबनान
- अवसर: UN शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (29 मई)

पृष्ठभूमि:

- भारत UN शांति स्थापना अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है।
- 1948 से अब तक 180 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों ने UN के झंडे तले अपनी जान कुर्बान की है।

महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

डैग हैमरशोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता (मरणोपरांत):

- हरभजन सिंह – MONUSCO के साथ सेवा दी
- सुजीत कुमार प्रधान – UNMISS के साथ सेवा दी

डैग हैमरशोल्ड मेडल के बारे में:

- स्थापना: 1997
- किसके द्वारा दिया जाता है: संयुक्त राष्ट्र
- प्रकृति: UN शांति स्थापना का सर्वोच्च मरणोपरांत सम्मान
- डैग हैमरशोल्ड के नाम पर रखा गया।
- उन कर्मियों को दिया जाता है जो UN शांति स्थापना मिशनों में सेवा करते हुए शहीद हो जाते हैं।

UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार के बारे में:

- स्थापना: 2016
- लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले शांति सैनिकों को सम्मानित करता है।
- संघर्ष क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा और भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

पिछले भारतीय प्राप्तकर्ता:

- मेजर सुमन गवानी – 2019
- मेजर राधिका सेन – 2023
- मेजर अभिलाषा बराक – 2025

UN शांति स्थापना में भारत का योगदान:

- वर्तमान में UN मिशनों में 6,000 से अधिक भारतीय कर्मी तैनात हैं।
- विश्व स्तर पर सबसे बड़े सैनिक योगदानकर्ताओं में से एक।

- 180 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों ने सेवा के दौरान अपनी जान न्योछावर की है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर' से सम्मानित किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गंगटोक में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर' (निशान) से सम्मानित किया। सिक्किम भारत का 15वां राज्य पुलिस बल और पूर्वोत्तर का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

मुख्य बिन्दु:

- पुरस्कार: प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर (निशान)
- प्रदानकर्ता: भारत की राष्ट्रपति
- प्राप्तकर्ता: सिक्किम पुलिस
- स्थान: गंगटोक, सिक्किम
- महत्व: किसी पुलिस बल के लिए सर्वोच्च औपचारिक सम्मान

पृष्ठभूमि:

- प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर असाधारण सेवा, बहादुरी, व्यावसायिकता, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है।
- सम्मानित बल के कर्मियों को अपनी वर्दी की बाईं आस्तीन पर एक विशेष प्रतीक (emblem) धारण करने का अधिकार होता है।

महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

- सिक्किम यह सम्मान प्राप्त करने वाला 15वां राज्य पुलिस बल बन गया है।
- यह पुलिसिंग और जनसेवा में उत्कृष्टता को मान्यता देता है।

प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर के बारे में:

- लोकप्रिय नाम: निशान
- प्रकृति: किसी पुलिस बल के लिए सर्वोच्च औपचारिक सम्मान
- प्रतीक:
- बहादुरी
- अनुशासन
- समर्पण
- व्यावसायिक उत्कृष्टता

सिक्किम पुलिस के बारे में:

- स्थापना: 1897
- मुख्यालय: गंगटोक
- DGP: अक्षय सचदेवा

सिक्किम के बारे में मुख्य तथ्य:

- राजधानी: गंगटोक
- मुख्यमंत्री: प्रेम सिंह तमांग
- राज्यपाल: ओम प्रकाश माथुर
- राज्य स्थापना दिवस: 16 मई 1975
- सर्वोच्च चोटी: कंचनजंगा

खेल -कूद

दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनीं

ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के अभियान के दौरान, भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव खिलाड़ियों में सभी फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं।

मुख्य बिंदु:

- खिलाड़ी: दीप्ति शर्मा
- उपलब्धि: महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी (एक्टिव खिलाड़ी)
- रिकॉर्ड: WT20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी
- मैच की खास बात: पाकिस्तान के खिलाफ 5/10 (ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026)
- पिछला रिकॉर्ड होल्डर (WT20I): मेगन शूट (ऑस्ट्रेलिया)
- भूमिका: ऑलराउंडर (भारत)

अन्य मुख्य तथ्य:

- WT20I: महिला टीमों के बीच इंटरनेशनल T20 मैच (ICC द्वारा मान्यता प्राप्त)
- ICC ने 2018 से सभी सदस्यों को पूर्ण WT20I का दर्जा दिया
- ICC मुख्यालय: दुबई, UAE
- ICC चेयरमैन: जय शाह
- WPL की शुरुआत 2023 में BCCI द्वारा की गई
- दीप्ति का 5/10 भारत के लिए WT20I में सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग आंकड़ों में से एक है

केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने 16 साल से ज्यादा के करियर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

- खिलाड़ी: केन विलियमसन
- देश: न्यूजीलैंड
- संन्यास: इंटरनेशनल क्रिकेट (2026)
- कुल रन: 19,346 इंटरनेशनल रन
- टेस्ट रन: 9,500 से ज्यादा (33 शतक और 6 दोहरे शतक के साथ)

कप्तानी में उपलब्धियां:

- 2019 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप फ़ाइनल
- 2021 T20 वर्ल्ड कप फ़ाइनल
- 2021 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता

भारत का पहले वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में दबदबा

गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित पहले वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ओवरऑल चैंपियन बना। भारत ने कुल 114 मेडल जीते, जिनमें 102 गोल्ड मेडल शामिल थे।

मुख्य बिंदु:

- इवेंट: वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026
- जगह: EKA एरिना, अहमदाबाद, गुजरात
- ओवरऑल चैंपियन: भारत
- कुल मेडल: 114
- मेडल टैली: 102 गोल्ड, 9 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज़

मुख्य हाइलाइट्स:

- मेडल स्टैंडिंग में भारत पहले स्थान पर रहा।
- जापान ने दूसरा स्थान हासिल किया।
- अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर रहा।
- यह पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप इवेंट था।

योगासन के बारे में:

- योग आसनों पर आधारित एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट।
- इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, ताकत और सहनशक्ति का मेल होता है।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में इसे डेमोस्ट्रेशन स्पोर्ट के तौर पर शामिल किया गया था।
- भारत इसे एक ग्लोबल स्पोर्टिंग डिसिप्लिन के तौर पर बढ़ावा दे रहा है।

निष्कर्ष:

भारत ने 114 मेडल जीतकर पहले वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में दबदबा बनाया और ग्लोबल लेवल पर योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के तौर पर बढ़ावा देने में अपनी लीडरशिप को फिर से साबित किया।

भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता

भारत ने फ़ाइनल में बांग्लादेश को हराकर SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता।

मुख्य बिंदु:

- टूर्नामेंट: SAFF महिला चैंपियनशिप 2026
- चैंपियन: भारत
- रनर-अप: बांग्लादेश
- भारत के खिताब: 6 (रिकॉर्ड)
- आयोजन संस्था: SAFF

पृष्ठभूमि:

- भारत ने फ़ाइनल में बांग्लादेश को हराकर SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता।
- यह जीत टूर्नामेंट के इतिहास में भारत का छठा खिताब था, जो किसी भी टीम द्वारा जीते गए सबसे ज्यादा खिताब हैं।
- बांग्लादेश रनर-अप रहा।

- इस चैंपियनशिप में दक्षिण एशिया की प्रमुख महिला फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया।

SAFF के बारे में:

- स्थापना: 1997
- मुख्यालय: ढाका, बांग्लादेश
- अध्यक्ष: काज़ी सलाहुद्दीन
- महासचिव: पुरुषोत्तम कट्टेल
- दक्षिण एशिया में फुटबॉल के लिए गवर्निंग बॉडी।
- एशियन फुटबॉल कॉन्फ़ेडरेशन (AFC) के तहत काम करता है।

मिरा आंद्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता

मिरा आंद्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 में महिलाओं का सिंगल्स खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में पोलैंड की माजा चवालिन्स्का को 6-3, 6-2 से हराया। यह जीत उनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब और एक बड़ी उपलब्धि थी।

मुख्य बिंदु:

- टूर्नामेंट: फ्रेंच ओपन 2026 (महिला सिंगल्स)
- चैंपियन: मिरा आंद्रीवा (रूस)
- रनर-अप: माजा चवालिन्स्का (पोलैंड)
- स्थान: रोलैंड गैरोस, पेरिस, फ्रांस
- सतह: क्ले कोर्ट

फ्रेंच ओपन 2026

- एडिशन: 125वां
- कैटेगरी: ग्रैंड स्लैम
- प्राइज़ मनी: €61,723,000
- जगह: रोलैंड गैरोस स्टेडियम

चैंपियंस:

- मेन्स सिंगल्स: अलेक्जेंडर ज़ेवेरेव
- विमेन्स सिंगल्स: मिरा एंड्रीवा
- मेन्स डबल्स: मार्सेल ग्रैनोलर्स / होरासियो ज़ेबालोस
- विमेन्स डबल्स: कैटरिना सिनियाकोवा / टेलर टाउनसेंट
- मिक्सड डबल्स: सारा एरानी / एंड्रिया वावास्सोरी

आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने नॉर्वे में आयोजित नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट जीता।

मुख्य बिंदु:

- विजेता: आर प्रज्ञानानंद
- इवेंट: नॉर्वे शतरंज 2026
- उपलब्धि: टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय
- स्थान: नॉर्वे

पृष्ठभूमि:

- फाइनल राउंड में विसेंट कीमर (जर्मनी) को हराया।
 - मैग्नस कार्लसन, अलीरेज़ा फिरोज़ा और डी गुकेश जैसे शीर्ष खिलाड़ियों को हराया।
 - विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय बने जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में क्लासिकल शतरंज में मैग्नस कार्लसन को दो बार हराया।
 - 18 अंकों के साथ समापन किया।
- #### नॉर्वे शतरंज के बारे में:
- शुरुआत: 2013
 - स्थान: ओस्लो/स्टावांगर, नॉर्वे
 - सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंटों में से एक।

ICC ने क्रिकेट कनाडा की मेंबरशिप सस्पेंड की

ICC ने गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव नियमों के उल्लंघन के कारण क्रिकेट कनाडा की मेंबरशिप सस्पेंड कर दी है, लेकिन कनाडाई टीम ICC इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए योग्य बनी रहेगी।

मुख्य बिंदु:

- संस्था: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC)
- प्रभावित संस्था: क्रिकेट कनाडा
- कारण: गवर्नेंस और मेंबरशिप से जुड़े नियमों का उल्लंघन
- स्थिति: टीम ICC टूर्नामेंट खेलना जारी रख सकती है

पृष्ठभूमि:

- ICC एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के ज़रिए कनाडाई टीमों को फंडिंग देगा।
- मेंबरशिप की बहाली गवर्नेंस में सुधार पर निर्भर करती है।
- नियमों के पालन की निगरानी ICC नॉर्मलाइज़ेशन कमेटी करेगी।
- 2025 में USA क्रिकेट के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की गई थी।

अन्य मुख्य तथ्य:

- ICC हेडक्वार्टर: दुबई
- ICC चेयरमैन: जय शाह
- कनाडा 1968 में ICC का एसोसिएट मेंबर बना।

भारत एशियन U-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में दूसरे स्थान पर रहा

भारत ने देश के बाहर आयोजित एशियन U-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 19 मेडल के साथ दूसरा स्थान हासिल किया।

मुख्य बिंदु:

- इवेंट: 22वीं एशियन U-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026
- जगह: हांगकांग, चीन
- भारत की रैंक: दूसरी
- मेडल टैली: 10 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज़ (कुल 19)
- टॉप देश: चीन
- तीसरा स्थान: जापान

अन्य मुख्य तथ्य:

- आयोजक: एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन
- पहला संस्करण: 1986
- AFI प्रेसिडेंट: बहादुर सिंह समू
- AFI हेडक्वार्टर: नई दिल्ली
- TOPS लॉन्च: 2014
- खेलो इंडिया लॉन्च: 2018

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 का खिताब बरकरार रखा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 के फ़ाइनल में गुजरात टाइटंस को पाँच विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता।

मुख्य बिन्दु:

- चैंपियन: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
- रनर-अप: गुजरात टाइटंस
- वेन्यू: नरेंद्र मोदी स्टेडियम
- नतीजा: RCB 5 विकेट से जीती
- उपलब्धि: IPL इतिहास में लगातार खिताब जीतने वाली तीसरी टीम

पृष्ठभूमि:

- GT ने 20 ओवर में 155/8 रन बनाए।
- RCB के लिए विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की।
- रसिक डार ने 3 विकेट लिए।
- भुवनेश्वर कुमार और जोश हेज़लवुड ने 2-2 विकेट लिए।

प्रमुख पुरस्कार:

- ऑरेंज कैप और MVP: वैभव सूर्यवंशी (RR)
- पर्पल कैप: कगिसो रबाडा (GT) – 29 विकेट
- इमर्जिंग प्लेयर: वैभव सूर्यवंशी (RR)

अन्य मुख्य तथ्य:

- IPL की शुरुआत 2008 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने की थी।
- हाल के विजेता: KKR (2024), RCB (2025, 2026)

निष्कर्ष:

IPL 2026 में RCB का खिताब बचाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी और इसने लीग की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में अपनी स्थिति को और मजबूत किया।

सिंगापुर ओपन 2026: सात्विक-चिराग ने मेन्स डबल्स का खिताब जीता

भारत की मेन्स डबल्स जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेटी ने सिंगापुर ओपन 2026 का खिताब जीता।

मुख्य बिन्दु:

- चैंपियन: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेटी
- इवेंट: मेन्स डबल्स
- टूर्नामेंट: सिंगापुर ओपन 2026
- रनर-अप: फजर अल्फियान और मुहम्मद शोहिबुल फिकरी (इंडोनेशिया)
- उपलब्धि: भारत का पहला सिंगापुर ओपन मेन्स डबल्स खिताब

पृष्ठभूमि:

- यह लगभग दो साल में उनका पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब था।
- यह खिताब उनके करियर का 9वां BWF वर्ल्ड टूर खिताब था।

अन्य मुख्य तथ्य:

- BWF मुख्यालय: कुआलालंपुर
- BWF प्रेसिडेंट: खुनयिंग पतामा लीसवाइत्राकुल
- BAI प्रेसिडेंट: हिमंत बिस्वा सरमा
- प्रमुख BWF वर्ल्ड टूर कैटेगरी: सुपर 1000, सुपर 750, सुपर 500, सुपर 300, सुपर 100

सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा

भारतीय पैरा-एथलीट सुमित अंतिल ने बेंगलुरु में आयोजित 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया।

मुख्य बिन्दु:

- एथलीट: सुमित अंतिल
- स्पर्धा: पुरुषों की भाला फेंक F64
- स्थान: बेंगलुरु
- नया विश्व रिकॉर्ड: 74.82 मीटर
- पिछला रिकॉर्ड: 73.29 मीटर (एशियाई पैरा गेम्स 2022)

पृष्ठभूमि:

- सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले एक पैरा-एथलीट हैं।
- 2015 में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में उन्होंने घुटने के नीचे अपना बायां पैर खो दिया था।
- उन्होंने कुश्ती से पैरा-एथलेटिक्स में कदम रखा और एक विश्व स्तरीय भाला फेंक खिलाड़ी बन गए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

IAF को सितंबर 2026 में भारत में बना पहला एयरबस C-295 एयरक्राफ्ट मिलेगा

भारतीय वायु सेना (IAF) को सितंबर 2026 में अपना पहला 'मेड-इन-इंडिया' (भारत में बना) एयरबस C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलेगा। वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) और एयरबस द्वारा बनाया गया यह एयरक्राफ्ट, प्राइवेट सेक्टर द्वारा IAF के लिए भारत में तैयार किया गया पहला मिलिट्री एयरक्राफ्ट है।

मुख्य बिन्दु:

- चर्चा में एयरक्राफ्ट: एयरबस C-295
- डिलीवरी: सितंबर 2026
- निर्माता: TASL + एयरबस डिफेंस एंड स्पेस
- निर्माण स्थल: वडोदरा, गुजरात
- कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर: सितंबर 2021
- कॉन्ट्रैक्ट की कीमत: ₹21,935 करोड़
- कुल एयरक्राफ्ट: 56 (16 स्पेन से, 40 भारत में बने)
- उद्देश्य: Avro HS-748 फ्लीट को बदलना और IAF की ट्रांसपोर्ट क्षमता को मजबूत करना।

पृष्ठभूमि:

- एयरबस C-295 एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल सैनिकों और सामान को लाने-ले जाने, मेडिकल निकासी, एयरड्रॉप ऑपरेशन और आपदा राहत कार्यों में किया जाता है।
- यह छोटी और कम तैयार (semi-prepared) एयरस्ट्रिप से भी ऑपरेट कर सकता है, जिससे यह बॉर्डर और आइलैंड वाले इलाकों के लिए उपयुक्त है।
- बाकी बचे 39 'मेड-इन-इंडिया' एयरक्राफ्ट अगस्त 2031 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे।

भारत ने कोस्ट गार्ड में अपना पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट शामिल किया

भारतीय कोस्ट गार्ड ने अपना पहला स्वदेशी रूप से बना एयर कुशन व्हीकल (ACV) H-561 शामिल किया है।

मुख्य बिन्दु:

- कार्यक्रम: पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट को शामिल करना
- होवरक्राफ्ट का नाम: H-561
- संगठन: भारतीय कोस्ट गार्ड
- निर्माता: चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गोवा
- प्रकार: एयर कुशन व्हीकल (ACV) / होवरक्राफ्ट
- पहल: मेक इन इंडिया
- ऑर्डर किए गए ACV: 6

पृष्ठभूमि:

- भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने की कोशिश का हिस्सा
- तटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान
- भारतीय कोस्ट गार्ड तटीय इलाकों में ऑपरेशन के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहा है
- भारत की तटरेखा के साथ समुद्री क्षेत्र की निगरानी में मदद करता है

PM नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तीन स्वदेशी नौसैनिक जहाजों को कमीशन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित तीन नौसैनिक जहाजों को कमीशन किया।

मुख्य बिन्दु:

- कार्यक्रम: तीन नौसैनिक जहाजों का कमीशनिंग
- किसके द्वारा कमीशन किया गया: PM नरेंद्र मोदी
- स्थान: श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता

कमीशन किए गए जहाज:

1. INS दूनागिरी (स्टेलथ फ्रिगेट – निगरानी और युद्ध क्षमता)
 2. INS संशोधक (हाइड्रोग्राफिक सर्वे पोत – समुद्र तल की मैपिंग और नेविगेशन)
 3. INS अग्रय (ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट – पनडुब्बी-रोधी युद्ध)
- डिज़ाइन: भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा
 - निर्माण: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा
 - स्वदेशी सामग्री: 75% से अधिक
 - MSME की भागीदारी: 200 से अधिक इकाइयाँ

पृष्ठभूमि:

- 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने का हिस्सा
- भारतीय नौसेना स्वदेशी युद्धपोत उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है
- GRSE (कोलकाता) एक प्रमुख रक्षा जहाज निर्माण यार्ड है
- भारत समुद्री बुनियादी ढांचे और नौसेना के आधुनिकीकरण का विस्तार कर रहा है

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs): भारत की न्यूक्लियर एनर्जी के विस्तार की कुंजी

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) भारत की न्यूक्लियर एनर्जी रणनीति का एक अहम हिस्सा बनकर उभर रहे हैं। इनका मकसद क्लीन एनर्जी क्षमता को बढ़ाना और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के

तहत देश के लंबे समय के डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना है।

मुख्य बिन्दु:

- टेक्नोलॉजी: स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs)
- क्षमता: प्रति मॉड्यूल 300 MW_e तक
- खासियत: फैक्ट्री में बने, मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर
- रेगुलेटर: एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (AERB) से उम्मीद है कि ये बड़े रिएक्टरों जैसे ही सुरक्षा मानक लागू करेगा
- मिशन: न्यूक्लियर एनर्जी मिशन (केंद्रीय बजट 2025-26)
- लक्ष्य: 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर क्षमता
- आवंटन: SMR विकास के लिए ₹20,000 करोड़

पृष्ठभूमि:

- SMRs छोटे, सुरक्षित और तेज़ी से लगाए जा सकने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर हैं
- इन्हें दूर-दराज़ के इलाकों और फ्लेक्सिबल बिजली उत्पादन के लिए डिज़ाइन किया गया है
- ये भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांज़िशन और एनर्जी सिक्योरिटी में मदद करते हैं
- ये 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के अनुरूप हैं

अन्य मुख्य तथ्य:

- SHANTI एक्ट, 2025 का मकसद न्यूक्लियर सेक्टर को आधुनिक बनाना और रेगुलेटेड प्राइवेट भागीदारी की अनुमति देना है
- SMRs के फायदे: कम लागत, तेज़ी से निर्माण, पैसिव सेफ्टी सिस्टम
- कोयले से चलने वाले पावर प्लांट को बदलने में मदद

भारत का 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम (होमी भाभा):

- PHWR → FBR → थोरियम-आधारित रिएक्टर
- मुख्य संस्थान: DAE, NPCIL, BARC
- रिन्यूएबल्स के साथ-साथ बेसलोड पावर को मज़बूत करने में मदद करता है

DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल (LRLACM) का सफल फ़्लाइट-टेस्ट किया

DRDO ने ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल (LRLACM) का सफल फ़्लाइट-टेस्ट किया है।

मुख्य बिन्दु:

- संगठन: DRDO
- मिसाइल: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल (LRLACM)
- प्रकार: ज़मीन से लॉन्च होने वाली क्रूज़ मिसाइल
- टेस्ट की जगह: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा
- उद्देश्य: लंबी दूरी पर ज़मीन पर मौजूद लक्ष्यों पर सटीक हमला करना
- उपलब्धि: मिशन के सभी लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए
- नोडल लैब: ADE, बेंगलुरु

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- पूरा नाम: लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल (LRLACM)
- किसके द्वारा विकसित: DRDO
- नोडल प्रयोगशाला: एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADE), बेंगलुरु
- ADE एयरोस्पेस सिस्टम और UAV के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है
- लॉन्च साइट: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा
- संभावित यूज़र: भारतीय सशस्त्र बल (नौसेना और वायु सेना)

IN-SPACe ने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड (TAF) के तहत तीन स्पेस स्टार्टअप्स को चुना

IN-SPACe ने स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी के कमर्शियलाइजेशन (व्यावसायीकरण) को बढ़ावा देने और भारत के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को मज़बूत करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड (TAF) स्कीम के तहत तीन भारतीय स्टार्टअप्स को चुना है।

मुख्य बिन्दु:

- संस्था: IN-SPACe
- स्कीम: टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड (TAF)
- चुने गए स्टार्टअप्स: एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज़, सैटशोर एनालिटिक्स इंडिया, TM2SPACE टेक्नोलॉजीज़
- उद्देश्य: स्वदेशी स्पेस टेक्नोलॉजी का कमर्शियलाइजेशन
- फंडिंग: स्टार्टअप्स/MSMEs के लिए 60% तक, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए 40% तक
- अधिकतम सहायता: प्रति प्रोजेक्ट ₹25 करोड़

अन्य मुख्य तथ्य:

- IN-SPACe की स्थापना 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेस के तहत हुई
- हेडक्वार्टर: अहमदाबाद
- प्राइवेट स्पेस कंपनियों के लिए सिंगल-विंडो एजेंसी के तौर पर काम करता है
- TAF फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया
- उद्देश्य: इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करना और स्पेस इन्वेंशन को बढ़ावा देना

नोवार्टिस ने एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए भारत की पहली मंज़ूरशुदा रेडियोलिगेण्ड थेरेपी लॉन्च की

ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस ने एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए भारत की पहली मंज़ूरशुदा रेडियोलिगेण्ड थेरेपी (Pluvicto) लॉन्च की है। यह भारत में प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी और टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्य बिन्दु:

- कंपनी: नोवार्टिस
- थेरेपी: Pluvicto (रेडियोलिगेण्ड थेरेपी)
- प्रकार: प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी / टारगेटेड कैंसर थेरेपी
- बीमारी: PSMA-पॉज़िटिव मेटास्टेटिक कैस्ट्रेशन-रेसिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर (mCRPC)

- टारगेट: प्रोस्टेट-स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन (PSMA)
- रेडियोआइसोटोप: ल्यूटेटियम-177
- महत्व: भारत की पहली मंजूरशुदा रेडियोलिगेण्ड थेरेपी

पृष्ठभूमि:

- mCRPC प्रोस्टेट कैंसर का एक एडवांस्ड स्टेज है जो हार्मोन थेरेपी के प्रति रेसिस्टेंट (असर न करने वाला) होता है
- PSMA एक प्रोटीन है जो प्रोस्टेट कैंसर सेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है
- रेडियोलिगेण्ड थेरेपी सीधे कैंसर सेल्स तक रेडिएशन पहुंचाती है
- पारंपरिक थेरेपी की तुलना में स्वस्थ टिशू को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करती है

अन्य मुख्य तथ्य:

- प्रोस्टेट कैंसर दुनिया भर में पुरुषों में होने वाले सबसे आम कैंसर में से एक है
- ल्यूटेटियम-177 का इस्तेमाल टारगेटेड रेडियोफार्मास्युटिकल थेरेपी में बड़े पैमाने पर किया जाता है
- BARC और DAE के माध्यम से भारत का न्यूक्लियर मेडिसिन इकोसिस्टम मज़बूत है

ISRO और DAE एडवांस्ड लूनर लैंडर टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम कर रहे हैं

ISRO और डिपार्टमेंट ऑफ़ एटॉमिक एनर्जी (DAE) मिलकर एक एडवांस्ड लूनर लैंडर बना रहे हैं। इसमें एक आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम होगा, जो चांद की रात के बेहद ठंडे हालात में भी लैंडर को चालू रखेगा और मिशन की अवधि को 100-200 दिनों तक बढ़ा सकेगा।

मुख्य बिन्दु:

- संस्थाएं: ISRO और डिपार्टमेंट ऑफ़ एटॉमिक एनर्जी (DAE)
- टेक्नोलॉजी: आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम वाला एडवांस्ड लूनर लैंडर
- मकसद: चांद की रात में भी काम करते रहना और मिशन की अवधि बढ़ाना
- मौजूदा क्षमता: ~14 दिन (चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर)
- प्रस्तावित क्षमता: 100-200 दिन
- उद्देश्य: लंबे समय तक चांद की खोज और डेटा इकट्ठा करना

पृष्ठभूमि:

- चांद पर तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है (+121°C से -129°C तक)
- चांद पर दिन और रात, दोनों लगभग 14 पृथ्वी-दिनों के बराबर होते हैं
- सूरज की रोशनी न होने के कारण, सोलर-पावर्ड लैंडर चांद की रात में काम नहीं कर पाते
- चंद्रयान-3 सिर्फ़ एक लूनर डे (चांद के एक दिन) तक ही काम कर पाया

- चांद के गहरे मिशनों के लिए थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम की ज़रूरत है

अन्य मुख्य तथ्य:

- ISRO और DAE ने पहले रेडियोआइसोटोप हीटर यूनिट्स (RHUs) पर काम किया था
- भविष्य का मिशन: LUPEX (ISRO-JAXA) - चांद पर मौजूद पानी की बर्फ़ का अध्ययन करने के लिए
- ISRO चेयरमैन: V. नारायणन

IIT भुवनेश्वर ने पानी में आर्सेनिक का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस "ArsenSafe" विकसित किया

IIT भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने पीने के पानी में आर्सेनिक प्रदूषण का तेज़ी से पता लगाने के लिए 'ArsenSafe' नाम का एक सस्ता और पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। इसका मकसद भूजल प्रदूषण और उससे जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करना है।

मुख्य बिन्दु:

- संस्थान: IIT भुवनेश्वर
- डिवाइस: ArsenSafe
- उद्देश्य: पीने के पानी में आर्सेनिक का पता लगाना
- विशेषता: पोर्टेबल, कम लागत वाला और फ़ील्ड में इस्तेमाल करने योग्य डिवाइस
- तकनीक: रिड्यूस्ड ग्राफीन ऑक्साइड (rGO) पर आधारित सेंसर
- लक्ष्य: आर्सेनिक प्रदूषण का तेज़ और सटीक पता लगाना

पृष्ठभूमि:

- भारत में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण एक बड़ी समस्या है
- लंबे समय तक संपर्क में रहने से 'आर्सेनिकोसिस' जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है
- WHO की स्वीकार्य सीमा: 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर (10 ppb)
- आमतौर पर प्रभावित राज्य: पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर

DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लगातार तीन फ्लाइट टेस्ट किए

DRDO ने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम के लगातार तीन फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक किए। इससे मल्टी-लेयर्ड डिफेंस आर्किटेक्चर के ज़रिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों को रोकने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया।

मुख्य बिन्दु:

- संगठन: DRDO
- उपलब्धि: बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रोग्राम के लगातार तीन फ्लाइट टेस्ट
- उद्देश्य: मल्टी-लेयर्ड डिफेंस सिस्टम के ज़रिए बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की क्षमता का प्रदर्शन करना

- रक्षा मंत्री: राजनाथ सिंह
- क्षमताएं: बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना, एंटी-शिप मिसाइल डिफेंस, मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा
- महत्व: भारत के स्वदेशी मिसाइल शीलड और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है

पृष्ठभूमि:

- भारत का BMD प्रोग्राम 1999 के कारगिल युद्ध के बाद शुरू किया गया था।
- इसे DRDO ने विकसित किया है।
- इसमें एक्सो-एटमोस्फेरिक और एंडो-एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन (मिसाइल को रोकने) की क्षमताएं शामिल हैं।
- भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिनके पास एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी है।

अन्य मुख्य तथ्य:

- DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।
- चेयरमैन: डॉ. समीर वी. कामत।

ज़ोहो ने भारत में डिज़ाइन किए गए सर्वर 'नाथू ला' के साथ हार्डवेयर सेक्टर में कदम रखा

ज़ोहो कॉर्पोरेशन ने 'नाथू ला' लॉन्च करके हार्डवेयर सेक्टर में एंटी की है। यह उनका पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया सर्वर प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर की लागत को कम करना और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु:

- कंपनी: ज़ोहो कॉर्पोरेशन
- प्रोडक्ट: नाथू ला सर्वर
- डिज़ाइन: ज़ोहो इंजीनियरिंग टीम, नागपुर
- टेक्नोलॉजी पार्टनर: इंटेल
- प्रोसेसर: इंटेल ज़ियोन 6

पृष्ठभूमि:

- यह हार्डवेयर डेवलपमेंट में ज़ोहो की पहली बड़ी एंटी है।
- इसे AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइज़ेशन, HPC और एंटरप्राइज़ वर्कलोड के लिए बनाया गया है।
- बिजली की खपत को 12-18% तक कम करता है।
- कुल लागत (TCO) को 20-30% तक कम करता है।
- प्रोजेक्ट 2020 में शुरू हुआ और इसमें पांच साल से ज़्यादा की R&D शामिल थी।
- थर्मल मैनेजमेंट और सर्वर आर्किटेक्चर के लिए कई पेटेंट फाइल किए गए।
- 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों को सपोर्ट करता है।

नाथू ला सर्वर के बारे में:

- ज़ोहो का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया सर्वर प्लेटफॉर्म।

- सिक्किम में नाथू ला दर्रे (पास) के नाम पर इसका नाम रखा गया है।
- इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) भारत के पास है।
- मुख्य रूप से ज़ोहो के ग्लोबल डेटा सेंटरों में इस्तेमाल के लिए बनाया गया है।

ज़ोहो कॉर्पोरेशन के बारे में:

- हेडक्वार्टर: चेन्नई।
- 1996 में एडवेंटेनेट (AdventNet) के तौर पर स्थापना।
- संस्थापक: श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस।
- दुनिया भर में 130 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स को सेवा देता है।

निष्कर्ष:

नाथू ला के लॉन्च के साथ, ज़ोहो ने सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की ओर विस्तार किया है, जिससे भारत के स्वदेशी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम और AI इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमताएं मजबूत हुई हैं।

NASA ने इंसानों की चांद पर वापसी के लिए Artemis III मिशन के कू सदस्यों के नामों की घोषणा की

NASA ने Artemis III मिशन के लिए चार सदस्यों वाले कू की घोषणा की है। इस मिशन का मकसद 1972 में हुए अपोलो 17 मिशन के बाद पहली बार इंसानों को चांद पर वापस भेजना है।

मुख्य बिंदु:

- मिशन: Artemis III
- मकसद: इंसानों को चांद पर वापस भेजना
- लैंडिंग की योजना वाली जगह: चांद का दक्षिणी ध्रुव (South Pole)
- आखिरी बार इंसानों के साथ चांद पर लैंडिंग: अपोलो 17 (1972)
- लंबा लक्ष्य: मंगल ग्रह पर इंसानी मिशन की तैयारी करना

Artemis III कू:

1. रीड वाइज़मैन – कमांडर
2. विक्टर ग्लोवर – पायलट
3. क्रिस्टीना कोच – मिशन स्पेशलिस्ट
4. जेरेमी हैनसेन – मिशन स्पेशलिस्ट

मिशन की मुख्य बिंदु:

- अंतरिक्ष यात्री ओरियन स्पेसक्राफ्ट से यात्रा करेंगे।
- लॉन्च व्हीकल: स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS)।
- चांद पर लैंडिंग के लिए SpaceX के स्टारशिप ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम (HLS) का इस्तेमाल किया जाएगा।
- क्रिस्टीना कोच चांद पर मिशन के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बन सकती हैं।
- विक्टर ग्लोवर चांद पर मिशन के लिए चुने जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन सकते हैं।
- जेरेमी हैनसेन चांद मिशन पर जाने वाले पहले कनाडाई अंतरिक्ष यात्री बनेंगे।

SIPRI रिपोर्ट में भारत के तैनात परमाणु वॉरहेड और बढ़े हुए परमाणु जखीरे पर प्रकाश डाला गया है

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम ईयरबुक में बताया गया है कि 2026 में भारत का अनुमानित परमाणु जखीरा बढ़कर 190 वॉरहेड हो गया है और यह भी संकेत दिया गया है कि भारत ने पहली बार शांति के समय में परमाणु वॉरहेड तैनात किए हो सकते हैं।

मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट: SIPRI ईयरबुक 2026
- भारत का अनुमानित परमाणु जखीरा: 190 वॉरहेड
- पिछला अनुमान: 180 वॉरहेड
- तैनात वॉरहेड की संख्या: 12
- मुख्य फोकस: परमाणु आधुनिकीकरण और समुद्र-आधारित प्रतिरोध (deterrence)

पृष्ठभूमि:

- भारत ने शांति के समय में 12 परमाणु वॉरहेड तैनात किए हो सकते हैं।
- पारंपरिक रूप से, भारत वॉरहेड और डिलीवरी सिस्टम को अलग-अलग रखता था।
- कुछ तैनात वॉरहेड समुद्र-आधारित प्रतिरोध क्षमताओं से जुड़े हो सकते हैं।
- भारत लंबी दूरी की मिसाइलों, कैनिस्ट्राइज्ड सिस्टम और SSBN-आधारित प्रतिरोध को आधुनिक बनाना जारी रखे हुए है।
- SIPRI ने परमाणु हथियारों पर बढ़ती वैश्विक निर्भरता और परमाणु प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के बारे में चेतावनी दी है।

SIPRI के बारे में:

- स्थापना: 1966
- मुख्यालय: स्टॉकहोम, स्वीडन
- हथियारों, सैन्य खर्च, हथियारों के हस्तांतरण और निरस्त्रीकरण पर शोध करने वाला स्वतंत्र संस्थान।

भारत ने स्वदेशी रुद्रम-II (RudraM-II) एयर-टू-सरफेस मिसाइल का सफल परीक्षण किया

DRDO और भारतीय वायु सेना ने ओडिशा के चांदीपुर में एक हवाई प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रुद्रम-II एयर-टू-सरफेस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

मुख्य बिंदु:

- मिसाइल: रुद्रम-II
- प्रकार: एयर-टू-सरफेस प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल (सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल)
- परीक्षण स्थल: इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज
- किसके द्वारा विकसित: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO)
- उपयोगकर्ता: भारतीय वायु सेना (IAF)

पृष्ठभूमि:

SEAD/DEAD मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया।

इन पर निशाना साध सकती है:

- दुश्मन के रडार स्टेशन
- सरफेस-टू-एयर मिसाइल (SAM) सिस्टम
- कमांड और कंट्रोल सेंटर

जमीन पर मौजूद अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य

- स्ट्राइक रेंज: लगभग 300 किमी।
- गति: लगभग मैक 5.5।
- पूरी सटीकता के साथ पहले से तय लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

- नोडल प्रयोगशाला: रिसर्च सेंटर इमारत (RCI)।
- अन्य DRDO प्रयोगशालाएं: DRDL, HEMRL, ARDE, ITR।
- इंडस्ट्री पार्टनर: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)।

Red Balloon Aerospace ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

भारतीय स्टार्टअप Red Balloon Aerospace ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून (SPB) प्लेटफॉर्म सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

मुख्य बिंदु:

- संगठन: Red Balloon Aerospace
- प्लेटफॉर्म: सुपर प्रेशर बैलून (SPB)
- लॉन्च स्थल: विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
- ऊँचाई: 20-40 km (नियर स्पेस)
- महत्व: भारत का पहला स्वदेशी SPB प्लेटफॉर्म

पृष्ठभूमि:

- नियर स्पेस पृथ्वी से 20 km और 100 km के बीच स्थित है।
- यह कमर्शियल विमानों के ऊपर और सैटेलाइट के नीचे स्थित होता है।
- SPB का उपयोग दुनिया भर में संचार, निगरानी, वायुमंडलीय अध्ययन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है।

उपयोग:

- दूरसंचार कवरेज
- पृथ्वी अवलोकन
- आपदा प्रबंधन
- पर्यावरण निगरानी
- रक्षा निगरानी
- ग्रामीण कनेक्टिविटी

सुपर प्रेशर बैलून (SPB) के बारे में:

- हवा से हल्के विशेष प्लेटफॉर्म।
- आसपास के वातावरण की तुलना में आंतरिक दबाव अधिक बनाए रखते हैं।

विशेषताएँ:

- स्थिर ऊँचाई
- लंबे समय तक संचालन
- वैज्ञानिक और संचार पेलोड सहायता
- लगातार वायुमंडलीय अवलोकन

महत्व:

- सैटेलाइट का एक किफायती विकल्प।
- मिशन के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और वापस पाया जा सकता है।

चीन ने Shenzhou-23 मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया

चीन ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसानों को उतारने की अपनी योजना के तहत, तीन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर Shenzhou-23 को सफलतापूर्वक Tiangong अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया।

मुख्य बिन्दु:

- मिशन: Shenzhou-23
- देश: चीन
- लॉन्च वाहन: Long March-2F रॉकेट
- लॉन्च स्थल: Jiuquan सैटेलाइट लॉन्च सेंटर
- गंतव्य: Tiangong अंतरिक्ष स्टेशन
- चालक दल के सदस्य: 3 अंतरिक्ष यात्री
- एजेंसी: China Manned Space Agency (CMSA)

पृष्ठभूमि:

- Shenzhou चीन का प्रमुख मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है।
- यह मिशन 2030 तक चंद्रमा पर मानवयुक्त लैंडिंग के चीन के लक्ष्य का समर्थन करता है।
- यह अंतरिक्ष में अपनी दीर्घकालिक उपस्थिति का विस्तार करने और उन्नत मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को विकसित करने की चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

जहाज पर सवार अंतरिक्ष यात्री

1. Zhu Yangzhu – मिशन कमांडर
2. Zhang Zhiyuan – पायलट
3. Lai Ka-ying – पेलोड विशेषज्ञ

मिशन का महत्व:

- चीन का पहला नियोजित एक साल लंबा मानव अंतरिक्ष मिशन।
- 2030 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।

चालक दल ये कार्य करेगा:

- वैज्ञानिक प्रयोग
- अंतरिक्ष चिकित्सा अध्ययन
- दीर्घकालिक मिशनों के लिए प्रौद्योगिकी परीक्षण

Tiangong अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में:

- "Tiangong" का अर्थ है "स्वर्गीय महल"।

- Low Earth Orbit (LEO) में चीन का स्थायी रूप से संचालित मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन।
- मुख्य मॉड्यूल: Tianhe।
- इसका निर्माण 2021 में शुरू हुआ।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- चीन की योजना 2035 तक रूस के साथ एक स्थायी चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की है।
- चीन 2024 में चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से नमूने वापस लाने वाला पहला देश बन गया।
- "Shenzhou" का अर्थ है "दिव्य पोत"।

निष्कर्ष:

Shenzhou-23 चीन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में एक प्रमुख मील का पत्थर है और चंद्र अन्वेषण तथा दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए उसकी महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करता है।

JUNE 12 ANTI-CHILD LABOR DAY
• Every Child Deserves A Childhood •

STOP CHILD LABOUR
LET THEM DREAM

CHILDHOOD NOT LABOUR

IMPORTANCE
In 2002, the International Labour Organization (ILO) launched this day to bring attention and join efforts to fight against child labour.
And also marks the 20 years since the adoption of the ILO's Worst Forms of child Labour Convention, 1999.
This day mainly focus on the children development and it protects the right of education and dignified life for the children.

INCEPTION
2002

EDITION
25th

MOTTO
To raise awareness and activism to prevent child labour.

ORGANISATION INVOLVED
ILO
UNICEF

NOTE: INDIA
Earlier: Child below 18 years
Now: Child below 14 years

SAY NO TO CHILD LABOUR

YES TO EDUCATION YES TO FUTURE

END CHILD LABOUR. BUILD A BETTER FUTURE.

PROTECT CHILDREN • EDUCATE CHILDREN • EMPOWER CHILDREN • RESPECT THEIR RIGHTS

TOGETHER, WE CAN END CHILD LABOUR AND CREATE A WORLD WHERE EVERY CHILD CAN LEARN, GROW AND DREAM.

निधन

तिमोर-लेस्ते के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसिस्को "लू ओलो" गुटेरेस का निधन



तिमोर-लेस्ते के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसिस्को "लू ओलो" गुटेरेस का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 2017 से 2022 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में काम किया और इंडोनेशियाई कब्जे के खिलाफ तिमोर-लेस्ते के आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई।

मुख्य बिन्दु:

- चर्चा में रहे व्यक्ति: फ्रांसिस्को "लू ओलो" गुटेरेस
- देश: तिमोर-लेस्ते (पूर्वी तिमोर)
- राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल: 2017-2022
- राजनीतिक पार्टी: FRETILIN (आज़ाद पूर्वी तिमोर के लिए क्रांतिकारी मोर्चा)
- महत्व: तिमोर-लेस्ते के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख नेता
- तिमोर-लेस्ते की आज़ादी: 20 मई 2002
- राजधानी: दिली
- मौजूदा राष्ट्रपति: जोस रामोस-होर्टा

पृष्ठभूमि:

- तिमोर-लेस्ते 1975 से 1999 तक इंडोनेशिया के कब्जे में था।
- 1999 में UN समर्थित जनमत संग्रह से देश की आज़ादी का रास्ता खुला।
- यह आधिकारिक तौर पर 20 मई 2002 को एक आज़ाद देश बना।
- तिमोर-लेस्ते दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित है और दुनिया के सबसे नए संप्रभु देशों में से एक है।

अन्य मुख्य तथ्य:

- आधिकारिक नाम: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ तिमोर-लेस्ते।
- तिमोर द्वीप को इंडोनेशिया के साथ साझा करता है।
- मुद्रा: यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर (USD)।
- आधिकारिक भाषाएँ: टेदुम और पुर्तगाली।
- 2002 से संयुक्त राष्ट्र (UN) का सदस्य।

मशहूर मांड लोक गायिका गवरी देवी का 98 साल की उम्र में निधन



राजस्थान की मशहूर मांड लोक गायिका गवरी देवी का पाली ज़िले में 98 साल की उम्र में निधन हो गया। वह राजस्थान की पारंपरिक मांड गायन शैली की सबसे प्रमुख गायिकाओं में से एक थीं और उन्होंने लोक संगीत की विरासत को बचाने में अहम भूमिका निभाई।

मुख्य बिन्दु:

- व्यक्तित्व: गवरी देवी
- क्षेत्र: मांड लोक गायन
- राज्य: राजस्थान
- ज़िला: पाली
- निधन के समय उम्र: 98 साल
- योगदान: भारत और विदेशों में मांड लोक संगीत को बढ़ावा देना
- मशहूर गाना: "केसरिया बालम"

पृष्ठभूमि:

- लोक संगीत के लिए लगभग आठ दशक समर्पित किए
- मांड गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया
- दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी रहीं
- भक्ति, लोक और सूफी-प्रेरित संगीत के लिए जानी जाती थीं
- राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को बचाने में अहम भूमिका निभाई

अन्य खास तथ्य:

- मांड राजस्थान की एक पारंपरिक लोक संगीत शैली है
- उत्पत्ति: जैसलमेर का मांड क्षेत्र
- शाही दरबार की संगीत परंपराओं के लिए जानी जाती है
- अन्य मशहूर गाने: मोर बोले रे मालजी, बागा चलो केसरिया
- राजस्थान सरकार द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित

थाईलैंड की राजकुमारी बन्नकितियाभा का 47 साल की उम्र में निधन



थाईलैंड की राजकुमारी बज्रकितियाभा महिडोल, जो एक जानी-मानी कानूनी विशेषज्ञ और राजनयिक थीं, का 47 साल की उम्र में निधन हो गया है।

मुख्य बिंदु:

- व्यक्तित्व: बज्रकितियाभा महिडोल
- देश: थाईलैंड
- उम्र: 47 साल
- क्षेत्र: कानून, कूटनीति और मानवाधिकार
- मुख्य फोकस: महिला कैदियों का कल्याण और कानूनी सुधार

पृष्ठभूमि:

- थाईलैंड के अटॉर्नी जनरल कार्यालय में अभियोजक (prosecutor) के तौर पर काम किया
- कानून के शासन और न्याय सुधारों को मजबूत करने में सक्रिय रूप से शामिल रहीं
- महिला कैदियों के पुनर्वास के लिए "कमलंगजाई (इंस्पायर)" प्रोजेक्ट शुरू किया
- संयुक्त राष्ट्र की पहलों के माध्यम से वैश्विक न्याय मानकों में योगदान दिया
- ऑस्ट्रिया में थाईलैंड की राजदूत और वियना में संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि के तौर पर काम किया

थाईलैंड के बारे में:

- राजधानी: बैंकॉक
- सरकार: संवैधानिक राजतंत्र
- वर्तमान शासक: महा वजिरालोंगकोर्न

भारतीय शूटिंग दिग्गज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन



खबरों के अनुसार, भारतीय शूटिंग दिग्गज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है।

मुख्य बिंदु:

- व्यक्तित्व: जसपाल राणा

- क्षेत्र: शूटिंग (पिस्टल इवेंट्स)
- भूमिका: एथलीट से नेशनल कोच बने
- प्रमुख ट्रेनी (शिष्य): मनु भाकर
- पुरस्कार: अर्जुन पुरस्कार, पद्म श्री, द्रोणाचार्य पुरस्कार

पृष्ठभूमि:

- जसपाल राणा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के सबसे सफल शूटर्स में से एक थे
- एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते
- वैश्विक स्तर पर पिस्टल शूटिंग में भारत की सफलता में अहम भूमिका निभाई
- रिटायरमेंट के बाद कोचिंग में आए और टॉप शूटर्स को ट्रेनिंग दी
- मनु भाकर के अंतरराष्ट्रीय करियर और ओलंपिक सफलता के दौरान उनका मार्गदर्शन किया
- 25 मीटर पिस्टल इवेंट्स में अपनी बेहतरीन तकनीकी जानकारी के लिए जाने जाते थे

प्रमुख उपलब्धियां (करियर की खास बातें):

- 15 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल (9 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज)
- 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की (2006 एशियाई खेल)
- इतिहास में भारत के सबसे सफल पिस्टल शूटर्स में से एक

पुरस्कार और सम्मान:

- अर्जुन पुरस्कार (1994)
- पद्म श्री (1997)
- कोचिंग में बेहतरीन काम के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार (2020)

एक्सॉन के पूर्व प्रमुख ली रेमंड का 87 साल की उम्र में निधन



ली रेमंड एक जाने-माने अमेरिकी बिज़नेस एग्जीक्यूटिव थे, जिन्होंने एक्सॉन-मोबिल (ExxonMobil) के CEO के तौर पर काम किया और आधुनिक ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री को आकार देने में अहम भूमिका निभाई।

उन्हें मुख्य रूप से 1999 में एक्सॉन-मोबिल मर्जर (विलय) का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, जिससे उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बनी थी।

मुख्य बिंदु:

- पूर्व CEO: ली रेमंड
- कंपनी: एक्सॉन-मोबिल
- पहचान: एक्सॉन-मोबिल मर्जर (1999)
- इंडस्ट्री: ग्लोबल ऑयल और एनर्जी सेक्टर

- निधन के समय उम्र: 87 साल (डलास, USA)

पृष्ठभूमि:

- 1963 में केमिकल इंजीनियर के तौर पर एक्सॉन से जुड़े
- कॉर्पोरेट पदानुक्रम में आगे बढ़ते हुए CEO बने
- एक्सॉन-मोबिल मर्जर का नेतृत्व किया, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनियों में से एक बनी
- एक्सॉन वाल्डेज़ ऑयल स्पिल (तेल रिसाव) की घटना के बाद की कार्रवाई की देखरेख की
- मुख्य ऑयल और गैस ऑपरेशन्स को मजबूत करने पर ध्यान दिया

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले मलयालम एक्टर सलीम कुमार का 56 साल की उम्र में निधन



नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले मलयालम एक्टर और डायरेक्टर सलीम कुमार का केरल के कोच्चि में 56 साल की उम्र में निधन हो गया।

मुख्य बिंदु:

- चर्चा में रहे व्यक्ति: सलीम कुमार
- खबर की कैटेगरी: निधन (Obituary)
- पेशा: एक्टर और डायरेक्टर
- राज्य: केरल
- प्रमुख अवॉर्ड: बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड

पृष्ठभूमि:

- अपने करियर की शुरुआत मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर की।
- मलयालम सिनेमा के सबसे मशहूर एक्टर्स में से एक बने।
- कॉमिक और गंभीर, दोनों तरह के किरदारों में अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते थे।
- फिल्म 'अदमिंते मकान अबू' (Adaminte Makan Abu) के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता।

नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के बारे में:

- स्थापना: 1954।
- किसके द्वारा दिए जाते हैं: डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स।
- मंत्रालय: सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
- भारत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म अवॉर्ड्स में से एक।

CBFC के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन



बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर और CBFC के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी का लिवर से जुड़ी बीमारियों के कारण 76 साल की उम्र में निधन हो गया।

मुख्य बिंदु:

- व्यक्ति: पहलाज निहलानी
- पेशा: फिल्म प्रोड्यूसर
- पूर्व पद: CBFC चेयरमैन
- उम्र: 76 साल

पृष्ठभूमि:

- बॉलीवुड के अनुभवी प्रोड्यूसर, जिनका करियर चार दशकों से ज्यादा लंबा रहा।
- गोविंदा और चंकी पांडे को लॉन्च करने में अहम भूमिका निभाई।
- 'हथकड़ी' (1982) फिल्म से फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखा।
- 'इल्जाम', 'आँखें' और 'शोला और शबनम' जैसी मशहूर फिल्मों प्रोड्यूस कीं।
- 2015 से 2017 तक CBFC चेयरमैन के तौर पर काम किया।

पहलाज निहलानी के बारे में:

- पेशा: फिल्म प्रोड्यूसर
- CBFC कार्यकाल: 2015-2017
- पहली फिल्म: हथकड़ी (1982)
- आखिरी फिल्म: अनाड़ी इज़ बैक (2023)

CBFC के बारे में:

- पूरा नाम: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन
- मंत्रालय: सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- काम: भारत में पब्लिक स्क्रीनिंग के लिए फिल्मों को सर्टिफाई करना
- हेडक्वार्टर: मुंबई
- मौजूदा चेयरमैन: शशि शेखर वेम्पति

डॉ. सुभाष सी. कश्यप का निधन



संविधान के जाने-माने विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी. कश्यप का 97 साल की उम्र में नई दिल्ली में निधन हो गया।

मुख्य बिन्दु:

- लोकसभा के पूर्व महासचिव (1984-1990)
- संविधान विशेषज्ञ और विद्वान
- सम्मान: पद्म भूषण (2003)

पृष्ठभूमि:

- संविधान और संसद पर 100 से ज़्यादा किताबें लिखीं।
- संसदीय सुधारों और संवैधानिक साक्षरता में अहम योगदान दिया।
- लोकसभा अध्यक्ष के मुख्य प्रशासनिक और प्रक्रिया संबंधी सलाहकार के तौर पर काम किया।

अन्य अहम जानकारी:

- लोकसभा महासचिव, लोकसभा सचिवालय का सबसे बड़ा स्थायी अधिकारी होता है।

लोकसभा:

- संसद का निचला सदन
- मौजूदा सदस्य संख्या: 543
- प्रमुख संविधान विशेषज्ञों में बी.आर. अंबेडकर और नानी पालकीवाला शामिल हैं।

मशहूर प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का 89 साल की उम्र में निधन



दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का मुंबई में 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं के गानों में उनके योगदान के लिए जाना जाता था।

मुख्य बिन्दु:

- नाम: सुमन कल्याणपुर
- जन्म: 28 जनवरी 1937, ढाका (अब बांग्लादेश)
- निधन: मुंबई, 2026
- पहचान: हिंदी और कई भाषाओं में प्लेबैक सिंगिंग
- पद्म भूषण: 2023

पृष्ठभूमि:

- हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, पंजाबी और ओडिया भाषाओं में गाने गाए।
- मशहूर गानों में 'आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे', 'ना तुम हमें जानो' और 'बहना ने भाई की कलाई पे' शामिल हैं।

पुरस्कार और सम्मान:

- पद्म भूषण (2023)
- लता मंगेशकर पुरस्कार
- मिर्ची म्यूजिक लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (2022)

CCI के पूर्व चेयरमैन धनेंद्र कुमार का निधन



पूर्व IAS अधिकारी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के संस्थापक चेयरमैन, धनेंद्र कुमार का नई दिल्ली के हौज खास स्थित उनके आवास पर आग लगने के बाद निधन हो गया।

मुख्य बिन्दु:

- पूर्व चेयरमैन: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
- CCI कार्यकाल: 2009-2011
- IAS बैच: 1968 (हरियाणा कैडर)
- मृत्यु का कारण: घर में आग लगने के बाद धुएं के संपर्क में आना
- स्थान: नई दिल्ली

पृष्ठभूमि:

- धनेंद्र कुमार एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पहले चेयरमैन थे।
- उन्होंने विश्व बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

- 2009 से 2011 तक CCI के पहले चेयरमैन के रूप में कार्य किया।
- भारत के प्रतिस्पर्धा नियामक को चालू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बारे में:

- स्थापना: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत
- कार्यशील: 2009 से
- प्रशासनिक मंत्रालय: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
- मुख्यालय: नई दिल्ली

मशहूर उर्दू शायर डॉ. बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में निधन

मशहूर उर्दू शायर और पद्म श्री से सम्मानित डॉ. बशीर बद्र का मध्य प्रदेश के भोपाल में 91 साल की उम्र में निधन हो गया।

मुख्य बिन्दु:

- व्यक्तित्व: डॉ. बशीर बद्र
- क्षेत्र: उर्दू शायरी और राज़ल
- उम्र: 91 साल

- जगह: भोपाल, मध्य प्रदेश
- पुरस्कार: पद्म श्री (1999)



पृष्ठभूमि:

- उर्दू शायरी को आसान, आम लोगों से जुड़ा हुआ और सुलभ बनाने के लिए मशहूर।
- उनकी गज़लों में गहरी भावनाएं और रोज़मर्रा की भाषा का मेल होता था।
- साहित्य, फ़िल्मों, राजनीति और आम बातचीत में उनकी शायरी के शेर अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं।

मुख्य विशेषताएं:

- आधुनिक उर्दू गज़ल के उस्ताद।
- लंबे समय से बीमार रहने और डिमेंशिया (भूलने की बीमारी) के कारण निधन हुआ।
- आज के दौर के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले उर्दू शायरों में से एक।

साहित्यिक योगदान:

शायरी के संग्रह:

- आस
- आमद
- आहट
- इकाई
- इमेज
- कुल्लियात-ए-बशीर बद्र

साहित्यिक आलोचना:

- आज़ादी के बाद उर्दू गज़ल का तनक़ीदी मुताला
- बीसवीं सदी में गज़ल

शैक्षणिक करियर:

- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर।
- लगभग 17 साल तक मेरठ कॉलेज में उर्दू विभाग के प्रमुख रहे।

पुरस्कार और सम्मान:

- पद्म श्री – साहित्य और शिक्षा

- 'आस' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार
- उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और बिहार उर्दू अकादमी द्वारा सम्मानित।
- मीर अकादमी पुरस्कार से सम्मानित।

अन्य मुख्य तथ्य:

- आम पाठकों के बीच उर्दू गज़लों को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं।
- उनकी रचनाएं आज के भारतीय साहित्य में आज भी बहुत असरदार हैं।

पांच बार के ओलंपियन शूटर राजा रणधीर सिंह का निधन



दिग्गज शूटर और खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह का नई दिल्ली में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह पांच बार के ओलंपियन थे और भारतीय तथा एशियाई खेल प्रशासन में एक प्रमुख हस्ती थे।

मुख्य बिन्दु:

- व्यक्तित्व: राजा रणधीर सिंह
- क्षेत्र: शूटिंग और खेल प्रशासन
- उपलब्धि: एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय शूटर
- निधन: नई दिल्ली
- आयु: 79 वर्ष

पृष्ठभूमि:

- पांच ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- 1978 के एशियाई खेलों में शूटिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता।
- 1964 के टोक्यो ओलंपिक में एक रिज़र्व शूटर के रूप में सेवा दी।

पुरस्कार और सम्मान:

- अर्जुन पुरस्कार
- महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार
- OCA मेरिट पुरस्कार

विविध घटनाएँ

जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया; राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर किया

जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया।

मुख्य बिन्दु:

➤ व्यक्ति: जॉर्ज कुरियन

छोड़े गए पद:

- राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामले
- राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी
- मंजूरी देने वाले: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
- सलाह देने वाले: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- कारण: राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होना; दोबारा नॉमिनेट न होना
- पिछला सदन: राज्यसभा (मध्य प्रदेश)
- मंत्री के तौर पर कार्यकाल: जून 2024 से

पृष्ठभूमि:

- मंत्रियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने का काम संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत होता है
- मंत्रियों का संसद सदस्य होना या 6 महीने के भीतर चुना जाना ज़रूरी है
- सदस्यता बनाए रखने में नाकाम रहने पर संवैधानिक रूप से पद छोड़ना पड़ता है
- राज्यसभा सीटों के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है

कीर स्टारमर ने UK के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा की

UK के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता, दोनों पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की है। नए नेता के चुने जाने तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।

मुख्य बिन्दु:

- देश: यूनाइटेड किंगडम
- प्रधानमंत्री: कीर स्टारमर
- पार्टी: लेबर पार्टी
- इस्तीफे की तारीख: 22 जून 2026
- नेतृत्व चुनने की प्रक्रिया शुरू: 9 जुलाई 2026
- मौजूदा स्थिति: उत्तराधिकारी चुने जाने तक PM बने रहेंगे
- संभावित उत्तराधिकारी: एंडी बर्नहम

मुख्य कारण:

- लेबर पार्टी के भीतर अंदरूनी दबाव
- सांसदों के बीच घटना समर्थन

➤ यह आकलन कि अगले आम चुनाव से पहले नेतृत्व में बदलाव ज़रूरी है

SpaceX IPO के बाद एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बने

खबरों के अनुसार, SpaceX के रिकॉर्ड-तोड़ने वाले \$75 बिलियन के IPO के बाद एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं।

मुख्य बिन्दु:

- व्यक्ति: एलन मस्क
- कंपनी: SpaceX
- उपलब्धि: दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर (रिपोर्ट के अनुसार)
- IPO का साइज़: \$75 बिलियन
- SpaceX की वैल्यूएशन: ~\$1.77 ट्रिलियन (IPO स्टेज)
- मार्केट वैल्यू: लिस्टिंग के बाद \$2 ट्रिलियन से ज़्यादा हुई
- महत्व: इतिहास का सबसे बड़ा IPO, ग्लोबल स्पेस इकॉनमी को बढ़ावा

अन्य मुख्य तथ्य:

- SpaceX = स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प.
- हेडक्वार्टर: स्टारबेस, टेक्सास, USA
- CEO: एलन मस्क
- मुख्य सिस्टम: स्टारलिनक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क
- प्रमुख कंपटीटर: ब्लू ओरिजिन, रॉकेट लैब, वर्जिन गैलेक्टिक
- IPO का मतलब है किसी प्राइवेट कंपनी का पहला पब्लिक शेयर ऑफरिंग

ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में श्रीलंका 67वें स्थान पर, दक्षिण एशिया में दूसरा स्थान

ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) 2026 में श्रीलंका को 163 देशों में से 67वां स्थान मिला है, जो शांति के मामले में काफी सुधार दिखाता है।

अब यह भूतान के बाद दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण देश है।

मुख्य बिन्दु:

- रिपोर्ट: ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026
- प्रकाशक: इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस
- श्रीलंका की रैंक: 67वीं (163 देशों में से)
- सुधार: +14 स्थान
- दक्षिण एशिया में रैंक: दूसरी (भूतान के बाद)

पृष्ठभूमि:

- श्रीलंका की रैंकिंग में सुधार मुख्य रूप से सैन्यीकरण (militarisation) के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के कारण हुआ है

- यह इंडेक्स 163 देशों में शांति को मापता है, जिसमें दुनिया की 99.7% आबादी शामिल है
- यह आंतरिक संघर्ष, सुरक्षा और सैन्य खर्च के रुझानों का मूल्यांकन करता है
- कुल मिलाकर वैश्विक शांति में गिरावट आई है, और कई देशों की स्थिति खराब हुई है
- 2008 के बाद से बाहरी संघर्षों में शामिल देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है

ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) के बारे में:

यह सालाना राष्ट्रीय और वैश्विक शांति को मापता है

इसमें तीन मुख्य क्षेत्र शामिल हैं:

- सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा
- चल रहे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष
- सैन्यीकरण
- शीर्ष 5 सबसे शांतिपूर्ण देश (2026): आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर
- भूतान दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है (वैश्विक स्तर पर 16वां)

दक्षिण एशिया रैंकिंग:

- भूतान – 16वां (क्षेत्र में पहला)
- श्रीलंका – 67वां
- नेपाल – 111वां
- बांग्लादेश – 117वां
- भारत – 127वां
- पाकिस्तान – 152वां
- अफगानिस्तान – 157वां

राजीव बजाज बजाज फिनसर्व के बोर्ड से हटेंगे

राजीव बजाज ने बजाज फिनसर्व के नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर दोबारा चुने जाने की कोशिश न करने का फैसला किया है और 31 जुलाई 2026 को कंपनी की AGM के बाद वे पद छोड़ देंगे।

मुख्य बिंदु:

- चर्चा में व्यक्ति: राजीव बजाज
- कंपनी: बजाज फिनसर्व
- पद: नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
- AGM की तारीख: 31 जुलाई 2026
- कारण: बजाज ऑटो में बढ़ती जिम्मेदारियां

पृष्ठभूमि:

- राजीव बजाज रोटेशन के तहत रिटायर होंगे और बजाज फिनसर्व के डायरेक्टर नहीं रहेंगे।
- उन्होंने बाहरी जिम्मेदारियों को कम करने का कारण बजाज ऑटो में बढ़ती जिम्मेदारियों को बताया।
- वे बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे।

भविता मंडावा 'फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026' लिस्ट में शामिल

भारतीय मॉडल भविता मंडावा को ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ने के लिए 'फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026' लिस्ट में 'आर्ट्स' कैटेगरी में शामिल किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- पर्सनैलिटी: भविता मंडावा
- पहचान: फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026
- कैटेगरी: आर्ट्स
- होमटाउन: हैदराबाद
- बड़ी उपलब्धि: न्यूयॉर्क में शनेल (Chanel) के 'मेटियर्स डी'आर्ट' (Métiers d'Art) रनवे शो की शुरुआत करने वाली पहली भारतीय मॉडल (दिसंबर 2025)

पृष्ठभूमि:

- न्यूयॉर्क सबसे में खोजे जाने के बाद भविता को इंटरनेशनल पहचान मिली।
- दिसंबर 2025 में, वह शनेल के 'मेटियर्स डी'आर्ट' रनवे शो की शुरुआत करने वाली पहली भारतीय मॉडल बनीं।
- मार्च 2026 में, उन्हें शनेल का पहला भारतीय 'हाउस एंबेसडर' नियुक्त किया गया।
- ग्लोबल फैशन में बढ़ते प्रभाव के कारण उन्हें 'फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया' के लिए चुना गया।

CDS जनरल अनिल चौहान चार दशकों से ज्यादा की सैन्य सेवा के बाद रिटायर हुए

जनरल अनिल चौहान भारतीय सशस्त्र बलों में 45 साल से ज्यादा की सेवा के बाद रिटायर हो गए। उन्होंने दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के तौर पर काम किया और रक्षा सुधारों और संयुक्त सैन्य एकीकरण में अहम भूमिका निभाई।

मुख्य बिंदु:

- अधिकारी: जनरल अनिल चौहान
- पद: भारत के दूसरे CDS
- कार्यकाल: 30 सितंबर 2022 – 30 मई 2026
- सेवा: 45+ साल
- रेजिमेंट: 11 गोरखा राइफल्स

पृष्ठभूमि:

- जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद 2022 में उन्हें CDS नियुक्त किया गया था।
- भारतीय सेना में अहम कमांड और रणनीतिक भूमिकाओं में काम किया।

CDS के बारे में:

- कारगिल समीक्षा सुधारों के बाद 2019 में बनाया गया।
- तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों पर सरकार के शीर्ष सैन्य सलाहकार।
- सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के प्रमुख।

पहले CDS: बिपिन रावत

माह के महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास

खोज और बचाव अभ्यास (SAREX)

दक्षिण कोरिया और जापान ने नौ साल के अंतराल के बाद एक संयुक्त समुद्री खोज और बचाव अभ्यास किया। यह अभ्यास जेजू द्वीप के पास आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच ऑपरेशनल सहयोग, समुद्री सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया समन्वय को मजबूत करना था।

मुख्य बिंदु:

- देश: दक्षिण कोरिया और जापान
- कार्यक्रम: संयुक्त समुद्री खोज और बचाव अभ्यास
- स्थान: जेजू द्वीप के पास, दक्षिण कोरिया
- भाग लेने वाली एजेंसियां: कोरिया कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड
- पिछले अभ्यास के बाद का अंतर: 9 साल

पृष्ठभूमि:

- यह अभ्यास समुद्री खोज और बचाव कार्यों, आपातकालीन प्रतिक्रिया समन्वय, संचार और सूचना साझा करने पर केंद्रित था।
- इसे समुद्र में ऑपरेशनल सहयोग और आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए आयोजित किया गया था।
- यह अभ्यास दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों के बीच हुआ है।
- यह अभ्यास इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग के बढ़ते महत्व को उजागर करता है।

समुद्री खोज और बचाव (SAR) के बारे में:

- इसका मतलब समुद्र में मूसीबत में फंसे लोगों का पता लगाने और उनकी मदद करने के लिए समन्वित प्रयास है।
- इसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा ढांचे के तहत आयोजित किया जाता है।
- यह आपदा प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता क्षमताओं को बढ़ाता है।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के बारे में:

- रणनीतिक क्षेत्र जो हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक फैला है।
- वैश्विक व्यापार मार्गों, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और भू-राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण।

निष्कर्ष:

दक्षिण कोरिया और जापान ने नौ साल बाद अपना संयुक्त समुद्री खोज और बचाव अभ्यास फिर से शुरू किया, जो बेहतर होते

द्विपक्षीय संबंधों और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।

'खान क्वेस्ट 2026' (KHAAN QUEST 2026)

भारतीय सेना की एक टुकड़ी मंगोलिया में होने वाले बहु-राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'खान क्वेस्ट 2026' में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र (UN) के शांति-समर्थन अभियानों और इसमें शामिल देशों के बीच आपसी तालमेल (interoperability) को बेहतर बनाने पर केंद्रित होगा।

मुख्य बिन्दु:

- अभ्यास: खान क्वेस्ट 2026
- मेज़बान देश: मंगोलिया
- स्थान: फाइव हिल्स ट्रेनिंग एरिया, उलानबटार
- अवधि: 20 जून – 3 जुलाई 2026
- भारतीय टुकड़ी: 40 जवान
- भारतीय यूनिट: जाट रेजिमेंट और अन्य आर्म्स व सर्विसेज़
- फोकस: UN शांति-समर्थन अभियान (चैप्टर VII)
- उद्देश्य: आपसी तालमेल और बहु-राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना

पृष्ठभूमि:

- मंगोलिया द्वारा आयोजित वार्षिक बहु-राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास
- शुरुआत में मंगोलिया और USA के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के तौर पर शुरू हुआ
- बाद में इसे बहु-राष्ट्रीय शांति-रक्षा अभ्यास के रूप में बढ़ाया गया
- UN-अधिकृत शांति-रक्षा स्थितियों पर फोकस
- रक्षा सहयोग के तहत भारत नियमित रूप से इसमें भाग लेता है

अन्य मुख्य तथ्य:

- मुख्य प्रशिक्षण क्षेत्र: C-IED ड्रिल, काफिले की सुरक्षा, गश्त, घेराबंदी और तलाशी (cordon & search), HADR
- UN शांति-रक्षा: भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में शामिल है
- UN चार्टर चैप्टर VII: शांति और सुरक्षा के लिए लागू करने वाले उपायों (enforcement measures) की अनुमति देता है
- भारत-मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी: 2015 में स्थापित
- मंगोलिया को "अनंत नीले आकाश की भूमि" (Land of the Eternal Blue Sky) कहा जाता है
- राजधानी: उलानबटार | मुद्रा: मंगोलियाई तोगरोग (Mongolian Tögrög)

माह के महत्वपूर्ण दिन

दिवस	मनाया जाता है	थीम/उद्देश्य/महत्व
जुलाई 1	डॉक्टर दिवस	प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती के अवसर पर।
जुलाई 2	विश्व यूएफओ दिवस	यह उस तारीख की याद दिलाता है जिस दिन प्रसिद्ध रोसवेल घटना जनता के सामने उजागर हुई थी।
जुलाई 6	विश्व जूनोसिस दिवस	मनुष्यों और जानवरों के बीच फैलने वाली एक जूनोटिक बीमारी के खिलाफ पहले टीकाकरण की खोज का जश्न मनाने हेतु।
जुलाई 11	विश्व जनसंख्या दिवस	जनसंख्या संबंधी मुद्दों की तात्कालिकता और महत्व पर ध्यान केंद्रित करना।
जुलाई 12	राष्ट्रीय सादगी दिवस	1817 में हेनरी डेविड थोरो की जयंती मनाने हेतु।
जुलाई 17	अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए वैश्विक दिवस	1998 में रोम संविधि को अपनाने के उपलक्ष्य में। इस संधि की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की स्थापना की गई।
जुलाई 18	अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस	शांति और स्वतंत्रता की संस्कृति में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के योगदान को मान्यता देने हेतु।
जुलाई 26	कारगिल विजय दिवस	कारगिल के ऊपर पहाड़ों में हुए संघर्ष में पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने हेतु
जुलाई 28	विश्व हेपेटाइटिस दिवस	आइये इसे समझें
जुलाई 29	अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस	इस दिन की स्थापना 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में जंगली बाघों की संख्या में गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी।

माह के महत्वपूर्ण घटनाक्रम

G7 समिट 2026: G7 क्या है और एवियन-लेस-बेन्स समिट के एजेंडा में क्या था?



परिचय

G7 समिट दुनिया की सबसे असरदार एडवांस्ड इकॉनमी की मीटिंग में से एक है, जहाँ लीडर सिक्योरिटी और ट्रेड से लेकर क्लाइमेट चेंज और नई टेक्नोलॉजी तक, दुनिया की बड़ी चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। 2026 में, यह समिट फ्रांस के एवियन-लेस-बेन्स में हुई थी, जिसमें दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रियलाइज़्ड डेमोक्रेसी के लीडर और बुलाए गए पार्टनर देश एक साथ आए थे।

G7 क्या है?

ग्रुप ऑफ़ सेवन (G7) सात एडवांस्ड इकॉनमी का एक इनफॉर्मल फोरम है जो ग्लोबल इकॉनमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी मामलों पर कोऑर्डिनेट करता है। इसके सदस्य हैं:

- यूनाइटेड स्टेट्स
- यूनाइटेड किंगडम
- कनाडा
- फ्रांस
- जर्मनी
- इटली
- जापान
- यूरोपियन यूनियन (EU) भी G7 मीटिंग में हिस्सा लेता है।

यह ग्रुप 1970 के दशक में ग्लोबल इकॉनमिक चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया था। समय के साथ, इसका एजेंडा इंटरनेशनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, हेल्थ, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिकल मुद्दों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया। कई इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन के उलट, G7 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर या सेक्रेटरेट नहीं है। प्रेसीडेंसी हर साल

मैंबर देशों के बीच रोटेट होती है, जिसमें होस्ट देश समिट का एजेंडा तय करता है।

2026 एवियन-लेस-बेन्स समिट

52वां G7 समिट फ्रांस ने 15-17 जून 2026 तक झील के किनारे बसे शहर एवियन-लेस-बेन्स में होस्ट किया था, जो फ्रेंच-स्विस् बॉर्डर के पास है। यह जगह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने पहले 2003 में G8 समिट होस्ट किया था। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों ने समिट की अध्यक्षता की और कई पार्टनर देशों और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन को मुख्य ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा में भाग लेने के लिए इन्वाइट किया।

समिट के एजेंडा में मुख्य मुद्दे

1. रूस-यूक्रेन युद्ध

चल रहा रूस-यूक्रेन संघर्ष समिट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक रहा। G7 नेताओं ने इन बातों पर चर्चा की:

- यूक्रेन के लिए लगातार मिलिट्री, फाइनेंशियल और मानवीय मदद।
- यूक्रेन की लंबे समय की सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिशें।
- प्रतिबंधों के ज़रिए रूस पर दबाव बनाए रखने के उपाय।
- स्थायी शांति पाने की संभावनाएं।
- यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने समिट चर्चाओं में हिस्सा लिया और लगातार अंतरराष्ट्रीय समर्थन मांगा।

2. मिडिल ईस्ट तनाव और ईरान

पश्चिम एशिया में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर काफी ध्यान दिया गया।

नेताओं ने इन बातों पर चर्चा की:

- ईरान से जुड़े बढ़ते तनाव।
- क्षेत्रीय स्थिरता और संघर्ष की रोकथाम।
- महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा।
- बिना किसी रुकावट के वैश्विक ऊर्जा सप्लाई सुनिश्चित करना।

यह मुद्दा खास तौर पर महत्वपूर्ण था क्योंकि इस क्षेत्र में अस्थिरता वैश्विक तेल बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर डाल सकती है।

3. ग्लोबल अर्थव्यवस्था और व्यापार

कई देशों में धीमी आर्थिक वृद्धि और लगातार महंगाई के दबाव के बीच, नेताओं ने आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।

मुख्य चर्चाओं में शामिल थे:

- स्थायी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना।
- ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित करना।
- व्यापार में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करना। इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना।
- समिट में ग्लोबल मार्केट पर ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सरकारी सब्सिडी के असर की भी जांच की गई।

4. ज़रूरी मिनरल्स और सप्लाई चेन सिक्वोरिटी

लिथियम, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे ज़रूरी मिनरल्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी हैं।

G7 ने इन तरीकों पर विचार किया:

- ज़रूरी मिनरल्स के सोर्स को अलग-अलग तरह का बनाना।
- कुछ सप्लायर्स पर निर्भरता कम करना।
- स्ट्रेटेजिक मिनरल पार्टनरशिप को मजबूत करना।
- क्लीन-एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा मजबूत सप्लाई चेन बनाना।

5. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का एक मुख्य विषय बनकर उभरा।

लीडर्स ने इन पर चर्चा की:

- AI का ज़िम्मेदारी से डेवलपमेंट और इस्तेमाल।
- AI गवर्नेंस और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क।
- गलत जानकारी और साइबर सिक्वोरिटी से जुड़े रिस्क।

- ऑनलाइन बच्चों और कमज़ोर ग्रुप्स की सुरक्षा।
 - एथिकल सेफ़र्गार्ड्स के साथ इनोवेशन को बैलेंस करना।
- चर्चाओं में AI टेक्नोलॉजी के तेज़ी से बढ़ने और उनके सामाजिक असर को लेकर बढ़ती चिंताएँ दिखीं।

6. डेवलपिंग देशों में कर्ज़ की चुनौतियाँ

कई डेवलपिंग देश बढ़ते कर्ज़ के बोझ और फाइनेंसिंग की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। G7 ने इन बातों पर विचार किया:

- कर्ज़ रीस्ट्रक्चरिंग के तरीके।
- कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए फ़ाइनेंशियल मदद।
- इंटरनेशनल फ़ाइनेंशियल संस्थानों में सुधार।
- सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंफ़्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए मदद।

इसका मकसद कम और मिडिल इनकम वाले देशों में कर्ज़ के संकट से आर्थिक विकास को कमज़ोर होने से रोकना था।

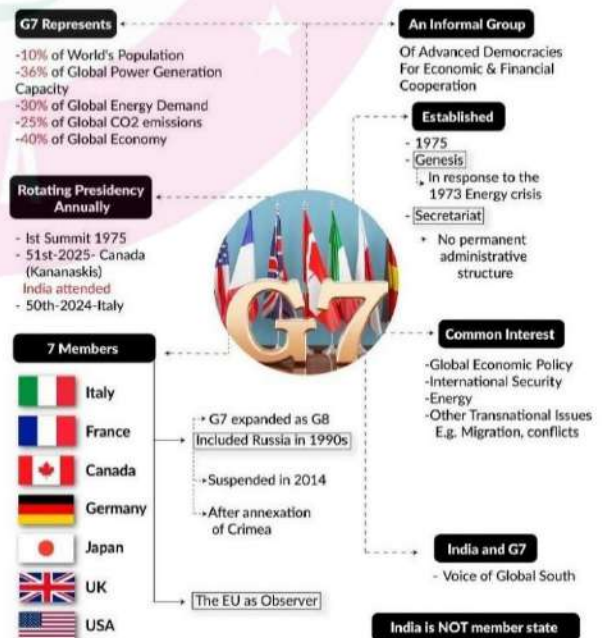
7. ग्लोबल हेल्थ कोऑपरेशन

हाल की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से सीखे गए सबक के बाद हेल्थ सिक्वोरिटी एक ज़रूरी मुद्दा बना रहा।

नेताओं ने चर्चा की:

- भविष्य की महामारियों के लिए तैयारी को मजबूत करना।
 - इंटरनेशनल बीमारी की निगरानी में सुधार करना।
 - वैक्सीन बनाने में सहयोग बढ़ाना।
 - इबोला जैसी बीमारियों के फैलने पर तालमेल बिठाना।
- कैंसर रिसर्च और इलाज में ग्लोबल कोशिशों को आगे बढ़ाना।

The Group of G7 Countries



पार्टनर देशों की भागीदारी

हालांकि G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को पार्टनर देश के तौर पर बुलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में हिस्सा लिया और इन बातों पर चर्चा में हिस्सा लिया:

- ग्लोबल आर्थिक सहयोग।
- नई टेक्नोलॉजी और AI।
- एनर्जी सिक्योरिटी।
- डेवलपमेंट पार्टनरशिप।

ग्लोबल गवर्नेंस संस्थानों में सुधार। भारत का बार-बार हिस्सा लेना ग्लोबल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल मामलों में उसकी बढ़ती अहमियत को दिखाता है।



G7 समिट क्यों ज़रूरी है?

G7 देश मिलकर दुनिया के इकोनॉमिक आउटपुट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और फाइनेंशियल असर का एक बड़ा हिस्सा हैं। हालांकि यह ग्रुप कानूनी तौर पर ज़रूरी ग्लोबल फैसले

नहीं ले सकता, लेकिन इसकी चर्चाएं अक्सर इंटरनेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और डिप्लोमैटिक पहल को आकार देती हैं।

जैसे-जैसे ग्लोबल चुनौतियां आपस में जुड़ती जा रही हैं, G7 समिट युद्ध, इकोनॉमिक अनिश्चितता, टेक्नोलॉजिकल बदलाव, क्लाइमेट चुनौतियों और ग्लोबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर जवाबों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है।

निष्कर्ष

2026 के एवियन-लेस-बेन्स समिट में आज दुनिया के सामने मौजूद कुछ सबसे ज़रूरी मुद्दों पर फोकस किया गया—रूस-यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट तनाव से लेकर AI गवर्नेंस, ज़रूरी मिनरल, इकोनॉमिक लचीलापन और ग्लोबल हेल्थ तक। समिट ने बड़ी इंटरनेशनल चुनौतियों से निपटने और बड़ी इकोनॉमी और पार्टनर देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक फोरम के तौर पर G7 की लगातार भूमिका पर ज़ोर दिया।



खार्ग आइलैंड के बारे में: ईरान के ऑयल हब पर कब्ज़ा करना U.S. सैनिकों के लिए रिस्की क्यों हो सकता है

परिचय

खार्ग आइलैंड, फ़ारस की खाड़ी में एक छोटा सा आइलैंड है, जो हाल ही में ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल के बीच चल रहे झगड़े की चर्चाओं का एक बड़ा केंद्र बन गया है। हालाँकि यह मैप पर छोटा लग सकता है, लेकिन यह आइलैंड ईरान की इकॉनमी में एक अहम भूमिका निभाता है क्योंकि यह देश के मुख्य ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल के तौर पर काम करता है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही यूनाइटेड स्टेट्स इस आइलैंड पर कब्ज़ा कर सकता है, लेकिन इसे अपने पास रखना कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा और इससे अमेरिकी सैनिकों को बड़ा खतरा हो सकता है।



खार्ग आइलैंड कहाँ है?

खार्ग आइलैंड उत्तरी फ़ारस की खाड़ी में है, जो ईरान के तट से लगभग 25-26 किलोमीटर (16 मील) दूर और होर्मुज़ स्ट्रेट से लगभग 480 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में है। आइलैंड की गहरे पानी की फैसिलिटीज़ बड़े ऑयल टैंकरों को क्रूड ऑयल लोड करने देती हैं, जो ईरान के उथले समुद्र तट पर कई जगहों पर मुश्किल है।

खार्ग आइलैंड इतना ज़रूरी क्यों है?

खार्ग आइलैंड को अक्सर ईरान की तेल इंडस्ट्री की लाइफलाइन कहा जाता है।

खास बातें:

- ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट इसी आइलैंड से होकर जाता है।
- यह लगभग सात दशकों से ईरान का मुख्य तेल एक्सपोर्ट हब रहा है।
- खार्ग आइलैंड से एक्सपोर्ट होने वाला ज़्यादातर तेल एशियाई बाज़ारों, खासकर चीन में भेजा जाता है।
- आइलैंड की फैसिलिटी दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल टैंकरों को हैंडल कर सकती हैं।

क्योंकि तेल एक्सपोर्ट सरकारी रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है, इसलिए खार्ग आइलैंड में कोई भी रुकावट सीधे ईरान की इकॉनमी पर असर डालेगी।

आइलैंड एक स्ट्रेटेजिक टारगेट क्यों बन गया है?

कुछ U.S. अधिकारियों ने खार्ग आइलैंड को ईरान पर दबाव बढ़ाने के तरीके के तौर पर देखा है।

अगर आइलैंड पर कब्ज़ा कर लिया गया या इसका तेल इंफ्रास्ट्रक्चर बंद कर दिया गया:

- ईरान का तेल एक्सपोर्ट बहुत कम हो सकता है।
- तेहरान रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स खो देगा।
- ईरानी सरकार पर आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा।

ईरान की मिलिट्री और सरकारी ऑपरेशन को फाइनेंस करने की क्षमता कमज़ोर हो सकती है। लेकिन, मिलिट्री एनालिस्ट का कहना है कि यह ऑपरेशन हल करने के बजाय और ज़्यादा समस्याएँ खड़ी कर सकता है।

खार्ग आइलैंड पर कब्ज़ा करना रिस्की क्यों होगा?

1. U.S. सैनिक आसान टारगेट बन जाएंगे

मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि U.S. सेना शायद आइलैंड पर काफ़ी जल्दी कब्ज़ा कर सकती है। चुनौती उसके बाद उसे बचाना होगी।

आइलैंड पर तैनात अमेरिकी सैनिक इन चीज़ों की रेंज में होंगे:

- ईरानी मिसाइलें

- हथियारबंद ड्रोन
 - रॉकेट हमले
 - पास की ईरानी सेना से नेवी के हमले
- क्योंकि यह आइलैंड ईरानी मेनलैंड के पास है, इसलिए तेहरान लगातार किसी भी कब्ज़ा करने वाली सेना को टारगेट कर सकता है।

2. ईरान के पास मज़बूत डिफेंस है

खार्ग आइलैंड पर ईरान की सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की कड़ी सुरक्षा है।

एनालिस्ट चेतावनी देते हैं कि ईरान:

- आइलैंड के चारों ओर नेवी की माइंस लगा सकता है।
- ड्रोन के झुंड लॉन्च कर सकता है।
- मेनलैंड से मिसाइल हमले कर सकता है।

U.S. सेना को सपोर्ट करने वाले सप्लाइ शिप पर हमला कर सकता है। इससे कोई भी लंबे समय तक कब्ज़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।

3. आइलैंड पर कब्ज़ा करने के लिए बड़े मिलिट्री रिसोर्स की ज़रूरत है

पहले के U.S. मिलिट्री कमांडरों का अंदाज़ा है कि आइलैंड को सुरक्षित करने के लिए सैकड़ों, और शायद लगभग 800-1,000 सैनिकों की ज़रूरत होगी।

इसके अलावा, U.S. को इन चीज़ों की ज़रूरत होगी:

- एयर डिफेंस सिस्टम
- नेवल प्रोटेक्शन
- लगातार सप्लाइ मिशन
- इंटेलिजेंस और सर्विलांस सपोर्ट

इससे मिलिट्री रिसोर्स लंबे समय तक बंधे रह सकते हैं।

ग्लोबल ऑयल मार्केट पर असर

खार्ग आइलैंड के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे ईरान से कहीं ज़्यादा हो सकते हैं।

संभावित असर ये हैं:

- ग्लोबल ऑयल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी।
 - एनर्जी सप्लाइ में रुकावट।
 - पर्शियन गल्फ में ज़्यादा अस्थिरता।
 - दुनिया भर में ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल की बढ़ती कीमतें।
- एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि आइलैंड को बड़ा नुकसान होने से ग्लोबल एनर्जी मार्केट को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि ईरान का बहुत सारा ऑयल इसी एक जगह से होकर गुज़रता है।

बड़े इलाके में लड़ाई का खतरा

खार्ग आइलैंड पर हमला होने से ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है।

ईरान के संभावित जवाब ये हैं:

- इलाके में U.S. मिलिट्री एसेट्स पर हमले।
- गल्फ देशों में ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमले।
- शिपिंग रूट्स में रुकावट।
- मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ना।

ऐसी कार्रवाइयों से और देश लड़ाई में शामिल हो सकते हैं और इलाका और अस्थिर हो सकता है।

खार्ग आइलैंड को ज़्यादातर क्यों बख्शा गया है?

इसकी अहमियत के बावजूद, बड़ी ताकतें आमतौर पर आइलैंड की ऑयल फैसिलिटीज़ को सीधे टारगेट करने से बचती रही हैं। मुख्य कारण हैं:

- ग्लोबल एनर्जी संकट का डर।
- तेल की बढ़ती कीमतों का खतरा।
- बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय युद्ध की संभावना।
- लंबे समय तक आर्थिक अस्थिरता की चिंता।

जब द्वीप के पास मिलिट्री हमले हुए, तब भी रिपोर्ट बताती हैं कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में रुकावट से बचने के लिए तेल-एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक वैसे ही छोड़ दिया गया था।

निष्कर्ष

खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी में एक छोटे से द्वीप से कहीं ज़्यादा है—यह ईरान के तेल-एक्सपोर्ट सिस्टम की रीढ़ है और देश के लिए रेवेन्यू का एक ज़रूरी सोर्स है। हालांकि द्वीप पर कब्ज़ा करने से ईरान आर्थिक रूप से काफी कमज़ोर हो सकता है, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि इस पर कब्ज़ा करने से अमेरिकी सैनिकों को लगातार मिसाइल, ड्रोन और नेवी के खतरों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, खार्ग द्वीप पर किसी भी हमले से बड़े क्षेत्रीय संघर्ष और ग्लोबल तेल मार्केट में बड़ी रुकावटें पैदा होने का खतरा है। इन कारणों से, कई एनालिस्ट इस द्वीप को एक बहुत कीमती लेकिन बहुत खतरनाक मिलिट्री टारगेट मानते हैं।

PoK प्रोटेस्ट की जानकारी: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग सड़कों पर क्यों हैं?

परिचय

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट और हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसके कारण कई मौतें, चोटें, गिरफ्तारियां और बड़े पैमाने पर अशांति हुई है। हालांकि इसका तुरंत कारण PoK असेंबली में रिज़र्व सीटों को लेकर विवाद था, लेकिन ये प्रोटेस्ट आर्थिक तंगी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन से जुड़ी कहीं ज्यादा गहरी चिंताओं को दिखाते हैं।

हाल के प्रोटेस्ट किस वजह से शुरू हुए?

अशांति का तुरंत कारण PoK लेजिस्लेटिव असेंबली में जम्मू और कश्मीर के उन माइग्रेंट्स के लिए रिज़र्व 12 सीटों का मुद्दा है जो पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। हाल ही में एक कोर्ट के फैसले ने इन रिज़र्व सीटों को बरकरार रखा, जिससे लोगों का गुस्सा फिर से भड़क गया और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। कई स्थानीय निवासियों का तर्क है कि ये प्रतिनिधि PoK के बाहर से चुने जाते हैं और सही मायने में इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उनका मानना है कि यह व्यवस्था इस्लामाबाद को PoK के राजनीतिक सिस्टम पर बहुत ज्यादा असर देती है।

असेंबली सीट विवाद को समझना

PoK असेंबली में 53 सीटें हैं।

इनमें शामिल हैं:

- 33 सीधे चुनी हुई सीटें।
- 12 सीटें पाकिस्तान में कहीं और रहने वाले जम्मू और कश्मीर के माइग्रेंट्स के लिए रिज़र्व हैं।
- 5 सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व हैं।
- 1 सीट धार्मिक विद्वानों (उलेमा) के लिए है।
- 1 सीट विदेश में रहने वाले कश्मीरियों के लिए है।
- 1 सीट टेक्नोक्रेट्स के लिए है।

आलोचकों का कहना है कि करीब 20 सीटें अलग-अलग रिज़र्वेशन से भरी जाती हैं, जिससे लोकल वोटर्स का असर कम हो जाता है। 12 माइग्रेंट सीटें खास तौर पर इसलिए विवादित हो गई हैं क्योंकि लोकल लोगों को लगता है कि जो लोग PoK में नहीं रहते हैं, उनकी पॉलिटिक्स तय करने में इतनी अहम भूमिका नहीं होनी चाहिए।

आर्थिक शिकायतें: गुस्से की असली वजह

हालांकि सीट रिज़र्वेशन के मुद्दे ने हाल के विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, लेकिन लोगों में नाराज़गी सालों से बढ़ रही है।

1. ज्यादा बिजली के बिल

मंगला डैम जैसे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए इस इलाके में काफ़ी हाइड्रोपावर पैदा होने के बावजूद लोग बिजली की बढ़ती कीमतों की शिकायत करते हैं। कई लोकल लोगों का कहना है कि उन्हें सस्ती बिजली मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी ज़मीन और रिसोर्स बिजली बनाने में मदद करते हैं।

2. महंगाई और रहने का खर्च

लोग इन चीज़ों से जूझ रहे हैं:

- खाने की चीज़ों की बढ़ती कीमतें।
- सब्सिडी वाले गेहूँ के आटे की कमी।
- बढ़ते टैक्स।
- बेरोज़गारी का बढ़ना।

इन आर्थिक मुश्किलों ने अधिकारियों के प्रति निराशा को और बढ़ा दिया है।

3. रिसोर्स के इस्तेमाल की चिंताएँ

कई प्रोटेस्टर मानते हैं कि PoK के प्राकृतिक रिसोर्स का इस्तेमाल लोकल कम्युनिटी को सही फ़ायदा दिए बिना किया जा रहा है। इस सोच ने लोकल रिसोर्स और रेवेन्यू पर ज्यादा कंट्रोल की माँग को हवा दी है।

प्रोटेस्ट को कौन लीड कर रहा है?

इस मूवमेंट को मुख्य रूप से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) लीड कर रही है, जो ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स का एक ग्रुप है। इस ऑर्गनाइज़ेशन ने शुरू में बिजली के टैरिफ और महंगाई जैसे आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दिया, लेकिन बाद में अपनी माँगों को बढ़ाकर पॉलिटिकल रिफॉर्म और ज्यादा लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी शामिल कर लिया।

सरकार ने कैसे जवाब दिया है?

अधिकारियों ने प्रोटेस्ट पर कड़ा रवैया अपनाया है। खबरों के मुताबिक, इन उपायों में शामिल हैं:

- JAAC पर बैन लगाना।
- प्रदर्शन करने वाले नेताओं को गिरफ्तार करना।

- एक्टिविस्ट के खिलाफ देशद्रोह और आतंकवाद जैसे चार्ज लगाना।
- सुरक्षा बलों को तैनात करना।
- कुछ इलाकों में इंटरनेट पर रोक और कम्युनिकेशन में रुकावट डालना।
- प्रदर्शनों पर सख्ती।

प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पों में कई मौतें और चोटें आई हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है।

इस मामले में इतिहास क्यों ज़रूरी है?

विरोध की जड़ें मौजूदा आर्थिक समस्याओं से कहीं ज़्यादा हैं। कई लोगों को लगता है कि PoK को पहले से ही सीमित राजनीतिक आज़ादी मिली हुई है और यह पाकिस्तान की फ़ेडरल अथॉरिटीज़ से काफ़ी प्रभावित है। आलोचकों का कहना है कि शासन, विकास और प्रतिनिधित्व से जुड़े ज़रूरी फ़ैसले अक्सर स्थानीय संस्थाओं के बजाय इस्लामाबाद लेता है। इसलिए, कई जानकार मौजूदा आंदोलन को न सिर्फ़ आर्थिक राहत बल्कि ज़्यादा राजनीतिक भागीदारी और जवाबदेही की मांग के तौर पर भी देख रहे हैं।

गिलगित-बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है?

इस अशांति ने पड़ोसी गिलगित-बाल्टिस्तान की ओर भी ध्यान खींचा है, जो पाकिस्तान के शासन के तहत एक और इलाका है जो पहले जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा था।

PoK की तरह, गिलगित-बाल्टिस्तान में भी इन चीज़ों को लेकर चिंताएँ देखी गई हैं:

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
- आर्थिक विकास।
- संसाधनों का मैनेजमेंट।
- फ़ेडरल सरकार का कंट्रोल।

इस इलाके में हाल के चुनावों में भी दखलंदाज़ी और आबादी के कुछ हिस्सों में नाराज़गी के आरोप लगे हैं।

अंतरराष्ट्रीय ध्यान

विरोध ने इस इलाके के बाहर भी ध्यान खींचा है। कश्मीरी डायस्पोरा के सदस्यों ने, खासकर यूनाइटेड किंगडम में, हालात पर चिंता जताई है और बातचीत, ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा और संकट के शांतिपूर्ण समाधान की मांग की है।

इस अशांति ने सोशल मीडिया और इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर के बीच भी काफी चर्चा पैदा की है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया है।

निष्कर्ष

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूदा विरोध प्रदर्शन सिर्फ़ 12 रिज़र्व असेंबली सीटों के लिए नहीं हैं। ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक तंगी, रहने का बढ़ता खर्च, बिजली के टैरिफ, रिसोर्स कंट्रोल और सीमित लोकल ऑटोनॉमी की सोच से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का नतीजा हैं। हालांकि रिज़र्वेशन के मुद्दे ने तुरंत ट्रिगर का काम किया, लेकिन यह आंदोलन उन बड़ी निराशाओं को दिखाता है जो सालों से बन रही हैं। अधिकारी इन चिंताओं पर कैसे जवाब देते हैं, यह इस इलाके की भविष्य की स्थिरता तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

POK: A HISTORY OF CONFLICT, A CONSTITUTIONAL LIMBO
26 KILLED IN PAKISTANI CRACKDOWN AS PROTESTS EXPOSE ISLAMABAD'S HYPOCRISY AND A DOOMED EXPERIMENT

26 KILLED
INCLUDING WOMEN AND CHILDREN IN PAKISTAN'S CRACKDOWN IN POK

HISTORICAL TIMELINE: 1947 TO 1949

- AUGUST 1947:** In Peshawar, Kashmir was a princely state ruled by Maharaja Hari Singh (Dogra Hindu ruler of a Muslim-majority state). He chose to remain independent and did not join India or Pakistan.
- OCTOBER 1947:** Tribal militias from Pakistan's North-West Frontier, supported by Pakistan, invaded Kashmir.
- OCT 26, 1947:** Lord Mountbatten, Governor General of India, accepted the Instrument of Accession on behalf of India.
- 1947-JAN 5, 1949:** Operations on the first Indo-Pakistan War continued till January 5, 1949.
- AFTER CEASEFIRE:** By the time the evening sides stopped attacking each other, one-third of Kashmir was already under the control of Pakistan.
- On January 5, 1949,** a UN-sponsored ceasefire took place.

THE DIVIDED STATE (POST 1949)

- PAKISTAN OCCUPIED KASHMIR (POK)
- INDIA OCCUPIED KASHMIR (J&K)
- INDIA OCCUPIED JAMMU & KASHMIR (INDIA)

PAKISTAN'S CONTROL OVER POK: THE KARACHI AGREEMENT (1949)

During the war, Pakistan set up a provisional government called the "Azad Kashmir Government" in October 1947. It signed the Karachi Agreement in January 1949. According to the terms and conditions of the agreement:

- Pakistan took control of the defence of POK.
- Islamabad handled the foreign affairs of the region.
- Pakistan administered the northern territories, later called Gilgit-Baltistan, besides the POK.

ADMINISTRATIVE EVOLUTION

Earlier, the entire region of POK was controlled by Pakistan.

Later, POK and Gilgit-Baltistan were separated.

While POK has a separate legislature and government, Gilgit-Baltistan has a different government structure.

However, neither of them has been incorporated into the state of Pakistan.

AFTER 1971: SEEKING CONTROL

After Pakistan was defeated by India, leading to the creation of Bangladesh in 1971, Islamabad turned its attention to POK.

AKJ INTERIM CONSTITUTION ACT, 1974

According to the Act, POK was given:

- A Legislative Assembly
- A President
- A Prime Minister
- A Supreme Court
- Administrative Institutions

THE KASHMIR COUNCIL: A LEASH ON AUTONOMY

To keep control, Islamabad set up the Kashmir Council, which retained authority over:

- Legislation
- Finances
- Administrative matters

REFORMS IN 2019

Under pressure from demands for autonomy, Islamabad introduced certain reforms in 2019.

THE PRESENT STATUS OF POK (AKJ)

Despite so-called autonomy, POK (AKJ) has the following status:

- POK, or AKJ, as Pakistan calls it, is not a province of Pakistan.
- It has a distinct constitutional identity.
- Its final status should be determined through a future settlement of the Kashmir dispute.

HOW POK IS GOVERNED TODAY

POK currently has:

- A Prime Minister
- A President
- Legislative Assembly
- Local courts
- Administrative structures
- Foreign policy
- Security matters
- Strategic decision-making

BUT ISLAMABAD STILL CONTROLS:

POK remains a territory born out of war, sustained by control, but disputed by history, law and the will of its people. THE CRACKDOWN THAT KILLED 26 PEOPLE ONLY EXPOSES THE DEEPER TRUTH: A SYSTEM WITHOUT JUSTICE CAN NEVER BRING PEACE.

Monthly
CURRENT AFFAIRS
BY ENGINEERS ACADEMY



+91 8094441777



+91 8094441777



NIMBUS Learning



Engineers Academy



engineers_academy_india



www.engineersacademy.org



Engineers Academy Officials

